रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270749
CG-DL-E-09032026-270749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947
No. 47] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

(अंतिम जांच परिणाम)

मामला सं.-सीवीडी (एसएसआर)–01/2025

विषय : मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टेक्स्चर्ड टेम्पर्ड ग्लास" के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 7/10/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त सामानों की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सब्सिडीरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) (जिसे यहां आगे "सीवीडी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मेसर्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) और विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (वीजीपीएल) (जिसे इसके बाद "घरेलू उद्योग" या "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (अनुदान प्राप्त सामानों पर

सब्सिडीयुक्त सामानों पर सब्सिडीरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' कहा गया है) के अनुसार मलेशिया (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास (जिसे इसके बाद संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच की निर्यायक समीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी " कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में मूल सब्सिडीरोधी जांच अधिसूचना संख्या 06/13/2019- डीजीएडी दिनांक 12.09.2019 द्वारा शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि (i) संबद्ध देश की सरकार संबद्ध सामानों के उत्पादकों को विभिन्न सब्सिडी प्रदान कर रही थी; (ii) सब्सिडी सीवीडी नियमावली के तहत प्रतिकार योग्य प्रकृति की थी; और (iii) सब्सिडी वाले संबद्ध सामानों के आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। अत:, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 06/ 13/2019 दिनांक 11.12.2020 के माध्यम से संबद्ध सामानों के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। सकारात्मक सिफारिश के आधार पर, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 3/ 2021 - सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 9.3.2021 के माध्यम से निम्नलिखित निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी उपाय लगाए गए और ये उपाय 8 जून, 2026 तक लगाए गए थे।

क्र.सं.	उत्पादक	सीआईएफ मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
1	मेसर्स शिनयी सोलर एसडीएन. बीएचडी मलेशिया	9.71%
2	अन्य सभी	10.14%

3. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के लिए सब्सिडी जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए सब्सिडीरोधी शुल्क की समीक्षा करने तथा उसे जारी रखने और उसे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

4. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(6) और सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के नियम 24(3) के संदर्भ में लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, ऐसे शुल्क लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होंगे और प्राधिकारी को यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी वाले आयात के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

5. घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक आवेदन-पत्र दायर किया, जिसमें मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध किया गया था। आवेदकों ने इस आधार पर संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जारी रखने की मांग की है कि शुल्कों की समाप्ति से सब्सिडी वाले संबद्ध आयातों के जारी रहने की संभावना है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने शुल्क बढ़ाए जाने की मांग की।

6. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से दायर आवेदन-पत्र की जांच की और सब्सिडी जारी रहने और सब्सिडीकरण के जारी रहने/बारबार होने तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए। परिणामस्वरूप, नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 07/ 10/ 2025 - डीजीटीआर, दिनांक 24.6.2025 के माध्यम से संबद्ध जांच शुरू की, ताकि संबद्ध सामानों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना जारी रहने और बढ़ाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके, और यह जांच की जा सके कि क्या उक्त शुल्कों की समाप्ति से सब्सिडी जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। डीजीटीआर की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 0710/2025-सीमा शुल्क (सीवीडी) पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क बढ़ाया गया था, और शुल्क 8 जून 2026 तक प्रभावी है।

7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध सामानों से संबंधित उपरोक्त मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

8. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

8.1 जांच की शुरुआत

क. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 जून, 2025 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने ज्ञात विचार दें।

8.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति, अनुरोध किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

8.3 संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देश में निर्यातकों को एक निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

ख. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ग. उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर, उत्तर दिया है:

(i) शिनयी सोलर (एम) एसडीएन. बीएचडी,

(ii) एसबीएच किर्बिंग सोलर न्यू मैटेरियल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी।

8.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(5) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।

(i) मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड

(ii) सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड

(iii) प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड

(iv) रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(v) गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड

(vi) वार्री एनर्जीज लिमिटेड

(vii) अल्पेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(viii) विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड

(ix) एमवीवो फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड

(x) नवितस ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

(xi) सोवा पावर लिमिटेड

ख. निम्नलिखित आयातकों /प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। प्राधिकारी ने भी तदनुसार उनके अनुरोधों पर विचार किया है।

i. नवीतास ग्रीन साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड

ii. सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड,

iii. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

8.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

क. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जांच में वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच की अवधि शामिल है।

8.6 आगे की प्रक्रियाएँ

क. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

ख. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ग सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम सब्सिडीरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

घ. आवेदक घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना का मौके पर सत्यापन के माध्यम से भौतिक निरीक्षण, जहां तक आवश्यक समझा गया, प्राधिकारी द्वारा किया गया था। केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर, जहां भी लागू हो, आवश्यक सुधार के साथ, वर्तमान जांच परिणामों के उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है।

ड. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्य के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

च. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

छ. नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 28.10.2025 और 04.12.2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से उइन विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था। लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए था, और उन्हें प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

ज. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने पहुंच से इनकार किया है, या अन्यथा वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

झ. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पर टिप्पणियां प्रदान करने के लिए समय प्रदान किया। हालाँकि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई ठोस अनुरोध नहीं किए हैं और इसलिए, उत्पाद में कोई बदलाव नहीं किया गया।

ञ. प्राधिकारी ने साक्ष्य से समर्थित और वर्तमान जांच से संगत मानी गई सीमा तक सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी की गई सूचना पर विचार किया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यकारी दस्तावेज़ों की जांच की है, जो वर्तमान जांच परिणामों के लिए निष्कर्षों का आधार बनते हैं।

ट. निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण 18 फरवरी, 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था, जिसमें प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 25 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर विचार किया है।

ठ. इस अधिसूचना में '***' गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ड. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर= 84.58 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

9. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत अधिसूचना के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

3. "वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "कम से कम 90.5% ट्रांसमिशन के साथ टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई 4.2 मिमी से अधिक नहीं है (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे लेपित हो या बिना लेपित हो" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है)। संबद्ध सामान में आवश्यक संचरण का न्यूनतम स्तर लोहे की मात्रा को कम रखकर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200 पीपीएम से कम। जब एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल से लेपित किया जाता है तो ट्रांसमिशन स्तर लगभग 2%-3% बढ़ जाता है। कांच चाहे लेपित हो या बिना लेपित हो, उसे टेम्परिंग भट्ठी में टेम्पर किया जाता है/सख्त किया जाता है, क्योंकि यह सौर अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। बाजार स्थल में यह उत्पाद विभिन्न नामों से जाना जांता है, जैसे सोलर ग्लास, लो आयरन सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टे ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न सोलर ग्लास आदि।

4. संबद्ध सामान का उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक पैनल और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में किया जाता है। आयरन की मात्रा को कम रखकर संचरण का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200 पीपीएम से कम। जब एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल से लेपित किया जाता है तो ट्रांसमिशन स्तर लगभग 2%-3% बढ़ जाता है। कांच चाहे लेपित हो या बिना लेपित हो, उसे टेम्परिंग भट्ठी में टेम्पर या सख्त किया जाता है क्योंकि यह सौर अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। वर्तमान रुझान के अनुसार इन अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाने वाला ग्लास 2 एमएम से 4 एमएम मोटाई का है। संबद्ध सामानों का आकार उद्देश्य और मॉड्यूल आकार पर निर्भर करता है। कांच को टेम्परिंग से पहले या कोटिंग के बाद ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकारों में काटा जाता है। चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए उत्पाद वही रहता है जिसे प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में परिभाषित किया था।

5. संबद्ध सामानों को अध्याय शीर्ष 70071900 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, , घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि विभिन्न अन्य प्रशुल्क शीर्षों जैसे 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 आदि के तहत भी संबद्ध सामानों का आयात किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल संकेतात्मक हैं, और उत्पाद विवरण सभी परिस्थितियों में बना रहेगा।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ग. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, '4.2 मिमी से अधिक नहीं (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) मोटाई के न्यूनतम 90.5% संचरण के साथ बनावट वाला टेम्पर ग्लास है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे लेपित हो या बिना लेपित' ।

ख. बाजार की भाषा में उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न वाले सोलर ग्लास, हीट स्ट्रेंथ ग्लास आदि। टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक पैनल और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में किया जाता है। आयरन की मात्रा को कम रखकर संचरण का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200 पीपीएम से कम। जब एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल से लेपित किया जाता है तो ट्रांसमिशन स्तर लगभग 2%-3% बढ़ जाता है।

ग. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद को बाजार की भाषा में हीट स्ट्रेंथन्ड ग्लास के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने चीन और वियतनाम के खिलाफ विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हाल ही में संपन्न पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी जांच में हीट स्ट्रेंथन्ड ग्लास को वाणिज्यिक नामों में से एक के रूप में माना है। इसके अतिरिक्त, उस निर्धारण के विरुद्ध कोई चुनौती भी नहीं दी गई है। अत:, अंतिम जांच परिणामों में हीट स्ट्रेंथन्ड ग्लास का उल्लेख न करने का कोई कानूनी या अन्यथा कारण नहीं है।

घ. संबद्ध उत्पाद मुख्य रूप से 8-अंकीय स्तर पर प्रशुल्क वर्गीकरण के तहत आयात किए जाते हैं, अर्थात 70071900, भले ही उन्हें सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के विभिन्न उपशीर्षों के तहत वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है, जैसा कि आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों का आयात उप-शीर्ष 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011 में भी किया जा रहा है, जैसा कि आयात आंकड़ों से सिद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से, यह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण विरोध की परिस्थितियों में है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से आयातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और बाजार और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे गुणों के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध सामान, जो भारत में आ रहे हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। सब्सिडी वाले आयात और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, प्रकार्यों या अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के तहत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. विचाराधीन से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुराधों की जांच की गई है और नीचे हल किया गया है:

13. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, जांच की शुरुआत के स्तर पर, '4.2 मिमी से अनधिक (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) मोटाई के न्यूनतम 90.5% संचरण के साथ टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास के रूप में परिभाषित किया गया था और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे लेपित हो या बिना लेपित हो और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग सौर फोटोवोल्टिक पैनलों और सौर थर्मल अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में किया जाता है। आयरन की मात्रा को कम रखकर संचरण का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200 पीपीएम से कम। जब एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल से लेपित किया जाता है तो ट्रांसमिशन स्तर लगभग 2%-3% बढ़ जाता है।

14. विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे सौर ग्लास, सौर ग्लास लो आयरन, सौर पीवी ग्लास, उच्च ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न्ड सोलर ग्लास आदि। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि हीट स्ट्रेंथन्ड ग्लास बाजार की भाषा में विचाराधीन उत्पाद का केवल एक अन्य नाम है और इसके स्पष्टीकरण के लिए किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विरोध नहीं किया। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर सभी अनुरोधों और सामग्री का विश्लेषण किया, मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है। इसके अतिरिक्त, केवल बाजार की भाषा के आधार पर किसी नाम को स्पष्ट करने से, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संशोधन नहीं होता है। यह भी मानने की आवश्यकता है कि विचाराधीन उत्पाद के तहत वर्गीकृत किए

जाने वाले किसी भी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई भी ग्लास सभी मानदंडों को पूरा करता है (जैसे कि बनावट, सख्त, न्यूनतम 90.5% ट्रांसमिशन, मोटाई 4.2 मिमी से अधिक नहीं, जिसका कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है या बिना कोटिंग के) तो केवल, इसे किसी भी नाम या समझ के बावजूद विचाराधीन उत्पाद के रूप में माना जा सकता है। इसके मद्देनज़र, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि हीट स्ट्रेंथन्ड ग्लास केवल विचाराधीन उत्पाद के नामों में से एक है, जैसा कि मूल जांच के विचाराधीन उत्पाद में परिभाषित किया गया है।

15. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में 'कांच और कांच के बर्तन' श्रेणी के तहत और आगे सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकरण का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान सब्सिडीरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यद्यपि, आवेदक सामूहिक रूप से मात्रात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तथापि, एक आवेदक अर्थात् विशाखा ने हाल ही में उत्पादन शुरू किया था और वह पूर्व जांच का हिस्सा नहीं था और इसलिए, प्राधिकारी को प्रत्येक कंपनी के लिए अलग से आधार सत्यापित करना चाहिए और क्षति मापदंडों का आंकलन करना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह कि वर्तमान आवेदन-पत्र बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) और विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (वीजीपीएल) द्वारा दायर किया गया है। वे भारत में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादक हैं।

ख. आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) और विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (वीजीपीएल) द्वारा दायर किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक उद्योग के अलावा, 3 अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् गोविंद ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्रिवेणी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड और गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, जो संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे हैं।

21. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं हैं। इसके अलावा, आवेदकों के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इस प्रकार, प्राधिकरण का मानना है कि आवेदक सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग हैं, और यह आवेदन-पत्र सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा पूरी करता है।

22. फिर भी, सीमा प्रशुल्क सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर सब्सिडीरोधी शुल्क सब्सिडी-रोधी शुल्क की पहचान, अंकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के तहत, घरेलू उद्योग के आधार की अपेक्षा विशेष रूप से नियम 6(3) के तहत दी गई है, जो मूल जांच की शुरुआत के स्तर पर लागू होती है। इसके अलावा, नियम 24 (5), जो निर्णायक समीक्षा किए जाने को नियंत्रित करता है, नियम 6 की संपूर्णता को छोड़कर नियमावली के आवश्यक अनुप्रयोग का प्रावधान करता है। परिणामस्वरूप, नियम 6 (3) में निहित आधार की अपेक्षा निर्णायक समीक्षा कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती।

ड. <u>गोपनीयता और विविध मुद्दे</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

क. यह कि टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास के आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपाय एक दशक से अधिक समय से लागू हैं। यह लंबे समय तक निर्भरता घरेलू उद्योग को दक्षता में सुधार करने और बाजार में बदलाव के अनुकूल होने के लिए प्रोत्साहन को कमजोर करती है, प्रतिस्पर्धा के बजाय निर्भरता को बढ़ावा देती है। यह भी अनुरोध किया गया है कि यहां तक कि डब्ल्यूटीओ सिद्धांत भी व्यापार उपचार अनिश्चित समय तक बढ़ाए जाने को हतोत्साहित करते हैं। इस तरह के लंबे समय तक चलने वाले उपाय बाजार की गतिशीलता को विकृत करते हैं और नवाचार को कम करते हैं, जबकि आयात पर निर्भर निचले स्तर के उद्योगों पर अनुचित प्रभाव डालते हैं।

ख. यह भी अनुरोध किया गया था कि पिछली जांचों में घरेलू उद्योग यह साबित करने में विफल रहा कि आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई।

ग. निर्यातकों और मलेशिया सरकार द्वारा दायर की गई प्रतिक्रियाएं प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार ठीक से दायर की गई हैं और इसलिए, डीजीटीआर द्वारा प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जा सकता है।

घ. घरेलू उद्योग ने अनुचित गोपनीयता का दावा किया है और उनका अगोपनीय रूपांतर डीजीटीआर द्वारा अपनाई गई परिपाटी का स्पष्ट उल्लंघन है।

ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा विविध अनुरोधों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह कि किसी भी प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोधों का उचित अगोपनीय रूपांतर दायर नहीं किया है और इससे घरेलू उद्योग के अपने अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।

ख. मामलों के इतिहास के मुद्दे के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पिछले मामलों का इतिहास, वह भी, पूरी तरह से विभिन्न स्रोतों के खिलाफ, इस मामले के तथ्य के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक प्रासंगिकता नहीं रखता है। प्राधिकारी को केवल यह देखना होता है कि क्या सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने/पाटन/ सब्सिडीरोधी शुल्क बढ़ाने का मामला, मामले के तथ्यों/परिस्थितियों में किया गया है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान मामले में पिछले उपायों का कोई महत्व नहीं है, यदि निर्यातकों को सब्सिडी मिल रही है, तो घरेलू उद्योग के पास उचित राहत के लिए देश के कानूनों के तहत उपाय मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चूंकि निर्यातकों ने लाभ की प्राप्ति पर विवाद नहीं किया है, इसलिए घरेलू उद्योग को ऐसी परिपाटियों के खिलाफ सुरक्षा मांगने का पूरा अधिकार है।

ग. पिछली जांच में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी को कोई क्षति नहीं मिली है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन और मलेशिया के विरुद्ध पिछली जांच पर केवल एक नज़र डालने पर, हितबद्ध

पक्षकारों के लिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्राधिकारी ने सभी मामलों में क्षति पाई है। तथापि, मलेशिया के विरुद्ध, प्राधिकारी को कोई पाटन नहीं मिला और इसीलिए, उसके विरुद्ध कोई शुल्क नहीं लगाए गए थे।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के अनुरोध के संबंध में, यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग ने लागू व्यापार सूचनाओं और डीजीटीआर की परिपाटी के अनुसार अपना अगोपनीय रूपांतर दायर किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

26 घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक की गई और तदनुसार हल किया गया। गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फ़ाइल के रूप में उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह भी नोट करते है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

27. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क काफी समय से लागू हैं। इस संदर्भ में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, जिसमें प्राधिकारी सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच करते हैं, जैसाकि आवेदक द्वारा मांग की गई है। शुल्क के विस्तार की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब ऐसी संभावना सिद्ध करने वाले सकारात्मक साक्ष्य पाए जाएं। इसके अलावा, जहां निर्यातक देश में उत्पादक अपनी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से लाभान्वित होते रहते हैं, घरेलू उद्योग को सब्सिडी वाले आयात के विरुद्ध सुरक्षा मांगने का अधिकार बरकरार रहता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच सब्सिडीरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग कानूनी उपायों और सुरक्षा का लाभ उठाने का पूर्ण हकदार है, जहां यह सिद्ध हो कि किसी भी देश के निर्यातक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली परिपाटियों में लगे हुए हैं।

भाग-II

च. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

28. मलेशिया से उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की सलाह दी गई थी और उन्हें ऐसी सब्सिडियों, यदि कोई हों, की मौजूदगी और मात्रा का उचित निर्धारण करने के लिए तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव पर सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

29. मलेशिया सरकार सहित मलेशिया के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

i. मेसर्स शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी

ii. एसबीएच किर्बिंग सोलर न्यू मैटेरियल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी

कथित सब्सिडी कार्यक्रमों का सामान्य अवलोकन

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के निर्यातकों/उत्पादकों/ उनकी संबद्ध कंपनियों को विभिन्न प्रतिकार योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों से लाभ हुआ है।

ख. संबद्ध देश की सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं की है/न ही कोई सार्थक सूचना दी है। केवल सरकार ही इस संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान कर सकती है कि क्या उक्त योजना प्रतिकार योग्य है या नहीं। उत्तरदाता निर्यातक ही यह सूचना दे सकता है कि क्या कोई लाभ लिया था या नहीं। अन्य अधिकार क्षेत्रों में, जहां निर्यातक देश की सरकार सहयोग नहीं करती है, जांच अधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करते हैं और योजनाओं की प्रतिकार योग्यता का निर्धारण करते हैं।

ग. यह अनुरोध किया जाता है कि मलेशिया के निर्यातकों के साथ-साथ मलेशिया सरकार भी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उचित तरीके से उत्तर देने में विफल रही है। उन्होंने या तो नई योजनाओं से संबंधित सूचना प्रदान करने से इनकार कर दिया है या इसे प्रदान करने से चूक गए हैं। यह सादर अनुरोध है कि नई सब्सिडी योजनाओं के बारे में सूचना प्रदान करने से इनकार करना या उसमें चूक करना नियमावली कार्य-ढांचे के अंतर्गत संबंधित पक्षकारों द्वारा असहयोग है।

घ. जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में निहित है और साथ ही प्राधिकारी द्वारा पिछले मामलों में माना गया है, मलेशिया में शुरू की गई कोई भी नई योजना निर्णायक समीक्षा जांच के क्षेत्र में है। इसलिए, नई योजनाओं के संबंध में जानबूझकर सूचना से इंकार करना मलेशियाई सरकार पर नहीं है। मलेशियाई सरकार के साथ-साथ मलेशिया से निर्यातकों को असहयेागी पक्षकार माना जाना है।

ड. यह सादर अनुरोध है कि सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार तथा भारतीय सब्सिडीरोधी कानूनों के तहत, किसी भी जांच किए गए देश की सरकार किसी अन्य निर्यातक, आयातक आदि की तरह ही एक संबद्ध पक्षकार है। अत:, मलेशियाई सरकार की ओर से इस विफलता को अनिवार्य रूप से जांच में बाधा डालने का एक जानबूझकर प्रयास माना जाना चाहिए। इस प्रकार, निर्यातक को भी असहयोगी माना जाना है और उन्हें अपनी सरकार द्वारा जानबूझकर असहयोग करने के परिणाम भुगतने हैं।

च. यह स्वीकार किए बिना कि कुछ संगत सब्सिडी योजनाएं वास्तव में समाप्त हो गई हैं, यह ऐसी सब्सिडी योजनाओं के पुनः ब्रांडिंग या नामकरण या प्राप्त लाभों के निरंतर प्रभाव की संभावना को अलग नहीं करता है। निर्यातकों के साथ-साथ मलेशिया सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह मलेशिया में शुरू की गई किसी भी नई सब्सिडी योजना के बारे में प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से सूचित करे। तथापि, यह सूचना रोककर प्राधिकारी के साथ पूरी तरह से सहयोग करने से इनकार करने से यह बेहद संभावना है कि संबद्ध देश में नए लागू किए गए होंगे जिसमें निर्यातकों को कार्रवाई योग्य/प्रतिबंधित सब्सिडियों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

छ. जहां तक इस आरोप का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने सब्सिडी को प्रमाणित करने के लिए सभी संगत दस्तावेज प्रकट नहीं किए हैं, यह अनुरोध है कि मूल जांच में ही संबद्ध देश में सब्सिडी प्रमाणित है। इसके अलावा, ऐसा तर्क घरेलू उद्योग द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक कानूनी सीमा की गलत समझ पर आधारित है। निर्धारित कानूनी स्थिति के संदर्भ में, घरेलू उद्योग को जांच शुरू करने के लिए केवल प्रथम दृष्टया मामला दर्शाने की आवश्यकता है और यह संबंधित सरकार और निर्यातकों पर निर्भर है कि वे घरेलू उद्योग के तर्कों का खंडन करें। यह अनुरोध है कि विशिष्टता, लाभ और क्षति के संबंध के लिए कानूनी सीमाएं घरेलू उद्योग के साक्ष्य द्वारा सब्सिडी और इसके हानिकारक प्रभाव की पुष्टि करके पूरी की गई हैं।

ज. सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, मलेशिया में संबद्ध सामानों के निर्यातकों को कुछ लाभ उपलब्ध हैं। मलेशिया सरकार ने भाग लेने वाले निर्यातकों को भी कुछ लाभ दिए हैं। घरेलू उद्योग विनम्रतापूर्वक प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह सभी योजनाओं के लिए लाभों की गणना करे, चाहे वे उनके द्वारा उनकी आवेदन-पत्र में पहचाने गए हों या नहीं।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सब्सिडी कार्यक्रमों और मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी ने कार्यक्रमों का पर्याप्त विश्लेषण किए बिना जांच शुरू कर दी है। आवेदक ने प्रतिकार योग्य सब्सिडी के तीन तत्वों अर्थात् (क) वित्तीय योगदान, (ख) लाभ, और (ग) विशिष्टता की मौजूदगी सिद्ध नहीं की।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए आरोप कि मलेशिया सरकार और निर्यातकों ने पूरी सूचना नहीं दी है, पूरी तरह से निराधार, बेबुनियाद और रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के विपरीत है। उत्पादकों/निर्यातकों तथा मलेशिया सरकार ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग दिया है। प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सभी सूचना और आंकड़ों को निर्धारित समय सीमा के भीतर और नियमावली के तहत अपेक्षित प्रपत्र में विधिवत प्रस्तुत किया गया है।

ग. आवेदक आरोपों का समर्थन करने के लिए 'पर्याप्त साक्ष्य' देने में विफल रहा। मलेशिया में संबद्ध सामानों से कथित कार्यक्रम को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है। आवेदक द्वारा तथाकथित अधिकतर सब्सिडियां बिना किसी वास्तविक सबूत के मात्र दावे हैं। अत:, आरोप अपर्याप्त हैं और एएससीएम के सिद्धांतों को अनदेखा करते है।

घ. प्राधिकारी को किसी भी उद्देश्य के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों और मार्जिन का विश्लेषण करने के लिए निर्यातकों द्वारा दायर सत्यापित आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

च.3 परिकलन पद्धति

32. एएससीएम के अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 1 के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में प्राप्तकर्ता को दिए गए लाभ की गणना के लिए दिशानिर्देश और पद्धति का प्रावधान है और आगे यह भी प्रावधान है कि प्राप्तकर्ता को लाभ की गणना करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट की गई होगी। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता को लाभ की गणना करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई पद्धति संबंधित सदस्य के राष्ट्रीय कानून या कार्यान्वयन विनियमों में प्रदान की जाएगी और प्रत्येक विशेष मामले में इसका अनुप्रयोग पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाएगा। अपेक्षा के अनुसार, सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 सब्सिडी की मात्रा निर्धारित करने की पद्धति निर्धारित करती है। इस जांच में निर्धारण इन दिशानिर्देशों के अनुसार है।

33. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी प्रतिकार योग्य कार्यक्रम के तहत एक बार स्वीकार योग्य सब्सिडी का प्रतिकार करने का प्रस्ताव किया हैं न कि दोहरी प्रतिकार योग्यता का।

च.3.1 याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच:

निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रमों को विशेष रूप से याचिका में आरोप लगाया गया है और जांच शुरुआत की सूचना में उल्लेख किया गया है।

i. कार्यक्रम 1: प्राकृतिक गैस में सब्सिडी

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने वाली कंपनी द्वारा औद्योगिक प्रयोक्ताओं को रियायती दर पर प्रदान की जाती है। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया कि यह सब्सिडी विनिर्माण गतिविधियों में लगे उद्योगों के लिए उपलब्ध है। यह, बदले में, विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों को सस्ती गैस तक पहुंच प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, गैस कंपनी को सरकार द्वारा सब्सिडी की सीमा तक मुआवजा दिया जाता है। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन-पत्र में सहायक साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

35. यह अनुरोध किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से, गैस की कीमत अविनियमित रही है और गैस बिक्री करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार इच्छुक-खरीदार, इच्छुक-विक्रेता के आधार पर निर्धारित की गई है।

36. विदेश मंत्रालय (एमईए) और ऊर्जा आयोग (ईसी) मलेशिया सरकार द्वारा संशोधन अनुमोदन सहित विनियमित गैस कीइ कीमतों से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखते हैं।

37. औद्योगिक ग्राहकों से ली जाने वाली गैस की कीमत प्रशुल्क श्रेणी के आधार पर है। एक ही प्रशुल्क श्रेणी के सभी ग्राहकों पर समान कीमत लगाई जाएगी।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

38. मूल जांच में प्राधिकारी ने वर्तमान योजना के संबंध में निम्नलिखित जांच परिणाम दर्ज किए हैं:

"43. प्राधिकारी इस तथ्य को नोट करते है कि न तो मलेशिया सरकार और न ही मलेशिया के सहयोगी उत्पादक ने इस योजना की प्रतिकार योग्यता के खिलाफ कोई अनुरोध किया है। फिर भी, प्राधिकारी योजना की प्रतिकार योग्यता की जांच निम्नलिखित रूप में करते हैं:

क) मलेशिया सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह उल्लेख है कि मलेशिया में गैस की कीमतें सरकार द्वारा विनियमित हैं।

ख) मलेशिया सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि गैस की बाजार कीमतों और औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए गैस की कीमतों में कीमत अंतर है।

ग) इसके अलावा, मलेशिया सरकार के उत्तर में यह भी उल्लेख है कि औद्योगिक ग्राहकों से ली जाने वाली गैस की कीमत प्रशुल्क श्रेणी के आधार पर है, जो खपत-आधारित प्रशुल्क प्रणाली दर्शाती है।

39. वर्तमान समीक्षा जांच में मलेशिया सरकार द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया जाता है कि:

क) विदेश मंत्रालय (एमईए) और ऊर्जा आयोग (ईसी) मलेशिया सरकार द्वारा विनियमित और गैस कीमतों के संशोधन की मंजूरी का रिकॉर्ड रखते हैं।

ख) गैस की बाजार कीमतों और औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए गैस की कीमतों में कीमत अंतर है।

ग) औद्योगिक ग्राहकों से ली जाने वाली गैस की कीमत प्रशुल्क श्रेणी के आधार पर है।

40. अत:, यद्यपि निर्यातकों और मलेशिया सरकार ने वर्तमान योजना के तहत सब्सिडी की मौजूदगी से इनकार किया है और कहा है कि, 2022 के बाद से, गैस की कीमतें अविनियमित रही हैं, तथापि प्राधिकारी ने निर्यातकों दोनों निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की जांच की है और प्रत्येक निर्यातक के संबंध में डेस्क सत्यापन भी किया है। ऐसी जांच पर यह पाया गया है कि:

41. **एसबीएच किर्बिंग सोलर न्यू मैटेरियल:** डेस्क सत्यापन के दौरान निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना से पता चलता है कि उसने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, सबा एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड से पर्याप्त पारिश्रमिक से कम (एलटीएआर) पर गैस खरीदी है। यह भी देखा गया है कि सबा एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड ने एक स्पष्टीकरण

जारी किया है कि सबा क्षेत्र में गैस की कीमतें मलेशियाई संदर्भ कीमत (एमआरपी) के ***% से कम हैं। इसलिए प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि निर्यातक ने सबा एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड से पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर गैस प्राप्त की है, और यह कीमत निर्धारण क्षेत्र-विशिष्ट है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित है जो मलेशियाई संदर्भ कीमत से ***% से कम कीमत पर गैस की बिक्री करता है। तदनुसार, यह प्रतिकार योग्य सब्सिडी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

42. **शिनयी सोलर:** शिनयी सोलर एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया ने अनुरोध किया है कि उसने जांच की अवधि अवधि के दौरान कोई छूट, रियायत या विशिष्ट प्रशुल्क प्राप्त नहीं किए हैं। प्राकृतिक गैस आपूर्ति, गैस आपूर्तिकर्ता और उसकी संबद्ध कंपनी के बीच निष्पादित गैस आपूर्ति करार से शासित है, जिसके नाम से गैस मीटर और आपूर्तिकर्ता बीजक जारी किए जाते हैं। गैस मीटर कंपनी और उसकी संबद्ध कंपनी के बीच साझा किया जाता है। कंपनी को गैस आपूर्तिकर्ता से कोई छूट, रियायत या तरजीही प्रशुल्क प्राप्त नहीं होता। गैस लागत को बिना किसी मार्क-अप, मार्जिन या वाणिज्यिक समायोजन के, वास्तविक खपत के आधार पर हमारी कंपनी के बीच आवंटित और वापस चार्ज किया जाता है। प्राधिकारी ने अपने आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक कीमतों से सत्यापन किया है और पाया है कि शिनयी को एलटीएआर पर गैस प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार, प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि शिनयी सोलर के इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

ii. कार्यक्रम 2: बाज़ार विकास अनुदान

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

43. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि योजना निर्यात संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसएमई के लिए मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकारी (एमआईडीए) द्वारा शुरू की गई है। एमडीजी कार्यक्रम के तहत एक एसएमई के लिए अधिकतम अनुदान 200,000 आरएम है। एसएमई को कम से कम 60% मलेशियाई इक्विटी स्वामित्व के साथ कंपनी अधिनियम, 1965 के तहत शामिल किया जाना चाहिए था। साक्ष्य और कानूनी आधार सामान्य नीतियां, सुविधाएं और बाजार विकास अनुदान (एमडीजी)-2016 के लिए दिशानिर्देश हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. बाजार विकास अनुदान (एमडीजी) एसएमई मास्टरप्लान का हिस्सा था जो उच्च आय वाले राष्ट्र की स्थिति प्राप्त करने के लिए एसएमई के विकास को गति देने में गेम चेंजर होगा।

45. एमडीजी मलेशियाई एसएमई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार और निवेश मिशनों/ एक्सपोर्ट एक्सिलरेशन मिशनों, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, विदेशी व्यापार और सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट या विदेशों में खुदरा केंद्रों में मेड-इन-मलेशिया उत्पादों के लिए सूचीकरण शुल्क जैसे निर्यात संवर्धन गतिविधियों में भाग लेने के लिए 200,000 आरएम तक के प्रतिपूर्ति योग्य अनुदान के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार विकास योजना (एमडीपी) का उद्देश्य निर्यात संवर्धन गतिविधियों में एसएमई की भागीदारी को बढ़ाना है। एमडीपी एसएमई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार और निवेश मिशन/एक्सपोर्ट एक्सिलरेशन मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, विदेशों में सूचीकरण फीस और सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट या खुदरा केंद्रों में मलेशिया में निर्मित उत्पादों जैसी निर्यात संवर्धन गतिविधियों में उनकी भागीदारी के लिए 2,00,000 आरएम तक की प्रतिपूर्ति योग्य अनुदान प्रदान करता है। मलेशिया सरकार ने कहा है कि कार्यक्रम में कोई अपेक्षित परिवर्तन नहीं है।

47. सब्सिडी कार्यक्रम प्रत्यक्ष हस्तांतरण निधि के रूप में वित्तीय योगदान के लिए प्रदान करता है और इस प्रकार प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर है। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य के रूप में नोट किया गया है। हालांकि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

iii. कार्यक्रम 3: अग्रणी स्थिति

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

48. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत अग्रणी स्तर प्रदान की गई कंपनी को कारपोरेट आयकर से छूट मिलेगी। यह कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र में प्रचारित गतिविधियों/उत्पादों में निवेश को प्रोत्साहित करता है जो अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। यह विनिर्माण क्षेत्र में अनुमोदित प्रचारित उत्पादों/ गतिविधियों के लिए स्थानीय और विदेशी दोनों निवेशकों पर लागू होता है। आयकर के भुगतान से पांच साल की आंशिक छूट प्रदान की जाती है। एक कंपनी अपनी सांविधिक आय के 30% पर कर का भुगतान करती है, जिसमें छूट की अवधि उसके उत्पादन दिवस से शुरू होती है। अग्रणी अवधि के दौरान उपार्जित पूंजी भत्ते और संचित नुकसान को अग्रेणीत किया जा सकता है और कंपनी की अग्रणीय स्तर के बाद की आय से घटाया जा सकता है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

क) निवेश अधिनियम, 1986 का संवर्धन

ख) गैट 1994 के अनुच्छेद xvi:1 और सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार-मलेशिया दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 के अनुच्छेद 25 के अनुसरण में पूर्ण अधिसूचना।

ग) http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/

घ) संवर्धित क्रियाकलापों और उत्पादों की सूची जो निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 1986 के तहत अग्रणी स्थिति और निवेश कर भत्ते पर विचार करने के लिए पात्र हैं।

ङ.) निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 भाग-2 धारा 5, 6, 7, के संवर्धन के मलेशिया अधिनियम, 327 के कानून अग्रणी स्थिति से संबंधित है

च) वेब रिपोर्ट: एक्सिम बैंक का निर्यात ऋण पुनर्वित्त।

छ) मलेशिया के माध्यम से यूएस एक्सटूड

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षेकारों द्वारा किए गए अनुरोध

49. किसी संवर्धित क्रियाकलाप में भाग लेने या उस क्रियाकलाप/उत्पाद संवर्धित उत्पाद का उत्पादन करने की इच्छुक किसी भी कंपनी को अग्रणी स्तर प्रदान किया जाए, जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व का हो। संवर्धित क्रियाकलाप और संवर्धित उत्पाद वित्त मंत्री और निवेश और व्यापार मंत्री उद्योग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संवर्धित उत्पादों और क्रियाकलापों में अन्य में सभी क्षेत्र विनिर्माण, कृषि और सेवाएं शामिल हैं।

50. कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन अग्रणी स्तर और निवेश कर भत्ता हैं। कंपनियां इनमें से किसी एक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती हैं क्योंकि ये प्रोत्साहन परस्पर अनन्य हैं। कंपनियों को अग्रणी स्तर कार्यक्रम के लिए आवेदन मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकारी (एमआईडीए), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमआईटीआई) के तहत एक एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसके बाद कंपनी को एमआईडीए से अग्रणी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यह सुनिश्चित करने किया जाना है कि कंपनी ने लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया है। एमआईडीए संतुष्ट होने के बाद कि कंपनी ने शर्तों का पालन किया है, एमआईडीए कंपनी के लिए उत्पादन की तारीख निर्धारित करेगा और कार्यक्रम की शुरुआत और समाप्ति की तारीख निर्धारित करेगा। बाद में, कार्यक्रम के साथ अनुमोदित कंपनियां कर कटौती के लिए दावे की गणना वाले अपने वार्षिक कर विवरणी के साथ इनलैंड राजस्व बोर्ड को अपने दावे प्रस्तुत करती हैं। आवेदकों को अनुमोदन समिति से भी गुजरना होगा।

51. कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन अग्रणी स्तर और निवेश कर भत्ता हैं। ये प्रोत्साहन परस्पर अनन्य हैं। धारा 5-25 निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 1986 इसके प्रमाण हैं। लाभ पर देय करों से छूट है। साथ ही, हानियों को अग्रणीत किया जा सकता है।

52. अग्रणीय स्तर के लिए पात्रता मानदंड हैं: मूल्य वर्धित (वीए) प्रतिशत का स्तर; और प्रबंधकीय, तकनीकी और पर्यवेक्षक (एमटीएस) सूचकांक द्वारा मापी गई प्रौद्योगिकी का स्तर।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

53. प्राधिकारी नोट करते है कि निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 1986 की धारा 5 से 25 में अग्रणीय स्तर कार्यक्रम का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में आयकर से छूट के रूप में कर प्रोत्साहन का प्रावधान है। छूट अवधि के दौरान होने वाले नुकसान को कर योग्य आय/ शुद्ध लाभ को ऑफसेट करने के लिए बाद के वर्षों के लिए अग्रेणीत किया जा सकता है। यह कार्यक्रम संवर्धित उत्पादों /क्रियाकलापों की पूर्व-निर्दिष्ट सूची के लिए उपलब्ध है।

54. इस कार्यक्रम में राजस्व त्याग के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है, जो अन्यथा देय है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह सूची में उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप/उललिखित उत्पाद के लिए उपलब्ध है। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य के रूप में नोट किया गया है। हालांकि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

iv. कार्यक्रम 4: निवेश कर नीतियां

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

55. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत, निवेश कर भत्ता (आईटीए) प्राप्त कंपनी प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए वैधानिक आय के विरुद्ध इस भत्ते को ऑफसेट करने की हकदार है। यह कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र में संवर्धित क्रियाकलापों/ उत्पादों में निवेश को प्रोत्साहित करता है, जो अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। यह विनिर्माण क्षेत्र में संवर्धित उत्पादों/क्रियाकलापों के लिए स्थानीय और विदेशी निवेशकों, दोनों पर लागू होता है। पहले अर्हता प्राप्त पूंजी व्यय पर 5 वर्षों के भीतर किए गए अपने अर्हता प्राप्त पूंजी व्यय पर 60% का भत्ता दिया जाता है। कंपनी प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए अपनी वैधानिक आय के 70% के विरुद्ध इस भत्ते को ऑफसेट कर सकती है। इसकी वैधानिक आय का शेष 30% प्रचलित कंपनी कर दर पर कर लगाया जाएगा। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

क) निवेश अधिनियम, 1986 का संवर्धन

ख) गैट 1994 के अनुच्छेद 16:1 और सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार-मलेशिया दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 के अनुच्छेद 25 के अनुसरण में अधिसूचना।

ग) http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/

घ) उन संवर्धित क्रियाकलापों और उत्पादों की सूची जो निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 1986 के तहत अग्रणी स्थिति और निवेश कर भत्ते पर विचार किए के लिए पात्र हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षेकारों द्वारा किए गए अनुरोध

56. किसी संवर्धित क्रियाकलाप में भाग लेने या उस क्रियाकलाप/उत्पाद संवर्धित उत्पाद का उत्पादन करने की इच्छुक किसी भी कंपनी को अग्रणी स्तर प्रदान किया जाए, जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व का हो। संवर्धित क्रियाकलाप और संवर्धित उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मत्री द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 (अधिनियम 327) की धारा 26-29 इसके साक्ष्य हैं।

57. यह भत्ता केवल औद्योगिक भवनों, संयंत्र और मशीनरी पर किए गए पूंजीगत व्यय पर दिया जाता है जो सीधे बढ़ावा दी गई क्रियाकलापों या बढ़ावा दिए गए उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कंपनियों को एमआईटीआई के तहत एक एजेंसी, एमआईडीए को आईटीए कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद कंपनी को एमआईडीए द्वारा विधिवत प्रमाणित पहले पूंजीगत व्यय की शुरुआत के लिए आईटीए अवधि की शुरुआत सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। बाद में, कार्यक्रम के साथ अनुमोदित कंपनियां कर कटौती के लिए दावे की गणना वाले अपने वार्षिक कर विवरणी के साथ इनलैंड राजस्व बोर्ड (आईआरबी) को अपने दावे प्रस्तुत करती हैं।

58. आईटीए के लिए पात्रता मानदंड प्रबंधकीय, तकनीकी और पर्यवेक्षक (एमटीएस) सूचकांक द्वारा मापी गई मूल्य वर्धित (वीए) प्रतिशत और प्रौद्योगिकी का स्तर है।

59. सभी व्यक्ति/फर्में जिन्होंने आवेदन किया और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया, उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है। आवेदकों को अनुमोदन समिति से गुजरना होगा। सहायता सांविधिक आय से कटौती है। भत्ते को पूरी तरह से उपयोग किए जाने तक अग्रेणीत जा सकता है।

60. कोई कंपनी अग्रणीय स्तर प्राप्त करने के लिए चुनी जा सकती है लेकिन निवेश कर भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है, या निवेश कर भत्ता प्राप्त करने के लिए चुनी जा सकती है, लेकिन अग्रणीय स्तर नहीं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश कर भत्ता कार्यक्रम के लिए निवेश संवर्धन अधिनियम 1986 की धारा 26 से 29 में प्रावधान है। संवर्धित क्रियाकलापों और संवर्धित उत्पादों को पूंजी भत्ता दिया जाता है। मूल्य संवर्धन और तकनीकी अपेक्षाओं को भी पूरा किया जाना होता है। पहली अर्हता प्राप्त पूंजी व्यय किए जाने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर किए गए अर्हता प्राप्त पूंजी व्यय पर 60% का निवेश कर भत्ता। भत्ते का उपयोग मूल्यांकन के प्रत्येक वर्ष के लिए सांविधिक आय के 100% के विरुद्ध ऑफसेट करने के लिए किया जा सकता है। किसी भी अप्रयुक्त भत्ते को पूरी तरह से उपयोग किए जाने तक बाद के वर्षों में अग्रेणीत किया जा सकता है। यहां तक कि उन कंपनियों के लिए जो संवर्धित क्रियाकलाप, मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी के स्तर के सूचीबद्ध मानदंडों को पूरा करती हैं, प्राधिकारी इस कार्यक्रम के तहत लाभ चाहने वाले आवेदक को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार रखते हैं।

62. इस कार्यक्रम में राजस्व त्याग के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उद्यमों तक सीमित है, जो संवर्धित उत्पाद को पूरा करता है और प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। जिस कंपनी को अग्रणीय स्तर से आयकर छूट प्राप्त हुई है, वह इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं उठा सकती है। कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए जाना जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि कोई भी निर्यातक किसी भी दो योजनाओं में से किसी एक के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है और इसलिए, किसी एक योजना के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए ने कि दोनों के लिए।

63. **एसबीएच किर्बिंग सोलर न्यू मैटेरियल:** निर्यातक द्वारा अपने उत्तर और डेस्क सत्यापन के दौरान प्रस्तुत सूचना और दस्तावेज दर्शाते हैं कि उसने योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी नोट करते है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

64. **शिनयी सोलर:** शिनयी सोलर एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया ने अनुरोध किया है कि उसने वर्तमान योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है, जिसके तहत जनवरी 2015 से दस (10) वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन सुविधाओं पर किए गए कुल निवेश लागत का उपयोग वर्ष 2015 से संचित आईटीए का पूरी तरह से उपयोग होने तक अर्जित कर योग्य लाभ को ऑफसेट करने के लिए किया जा सकता है। डेस्क सत्यापन के दौरान निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्यापन किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

v. कार्यक्रम 5: पुनर्निवेश भत्ता

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

65. मौजूदा कंपनियों के लिए पुनर्निवेश भत्ता (आरए) उपलब्ध है जो विनिर्माण और चयनित कृषि गतिविधियों में लगी हुई हैं जो विस्तार, स्वचालन, आधुनिकीकरण या उसी उद्योग के भीतर किसी भी संबंधित उत्पादों में विविधीकरण के प्रयोजनों के लिए पुनर्निवेश करती हैं, इस शर्त पर कि ऐसी कंपनियां कम से कम 36 महीनों से प्रचालन में हैं। आरए कंपनी द्वारा किए गए अर्हता प्राप्त पूंजीगत व्यय पर 60% की दर से दिया जाता है, और मूल्यांकन के वर्ष के लिए इसकी सांविधिक आय के 70% के विरुद्ध ऑफसेट किया जा सकता है। किसी भी अप्रयुक्त भत्ते को पूरी तरह से उपयोग किए जाने तक बाद के वर्षों में अग्रणीत किया जा सकता है।

66. एक कंपनी मूल्यांकन के वर्ष के लिए अपनी सांविधिक आय के 100% के विरुद्ध आरए को ऑफसेट कर सकती है, यदि कंपनी वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक उत्पादकता स्तर प्राप्त करती है।

67. आरए प्रथम पुनर्निवेश किए जाने के वर्ष से आरंभ होने वाले 15 वर्षों की लगातार अवधि के लिए दिया जाएगा। कंपनियां केवल अर्हता प्राप्त परियोजना के पूरा होने पर, यानी भवन के पूरा होने के बाद या जब संयंत्र/मशीनरी प्रचालनात्मक उपयोग में लाई जाती है, आरए का दावा कर सकती हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षेकारों द्वारा किए गए अनुरोध

68. मलेशिया सरकार सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस योजना का कोई विवरण नहीं दिया। मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि उचित औचित्य के बिना मूल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) जांच का हिस्सा नहीं रहे कथित सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करना सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार (एएससीएम) के मौलिक सिद्धांतों और साक्ष्य सत्यापन के लिए स्थापित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।

69. मलेशिया सरकार का मानना है कि डीजीटीआर को सभी साक्ष्यों का पूरी तरह से सत्यापन करना चाहिए और केवल असमर्थित आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे उचित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के लिए एएससीएम की मौलिक अपेक्षाओं का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 11.2 के साक्ष्य मानकों को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रमों का जुड़ना जांच प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है और स्थापित डब्ल्यूटीओ दायित्वों का उल्लंघन करता है।

70. अनुच्छेद 11.2 के तहत, जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन-पत्र में (क) सब्सिडी और, यदि संभव हो, इसकी राशि; (ख) अनुच्छेद 15 के अर्थ के भीतर क्षति ; और (ग) सब्सिडी वाले आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य शामिल होगा"। जांच प्राधिकारी इन मूलभूत साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रम को जोड़ नहीं सकते हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पुनर्निवेश भत्ता (आरए) आयकर अधिनियम, 1967 की अनुसूची 7क के तहत प्रदान किया जाता है। यह मौजूदा विनिर्माण और कुछ कृषि कंपनियों को विस्तार, आधुनिकीकरण, स्वचालन या संबंधित उत्पादों में विविधीकरण में पुनर्निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

72. प्राधिकारी आयकर अधिनियम और मलेशियाई कर प्रोत्साहन पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मार्गदर्शन के आधार पर नोट करते हैं कि आरए: (i) पुनर्निवेश के लिए एक दीर्घावधि अवधि भत्ता (15 वर्ष) है; (ii) क्षमता विस्तार और तकनीकी उन्नयन के लिए पूंजी पुनर्निवेश को प्रोत्साहित करता है; और (iii) पूंजी-गहन निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण कर बचत प्रदान करता है।

73. अत:, तीन-तत्व परीक्षण को लागू करके: (i) वित्तीय योगदान: आरए कर योग्य आय आधार को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा राजस्व छोड़ा जाता है; (ii) लाभ: आरए कंपनियों को मानक व्यवस्था के तहत कम आयकर का भुगतान करने की अनुमति देता है। लाभ को आरए कटौती के कारण बचाए गए कर के रूप में निर्धारित किया जा सकता है; और (iii) विशिष्टता: आरए केवल मौजूदा विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है, जो 36 महीने की संचालन शर्त और निर्दिष्ट परियोजनाओं में पुनर्निवेश के अधीन है। यह सामान्य रूप से उपलब्ध उपाय नहीं है। इस प्रकार पुनर्निवेश भत्ता सैद्धांतिक रूप से प्रतिकार योग्य सब्सिडी है। हालाँकि, इस कार्यक्रम के तहत सहयोगी निर्यातकों द्वारा लाभ नहीं उठाया जाता है।

vi. कार्यक्रम 6: बढ़ाया गया पूंजी भत्ता

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

74. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत एक विशेष भत्ता दिया जाता है, जहां पूंजीगत व्यय को 2 वर्षों के भीतर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, अर्थात 40% का प्रारंभिक भत्ता और 20% का वार्षिक भत्ता दिया जाता है। पुनर्निवेश भत्ते के लिए पात्रता की 15 साल की अवधि के बाद, जो कंपनियां संवर्धित उत्पादों के निर्माण में पुनर्निवेश करती हैं, वे त्वरित पूंजी भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवेदन एमआईडीए से एक पत्र के साथ आईआरबी को प्रस्तुत किए जाने हैं, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि कंपनियां संविर्धित क्रियाकलापों/उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। कार्यक्रम के की मौजूदगी के साक्ष्य रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

क) निवेश अधिनियम, 1986 का संवर्धन

ख) http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/

ग) संवर्धित क्रियाकलापों और उत्पादों की सूची जो निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के तहत अग्रणी स्थिति और निवेश कर भत्ते पर विचार करने के लिए पात्र हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षेकारों द्वारा किए गए अनुरोध

75. बढ़ाया गया पूंजी भत्ता (एसीए) में दो वर्षों के भीतर अर्थात पहले वर्ष में 20 प्रतिशत का प्रारंभिक भत्ता और 40 प्रतिशत का वार्षिक भत्ता के अंतर्गत पूंजीगत व्यय को बट्टे खाते में डालने के लिए भत्तों का प्रावधान है। यह कार्यक्रम सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है और आईआरबी एसीए प्रदान करने में वस्तुनिष्ठ मानदंड लागू करता है। यह सहायता एक बढ़ाया गया पूंजी भत्ता है जिसे कर योग्य आय से घटाया जाता है। इस भत्ते को अग्रेणीत किया जा सकता है। आम तौर पर, बढ़ाए गए पूंजी भत्ते (एसीए) के लिए पात्र होने हेतु, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए:

क) वह आधार अवधि के दौरान व्यवसाय कर रहा था,

ख) उसने आधार अवधि में पात्र व्यय किया है,

ग) परिसंपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए किया गया था, और

घ) आधार अवधि के अंत में, वह परिसंपत्ति का स्वामी था और परिसंपत्ति प्रयोग में थी।

76. जांचाधीन कंपनियां एसीए का दावा करने के लिए पात्र होंगी, यदि वे मानदंडों को पूरा करती हैं और सरकार यह विवेकाधिकार नहीं बरतती है कि कौन सी कंपनी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम में दो वर्षों के भीतर कुल पूंजीगत व्यय को बट्टे खाते में डालने के लिए पूंजी भत्ता प्रदान किया गया है, अर्थात, पहले वर्ष में 20 प्रतिशत का प्रारंभिक भत्ता और 40 प्रतिशत का वार्षिक भत्ता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम में राजस्व त्याग के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उद्यमों के लिए उपलब्ध है जो संबंधित क्रियाकलाप कर हैं, जो इस भत्ते का उपयोग करने के लिए योग्य है और पात्रता की 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के कारण पुनर्निवेश भत्ते के लिए पात्र नहीं है। इसलिए, कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य माना जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

vii. कार्यक्रम 7: हरित वित्तपोषण पहलें

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

78. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, यह योजना मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकारी (एमआईडीए) (https://www.mida.gov.my/), द्वारा संचालित है, इन वित्तीय प्रोत्साहनों में नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों के लिए पर्याप्त कर लाभों का प्रावधान है। कार्यक्रम योग्य हरित व्यय पर पूंजी भत्ते प्रदान करता है, जबकि जीआईटीई पात्र हरित गतिविधियों से प्राप्त आय के एक प्रतिशत को कराधान से छूट देता है, प्रभावी रूप से पीपीए व्यवस्था सहित सौर परियोजनाओं के लिए निवेश पर आय को बढ़ाता है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

79. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि उचित औचित्य के बिना मूल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) जांच का हिस्सा नहीं होने वाले कथित सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करना सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार (एएससीएम) के मौलिक सिद्धांतों और साक्ष्य सत्यापन के लिए स्थापित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।

80. मलेशिया सरकार का विचार है कि डीजीटीआर को सभी सबूतों का पूरी तरह से सत्यापन करना चाहिए और केवल असमर्थित आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे उचित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के लिए एएससीएम की मौलिक अपेक्षाओं का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 11.2 के साक्ष्य मानकों को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रमों का जुड़ना जांच प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है और स्थापित डब्ल्यूटीओ दायित्वों का उल्लंघन करता है।

81. अनुच्छेद 11.2 के तहत, जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन-पत्र में (क) सब्सिडी और, यदि संभव हो, इसकी राशि; (ख) अनुच्छेद 15 के अर्थ के अभिप्राय से क्षति और (ग) सब्सिडी वाले आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य शामिल होगा"। जांच प्राधिकारी इन मूलभूत साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रम को जोड़ नहीं सकते हैं।

82. किसी भी प्रतिभागी निर्यातक ने इस कार्यक्रम के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या उन्होंने इसके तहत किसी भी सब्सिडी का लाभ उठाने से परहेज किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

83. प्राधिकारी नोट करते हैा कि घरेलू उद्योग द्वारा रखी गई सामग्री और हरित प्रौद्योगिकी के लिए मलेशियाई कर प्रोत्साहन पर सामान्य सूचना के आधार पर लाभार्थियों को सामान्य बाजार स्थितियों की तुलना में कम वित्तपोषण लागत या कम कर देनदारियों का लाभ मिलता है; और इस तरह के उपाय हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा गतिविधियों के लिए विशिष्ट हैं, जो आम तौर पर सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम को सिद्धांत रूप में प्रतिकार योग्य मानते हैं। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

viii. कार्यक्रम 8: नेट एनर्जी मीटरिंग (एनईएम) और सौर प्रोत्साहन

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

84. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वर्तमान कार्यक्रम के तहत, मलेशिया सरकार सौर उत्पादन (रूफटॉप, ऑनसाइट) के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

85. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, एनईएम राक्यत पहल मलेशिया की एनईएम 3.0 योजना का हिस्सा है, जिसे नेट मीटरिंग की अनुमति के माध्यम से रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना के तहत, मलेशियाई सरकार ने सोलर फॉर राक्यत इंसेंटिव स्कीम (सोलारिस) शुरु की थी, जिसमें घरेलू सौर प्रतिष्ठानों के लिए एमआईआर 4,000 (942.12 डॉलर) तक की छूट की पेशकश की गई थी।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

86. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि उचित औचित्य के बिना मूल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) जांच का हिस्सा नहीं होने वाली कथित सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करना सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार (एएससीएम) के मौलिक सिद्धांतों और साक्ष्य सत्यापन के लिए स्थापित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।

87. मलेशिया सरकार का विचार है कि डीजीटीआर को सभी सबूतों का पूरी तरह से सत्यापन करना चाहिए और केवल असमर्थित आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे उचित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के लिए एएससीएम की मौलिक अपेक्षाओं का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 11.2 के साक्ष्य मानकों को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रमों का जुड़ना जांच प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है और स्थापित डब्ल्यूटीओ दायित्वों का उल्लंघन करता है।

88. अनुच्छेद 11.2 के तहत, जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन-पत्र में (क) सब्सिडी और, यदि संभव हो, इसकी राशि; (ख) अनुच्छेद 15 के अर्थ के अभिप्राय से क्षति और (ग) सब्सिडी वाले आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य शामिल होगा"। जांच प्राधिकारी इन मूलभूत साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रम को जोड़ नहीं सकते हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया में सोलरिस जैसी एनईएम 3.0 और संबंधित योजनाएं नेट मीटरिंग और प्रत्यक्ष छूट की अनुमति देकर रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। घरेलू उद्योग का आरोप है कि संबद्ध निर्यातकों ने महत्वपूर्ण रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की है और इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। प्राधिकारी इस कार्यक्रम को सैद्धांतिक रूप से प्रतिकार योग्य मानते हैं क्योंकि लाभ केवल उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

ix. कार्यक्रम 9: क्षेत्रीय प्रोत्साहन (सभा/मेलाका)

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

90. याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुरोध किया है कि वर्तमान योजना के तहत, दोनों निर्यातकों को क्षेत्रीय योजनाओं जैसे भूमि सब्सिडी, फास्ट-ट्रैक परमिट आदि के माध्यम से सरकारी स्तर की सहायता से लाभ हुआ है, और उपलब्ध सूचना के अनुसार भाग लेने वाले निर्यातकों में से एक को किमानिस में एक नई सौर ग्लास विनिर्माण सुविधा में 7.2 बिलियन रुपये के निवेश के माध्यम से योजना के तहत लाभ मिल रहा है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

91. मलेशिया सरकार ने विस्तृत क्षेत्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रलेखन प्रदान नहीं किया है, लेकिन फिर से साक्ष्य के लिए एएससीएम अपेक्षाओं और किसी भी अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करने से पहले उचित औचित्य की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा, दोनों निर्यातकों ने भी योजना का कोई विवरण प्रदान नहीं किया है और इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने इस तरह कोई लाभ प्राप्त किया है।

क. प्राधिकारी द्वारा जांच

92. घरेलू उद्योग का आरोप है कि सरकारी या कॉरिडोर स्तर (उदाहरण के लिए, सबा, मेलाका) पर क्षेत्रीय प्रोत्साहन योजनाएं नामित क्षेत्रों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि सब्सिडी, बुनियादी ढांचे का समर्थन और तेजी से ट्रैक पर परमिट प्रदान करती हैं। भाग लेने वाले निर्यातकों में से एक को किमानिस (सबा) में लगभग 7.2 बिलियन के निवेश वाले एक बड़े सौर ग्लास विनिर्माण सुविधा के संबंध में इस तरह के क्षेत्रीय प्रोत्साहनों से लाभ हुआ।

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया ने आर्थिक गलियारों और सरकारी योजनाओं को नामित किया है जिसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना है: (i) भूमि का बाजार से कम प्रावधान; (ii) सरकार द्वारा वित्त पोषित या सह-वित्त पोषित बुनियादी ढांचा; और (iii) सरलीकृत और शीघ्र परमिट देने की प्रक्रियाएं। वैचारिक रूप से, इस तरह के उपाय तीन-तत्व परीक्षण को पूरा कर सकते हैं यदि: (i) भूमि और बुनियादी ढांचे को अपर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रदान किया जाता है, जिसका अर्थ है राजस्व की हानि या सरकारी लागत की धारणा; (ii) निवेशक की पूंजी लागत कम हो जाती है, जिससे मापने योग्य लाभ मिलता है; और (iii) प्रोत्साहन विशेष रूप से नामित क्षेत्रों और विशेष परियोजनाओं के लिए हैं, और आम तौर पर राष्ट्रव्यापी सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विशिष्ट विधायी पाठ, ऋण करार और वास्तविक उपयोग के आंकड़े रिकॉर्ड में नहीं हैं। यद्यपि प्राधिकारी इस कार्यक्रम को सैद्धांतिक रूप से प्रतिकार योग्य मानते हैं, तथापि इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं उठाया जाता है।

x. कार्यक्रम 10: आपूर्ति श्रृंखला सुविधा कार्यक्रम

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

94. आवेदक ने अनुरोध किया है कि इस योजना के तहत मलेशिया सरकार स्थानीय विक्रेता विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू कंपनियों के लिए अवसर पैदा करना, आपूर्ति श्रृंखला में कमियों को दूर करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और सीमित देयता कंपनियों (एलएलसी) को अपनी विनिर्माण गतिविधियों को घरेलू कंपनियों को आउटसोर्स करने में सहायता करना, साथ ही घरेलू कंपनियों को विकसित और उन्नत करना है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मलेशियाई

निवेश विकास प्राधिकारी (एमआईडीए) इस कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए शिनयी एनर्जी को अपनी सहायता प्रदान कर रहे है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

95. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि उचित औचित्य के बिना मूल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) जांच का हिस्सा नहीं होने वाली कथित सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करना सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार (एएससीएम) के मौलिक सिद्धांतों और साक्ष्य सत्यापन के लिए स्थापित प्रक्रियात्मक आवश्य अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।

96. मलेशिया सरकार का विचार है कि डीजीटीआर को सभी सबूतों का पूरी तरह से सत्यापन करना चाहिए और केवल असमर्थित आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे उचित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के लिए एएससीएम की मौलिक अपेक्षाओं का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 11.2 के साक्ष्य मानकों को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रमों का जुड़ना जांच प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है और स्थापित डब्ल्यूटीओ दायित्वों का उल्लंघन करता है।

97. अनुच्छेद 11.2 के तहत, जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन-पत्र में (क) सब्सिडी और, यदि संभव हो, इसकी राशि; (ख) अनुच्छेद 15 के अर्थ के अभिप्राय से क्षति और (ग) सब्सिडी वाले आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य शामिल होगा"। जांच प्राधिकारी इन मूलभूत साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रम को जोड़ नहीं सकते हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

98. आपूर्ति श्रृंखला सुविधा कार्यक्रम एक एमआईडीए-संचालित पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू विक्रेताओं को अपग्रेड करना और बहुराष्ट्रीय कंपनी (एमएनसी)/एलएलसी आउटसोर्सिंग को घरेलू आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करना है। मलेशिया में रसद और आपूर्ति श्रृंखला उद्योग की कंपनियों को विभिन्न कर प्रोत्साहन और/या सीमा शुल्क छूट सहित एमआईडीए से सुविधा सेवाओं के लिए पात्र बताया गया है। तथापि, विशिष्ट विधायी ग्रंथ, पाठ करार और वास्तविक उपयोग के आंकड़े रिकॉर्ड पर नहीं हैं। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम को सिद्धांत रूप में प्रतिकार योग्य मानते है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत सहयशेगी निर्यातकों द्वारा लाभ नहीं उठाया जाता है।

xi. कार्यक्रम 11: समूह राहत

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

99. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि आयकर अधिनियम 1967 के तहत सभी स्थानीय निगमित निवासी कंपनियों को समूह राहत प्रदान की जाती है। यह संबद्ध कंपनियों को एक समूह इकाई के नुकसान को दूसरे के लाभ के खिलाफ विरुद्ध ऑफसेट करने की अनुमति देता है, दावेदार और सरेंडर करने वाली कंपनियों में से प्रत्येक के पास सामान्य शेयरों की प्रदत्त शेयर पूंजी 2.5 मिलियन से अधिक होनी चाहिए। दावेदार और सरेंडर करने वाली दोनों कंपनियों की लेखा अवधि समान होनी चाहिए। समूह में दावेदार और सरेंडर करने वाली कंपनियों की शेयरधारिता, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, 70% से कम नहीं होनी चाहिए। मालिकाना हक या विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को समूह राहत के उद्देश्य से नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

100. मलेशिया सरकार ने विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेजीकरण प्रदान नहीं किया है, लेकिन फिर से साक्ष्य के लिए एएससीएम अपेक्षाओं और किसी भी अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करने से पहले उचित औचित्य की आवश्यकता पर जोर दिया है। दोनों निर्यातकों ने इस योजना के तहत प्राप्त किसी भी लाभ से इनकार किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयकर अधिनियम, 1967 के तहत समूह राहत, संबंधित कंपनियों को एक समूह इकाई के नुकसान को दूसरे के लाभ के खिलाफ ऑफसेट करने की अनुमति देती है, जिससे समूह स्तर पर समग्र कर बोझ कम हो जाता है। समूह राहत व्यवस्था की सामान्य समझ और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अनुसार: (i) समूह राहत आम तौर पर शेयरधारिता और नियंत्रण सीमा को पूरा करने वाली आवासी कंपनियों के लिए

एक आम तौर पर उपलब्ध तंत्र है; (ii) यह निर्यात निष्पादन या किसी विशिष्ट क्षेत्र पर निर्भर नहीं है; और (iii) यह उद्योगों या क्षेत्रों के बीच भेदभाव नहीं करता है।

102. तीन-तत्व परीक्षण को लागू करना: (i) जबकि समूह राहत में राजस्व की कुछ मात्रा शामिल हो सकती है, यह विशिष्ट उद्यमों या उद्योगों तक सीमित प्रतीत नहीं होता है; (ii) यह समूह कंपनियों के लिए आयकर प्रणाली की एक सामान्य विशेषता है; और (iii) इसलिए, प्रतिपूर्ति के लिए विशिष्टता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

103. अत: प्राधिकारी इस कार्यक्रम को इस जांच के प्रयोजनों के लिए प्रतिकार योग्य नहीं मानते है।

xii. कार्यक्रम 12: औद्योगिक भवन भत्ता (आईबीए)

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

104. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आईबीए उन कंपनियों को दिया जाता है जो निर्माण या भवन की खरीद पर पूंजीगत व्यय करती हैं जिसका उपयोग विनिर्माण, कृषि, खनन, बुनियादी ढांचा सुविधाएं, अनुसंधान, अनुमोदित सेवा परियोजनाओं और पर्यटन मंत्रालय के साथ पंजीकृत होटलों सहित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

105. मलेशिया सरकार ने विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेजीकरण उपलब्ध नहीं कराया है, लेकिन फिर से साक्ष्य के लिए एएससीएम अपेक्षाओं और किसी भी अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करने से पहले उचित औचित्य की आवश्यकता पर जोर दिया है। दोनों निर्यातकों ने इस योजना के तहत प्राप्त किसी भी लाभ से इनकार कर किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग भवन भत्ता ("आईबीए") से संबंधित दावा घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य शब्दों में किया गया है, जिसमें किसी भी लेनदेन-विशिष्ट या कंपनी-विशिष्ट साक्ष्य को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध निर्यातकों ने वास्तव में उक्त योजना का लाभ उठाया है।

107. यह भी नोट किया जाता है कि मलेशिया सरकार ने भाग लेने वाले निर्यातकों के संबंध में कथित प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत परिचालन ढांचे, पात्रता शर्तों, अनुदान तंत्र या वास्तविक संवितरण/लाभों को प्रदर्शित करने वाले कोई विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। निर्यातकों ने अपनी ओर से, आईबीए योजना के तहत किसी भी लाभ की प्राप्ति से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, और ऐसे इनकार का खंडन करने के लिए कोई विपरीत साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा लाभ की वास्तविक प्राप्ति को प्रमाणित करने वाली सत्यापन योग्य सूचना के अभाव में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि कथित आईबीए योजना के परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान भाग लेने वाले निर्यातकों को कोई प्रतिकार योग्य सब्सिडी मिली है। तदनुसार, आईबीए से संबंधित दावे को वर्तमान जांच के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाता है।

xiii. कार्यक्रम 13: संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

108. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पूंजी भत्ता व्यवसाय के लिए निश्चित परिसंपत्तियों की टूट-फूट के लिए राहत है। अर्हता प्राप्त करने के लिए, व्यय प्रकृति में पूंजीगत होना चाहिए और व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अर्हता प्राप्त व्यय (क्यूई) में व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जैसे कि संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, फिटिंग, मोटर वाहन आदि। जहां किसी परिसंपत्ति को किराए पर खरीद की अवधि पर अधिग्रहित किया जाता है, तो एक विशेष आधार अवधि के लिए क्यूई उस आधार अवधि के दौरान किए गए पूंजी पुनर्भुगतान की राशि पर आधारित होता है। प्रारंभिक भत्ता पूंजीगत व्यय किए जाने के समय परिसंपत्ति की लागत के आधार पर 20% पर तय किया जाता है। वार्षिक भत्ता परिसंपत्ति की मूल लागत के आधार पर हर साल दिया जाने वाला एक फ्लैट दर है और तदनुसार भिन्न होता है।

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. मलेशिया सरकार ने विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेजीकरण उपलब्ध नहीं कराया है, लेकिन फिर से साक्ष्य के लिए एएससीएम अपेक्षाओं और किसी भी अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करने से पहले उचित औचित्य की आवश्यकता पर जोर दिया है। दोनों निर्यातकों ने इस योजना के तहत प्राप्त किसी भी लाभ से इनकार किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

110. प्राधिकारी नोट करते है कि संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ते से संबंधित दावा घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य शब्दों में किया गया है, जिसमें किसी भी लेनदेन-विशिष्ट या कंपनी-विशिष्ट साक्ष्य को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि जांच की अवधि के दौरान प्रतिभागी निर्यातकों ने वास्तव में उक्त योजना का लाभ उठाया है या लाभान्वित हुए हैं।

111. यह भी नोट किया जाता है कि मलेशिया सरकार ने भाग लेने वाले निर्यातकों के संबंध में कथित प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत परिचालन ढांचे, पात्रता शर्तों, अनुदान तंत्र या वास्तविक संवितरण/लाभों को प्रदर्शित करने वाले कोई विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। निर्यातकों ने अपनी ओर से इस योजना के तहत किसी भी लाभ की प्राप्ति से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, और इस तरह के खंडन का खंडन करने के लिए कोई विपरीत साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा लाभ की वास्तविक प्राप्ति को प्रमाणित करने वाली सत्यापन योग्य सूचना के अभाव में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि इस योजना के परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान भाग लेने वाले निर्यातकों को कोई प्रतिकार योग्य सब्सिडी मिली है। तदनुसार, इस योजना से संबंधित दावे को वर्तमान जांच के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाता है

xiv. कार्यक्रम 14: मलेशियाई ब्रांड के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

112. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत, घरेलू स्तर पर स्थानीय ब्रांड उत्पादों के विज्ञापन पर किए गए व्यय को दोहरी कटौती की अनुमति दी जाती है, अर्थात कुछ गतिविधियों पर किए गए खर्चों को कर योग्य लाभ के मुकाबले दो बार सेट ऑफ किया जा सकता है। स्थानीय ब्रांड का स्वामित्व मलेशियाई ब्रांड नाम के पंजीकृत मालिक के पास 50% से अधिक होना चाहिए, जिसका स्वामित्व स्थानीय रूप से निगमित कंपनी के पास होना चाहिए जिसमें कम से कम 70% मलेशियाई स्वामित्व और मलेशिया या विदेशों में पंजीकृत हो। कटौती केवल एक आकलन वर्ष में एक कंपनी द्वारा ही दावा की जा सकती है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

क) निवेश अधिनियम, 1986 का संवर्धन

ख) आयकर निर्यात संवर्धन नियमावली, 1986

ग) मलेशिया के अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड सार्वजनिक विनियमन संख्या 1/2013

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

113. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि मलेशियाई ब्रांड नाम के सामानों के विज्ञापन में अर्हता प्राप्त विज्ञापनों के लिए व्यय, व्यवसाय से समायोजित आय प्राप्त करने में दोहरी कटौती के लिए पात्र है। आयकर (मलेशियाई ब्रांड नाम के सामानों पर विज्ञापन व्यय के लिए कटौती) नियमावली, 2002 साक्ष्य में दिए गए हैं। आवेदक कंपनियों को फॉर्म भरकर प्रोत्साहन का दावा करने और मलेशियाई ब्रांड के सामानों के विज्ञापन के लिए मलेशिया के भीतर किए गए खर्चों से संबंधित व्यावसायिक रसीदों की प्रतियों के साथ दावों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। मूल सहायक दस्तावेजों को आईआरबी द्वारा ऑडिट उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा रखा जाना चाहिए। जिस वित्तीय वर्ष (आधार अवधि) में व्यय किया जाता है, उसके लिए वार्षिक कर विवरणी में दावा किया जा सकता है। जांच के तहत कंपनियां कटौती का दावा करने के लिए पात्र होंगी यदि वे मानदंडों को पूरा करती हैं। सहायता कर योग्य आय से कटौती है। कटौती को अग्रणीत जा सकता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आयकर (मलेशियाई ब्रांड नाम सामानों पर विज्ञापन व्यय के लिए कटौती) नियमावली 2002 द्वारा शासित है। इस कार्यक्रम के तहत, मलेशियाई ब्रांड के विज्ञापन में किया गया व्यय व्यवसाय आय से दोहरी कटौती के लिए पात्र है। इस दोहरी कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कंपनी के पास 70% मलेशियाई इक्विटी होनी चाहिए और ब्रांड नाम निर्यात गुणवत्ता के सामान का होना चाहिए। कार्यक्रम राजस्व फोरगॉन के रूप में वित्तीय योगदान के लिए प्रदान करता है, जो अन्यथा देय है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उस उद्यम के लिए उपलब्ध है जो मलेशियाई ब्रांड के विज्ञापन पर खर्च करता है। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

xv. कार्यक्रम 15: पूर्वी तट आर्थिक गलियारे में विनिर्माण से संबंधित सेवा के लिए प्रोत्साहन

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

115. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारे में विनिर्माण और विनिर्माण से संबंधित सेवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना एक प्रतिकार योग्य सब्सिडी है, क्योंकि इसमें कर प्रोत्साहन, आयकर छूट, स्टाम्प शुल्क छूट और अन्य राजकोषीय रियायतों के रूप में मलेशिया सरकार द्वारा वित्तीय योगदान शामिल है। यह योजना क्षेत्र-विशिष्ट है और ईईसी के भीतर स्थित उद्यमों तक सीमित है, जिससे विशिष्टता का परीक्षण पूरा होता है। इसके अलावा, प्रोत्साहन का उद्देश्य चयनित और कृषि आधारित उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

116. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि उचित औचित्य के बिना मूल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) जांच का हिस्सा नहीं रहे कथित सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करना सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार (एएससीएम) के मौलिक सिद्धांतों और साक्ष्य सत्यापन के लिए स्थापित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।

117. मलेशिया सरकार का विचार है कि डीजीटीआर को सभी सबूतों का पूरी तरह से सत्यापन करना चाहिए और केवल असमर्थित आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे उचित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के लिए एएससीएम की मौलिक अपेक्षाओं का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 11.2 के साक्ष्य मानकों को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रमों का जुड़ना जांच प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है और स्थापित डब्ल्यूटीओ दायित्वों का उल्लंघन करता है।

118. अनुच्छेद 11.2 के तहत, जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन-पत्र में (क) सब्सिडी और, यदि संभव हो, इसकी राशि; (ख) अनुच्छेद 15 के अर्थ के अभिप्राय से क्षति और (ग) सब्सिडी वाले आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य शामिल होगा"। जांच प्राधिकारी इन मूलभूत साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किए बिना नई सब्सिडी कार्यक्रम को जोड़ नहीं सकते हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

119. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के साथ-साथ मलेशिया सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि ईईसी प्रोत्साहन योजना भौगोलिक रूप से सीमित प्रतीत होती है, लेकिन इसके प्रतिकार योग्य प्रकृति का निर्धारण करने के लिए जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के निर्यातकों को एक वित्तीय योगदान, लाभ के प्रदान और विशिष्टता के साथ-साथ एक मात्रात्मक लाभ को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। प्राधिकारी नोट करते है कि योजना के तहत लाभ की वास्तविक प्राप्ति और प्रयोग का निष्पादन करने या संबद्ध सामानों को किसी कथित लाभ के स्पष्ट संबंध और आवंटन को सिद्ध करने वाली कोई सत्यापित, निर्यातक-विशिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि इस योजना के परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान प्रतिभागी निर्यातकों को कोई प्रतिकार योग्य सब्सिडी मिली है। तदनुसार, इस योजना से संबंधित दावे को वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है।

xvi. कार्यक्रम 16: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर वापसी

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

120. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत, भुगतान किए गए आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर वापसी, यदि पुर्जे, कच्ची सामग्री या पैकेजिंग सामग्री का उपयोग अधिनियमों में निर्धारित शर्तों के आधार पर एक वर्ष के भीतर निर्यात के लिए सामानों के निर्माण में किया जाता है, तो एक निर्माता द्वारा दावा किया जा सकता है। कार्यक्रम की मौजूगी के प्रमाण के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

क) सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 99

ख) बिक्री कर अधिनियम 1972 की धारा 29

ग) उत्पाद शुल्क अधिनियम 1976 की धारा 19

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

121. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि रॉयल मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग (आरएमसीडी) द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर प्रशासित ड्रॉबैक कार्यक्रम, उन सामानों पर आयात शुल्क की वापसी के लिए प्रावधान करता है जिन्हें बाद में फिर से निर्यात किया जाता है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 93, 95 और 99 के तहत सत्यापन योग्य आयात और निर्यात दस्तावेज द्वारा समर्थित आवेदन पर सख्ती से काम करता है।

122. मलेशिया सरकार सरकार का यह भी अनुरोध है यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार के अनुबंध I, II और III के तहत अतिरिक्त छूट सिद्धांत को लागू करते हुए अपवादों के अंतर्गत आता है। इस संबंध में, यह सुनिर्धारित है, जिसमें यूरोपीय संघ – पाकिस्तान से कुछ पीईटी पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क में अपीलीय निकाय और डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा निर्णय भी शामिल हैं कि शुल्क वापसी योजनाएं केवल शुल्क उसी सीमा तक प्रतिकार योग्य हैं, जहां तक वास्तव में प्रोद्भूत शुल्क अतिरिक्त दिए गए हैं और केवल जहां उचित साक्ष्य आधार हैं।

123. मलेशिया सरकार और प्रतिभागी निर्यातकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच की अवधि के दौरान कार्यक्रम के तहत कोई लाभ नहीं उठाया गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

124. ड्रॉबैक कार्यक्रम कथित तौर पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 99, बिक्री कर अधिनियम, 1972 की धारा 29 और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1976 की धारा 19 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार, निर्धारित अवधि के भीतर निर्यातित सामान के निर्माण में प्रयुक्त पुर्जों, कच्ची सामग्री या पैकेजिंग सामग्री पर भुगतान किए गए आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति देता है, जिससे कार्यक्रम की मौजूदगी सिद्ध होती है।

125. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कार्यक्रम का प्रशासन रॉयल मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग (आरएमसीडी) द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाता है और केवल पूर्ण आयात और निर्यात दस्तावेज़ों के जमा और सत्यापन पर संचालित होता है। सैद्धांतिक रूप से, ड्रॉबैक कार्यक्रम केवल तभी प्रतिकार योग्य हो सकता है जब एससीएम करार के अनुबंध I, II और III के संदर्भ में वास्तव में प्रोद्भूत शुल्कों से अधिक छूट हो, और उचित साक्ष्य के अधीन हो। वर्तमान मामले में, दोनों संबद्ध निर्यातकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान ड्रॉबैक कार्यक्रम के तहत कोई लाभ नहीं उठाया या प्राप्त नहीं किया, और ऐसे बयानों का खंडन करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कार्यक्रम वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए प्रतिकार योग्य नहीं है।

xvii. कार्यक्रम 17: बिक्री कर छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

126. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कारोबार करने की लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने बिक्री कर से छूट दी है। यह कार्यक्रम आरएमसीडी द्वारा अनुमोदित और प्रशासित है और 1.9.2018 में स्थापित किया गया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस योजना के तहत 100,000 आरएम से कम के वार्षिक बिक्री कारोबार वाले निर्माताओं को लाइसेंस से छूट दी गई है और इस प्रकार उनके उत्पादन पर बिक्री कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। हालांकि, ये निर्माता लाइसेंस प्राप्त करने और इसके बजाय अपने इनपुट पर बिक्री कर छूट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

127. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि बिक्री कर छूट योजना बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश, 2018 के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों और निर्माताओं को स्थानीय रूप से निर्मित सामानों के आयात और खरीद पर बिक्री कर के भुगतान से राहत प्रदान करती है। छूटों को तीन अनुसूचियों के तहत संरचित किया गया है: अनुसूची क में निर्धारित मानदंडों और शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों की श्रेणियां शामिल हैं; अनुसूची ख में विशिष्ट गैर-कर योग्य सामानों के निर्माताओं को शामिल किया गया है, जो गैर-कर योग्य सामानों के निर्माण में अकेले और सीधे उपयोग की जाने वाली सभी सामानों (पेट्रोलियम को छोड़कर) के अधिग्रहण पर छूट प्रदान करते हैं; और अनुसूची ग में कर योग्य सामानों के पंजीकृत निर्माताओं को शामिल किया गया है, जो कर योग्य सामानों के निर्माण में अकेले और सीधे उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री, घटकों और पैकेजिंग सामग्री पर छूट प्रदान करते हैं। कार्यक्रम को रॉयल मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग (आरएमसीडी) द्वारा अनुमोदित और प्रशासित किया जाता है और संबंधित कंपनियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर पात्रता के साथ आवेदनों के आधार पर संचालित होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जांच के तहत किसी भी कंपनी ने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, न ही इसका लाभ उठाया और न ही इसे प्राप्त किया।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के साथ-साथ मलेशिया सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम का प्रशासन रॉयल मलेशियाई कस्टम विभाग द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम उन व्यक्तियों या निर्माताओं को बिक्री कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है जो पात्रता मानदंडों और शर्तों को पूरा करते हैं। यह छूट संयंत्र और मशीनरी के आयात और घरेलू बाजार में स्थानीय रूप से निर्मित सामानों की खरीद पर है। लाभ राजस्व के रूप में है क्योंकि यह निर्यातकों को बिक्री कर की छूट प्रदान करता है जो अन्यथा देय है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उद्यमों के लिए उपलब्ध है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य माना जाता है।

129. **शिनयी सोलर:** निर्यातक द्वारा अपने उत्तर में, साथ ही डेस्क सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की गई सूचना और दस्तावेज दर्शाते हैं कि निर्यातक ने कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की आवश्यकता है।

130. **एसबीएच किबिंग एसडीएन बीएचडी:** निर्यातक द्वारा अपने उत्तर में, साथ ही डेस्क सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की गई सूचना और दस्तावेज दर्शाते हैं कि निर्यातक ने कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की आवश्यकता है।

xviii. कार्यक्रम 18: आउटसोर्सिंग विनिर्माण गतिविधियों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

131. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत, व्यवसाय करने की लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, कम से कम 60% मलेशियाई इक्विटी वाले मलेशियाई ब्रांडों को आयात शुल्क और बिक्री कर छूट दी जाती है जो विनिर्माण गतिविधियों को आउटसोर्स करते हैं। स्थानीय/विदेश में उनके संविदात्मक निर्माताओं द्वारा तैयार उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क और बिक्री कर छूट और उनके अनुबंध निर्माताओं से अर्ध-तैयार माल पर आयात शुल्क और बिक्री कर छूट जो उनके स्थानीय अनुबंध निर्माताओं द्वारा तैयार उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है।

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि कार्यक्रम आउटसोर्सिंग विनिर्माण गतिविधियों के लिए कच्चे माल, घटकों और/या अपरिष्कृत उत्पादों पर आयात शुल्क छूट प्रदान करता है। शुल्क छूट के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें वित्त मंत्रालय, एमआईटीआई, आरएमसीडी, एमआईडीए और आईपीसी के प्रतिनिधियों से युक्त सदस्य शामिल हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी निर्माताओं को योजना से लाभ होगा और अधिकारी विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन का अनुमान नहीं है।

133. यह भी कहा गया है कि यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार के अनुबंध I, ii और iii के प्रावधानों के अनुरूप है। छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए:

क) आयातित कच्चा माल और घटक जिनका उपयोग शून्य आयात शुल्क के साथ तैयार उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है।

ख) अर्ध-तैयार उत्पादों को अनुबंध निर्माताओं से विदेशों से आयात किया जाता है और स्थानीय अनुबंध निर्माताओं द्वारा तैयार उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम का प्रशासन मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम आउटसोर्सिंग विनिर्माण गतिविधियों के लिए कच्चे माल, घटकों और/या अर्ध-तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क छूट प्रदान करता है। कच्चे माल जो निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं और अर्ध-तैयार माल जो स्थानीय निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुबंध निर्माताओं से आयात किए जाते हैं, इस छूट के लिए योग्य हैं। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य माना जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

xix. कार्यक्रम 19: हिस्से पुर्जो और खपत योग्य वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

135. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है किया है कि चूंकि सरकार की नीति है कि विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे उपयोग किए जाने वाले हिस्से पुर्जों और खपत योग्य वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाएगा जहां आयात शुल्क शून्य है और स्थानीय रूप से उत्पादन नहीं किया जाता है, जहां आयातित हिस्से पुर्जों और खपत योग्य वस्तुएं कर योग्य हैं लेकिन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं, वहां कर छूट-राजस्व छोड़ दिया जाता है। आयात शुल्क और बिक्री कर पर छूट दी गई है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए के प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहनों पर भरोसा किया है।

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

136. मलेशिया सरकार का कहना है कि कार्यक्रम योग्य निर्माता को हिस्से पुर्जों और खपत योग्य वस्तुओं पर आयात शुल्क छूट प्रदान करता है। एमआईडीए निर्माता की स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक पत्र जारी करता है। कार्यक्रम में कच्चे माल, घटकों और/ या अर्ध-तैयार उत्पादों पर आउटसोर्सिंग विनिर्माण गतिविधियों के लिए आयात शुल्क छूट का मूल्यांकन शामिल था। शुल्क छूट संबंधी एक समिति गठित की गई है जिसमें वित्त मंत्रालय, एमआईटीआई, आरएमसीडी, एमआईडीए और आईपीसी के प्रतिनिधियों से युक्त सदस्य शामिल हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी निर्माताओं को इस योजना से लाभ होगा और एमआईडीए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करता है। कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन का अनुमान नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप है (सब्सिडी परिभाषा का अपवाद)। इस कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले कानून और विनियम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 में निहित हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 द्वारा शासित है। यह हिस्से पुर्जो और खपत योग्य सामानों पर आयात शुल्क छूट प्रदान करता है। कार्यक्रम का प्रशासन मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकारी (एमआईडीए) द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम राजस्व अग्रिम के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है, जो

अन्यथा देय है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ मानदंडों की पूर्ति के अधीन है। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिए जाते हैं।

xx. कार्यक्रम 20: मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

138. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि सरकार की नीति है कि विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे उपयोग किए जाने वाले और स्थानीय रूप से उत्पादित नहीं किए जाने वाले मशीनरी और उपकरणों पर कर नहीं लगाया जाएगा, इसलिए आयातित मशीनरी और उपकरण पर कर छूट-राजस्व का त्याग दिया जाता है, लेकिन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। आयात शुल्क और बिक्री कर पर पूर्ण छूट दी गई है। स्थानीय रूप से खरीदी गई मशीनरी और उपकरणों पर लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण भंडार, बाउंडेड भंडार या मुक्त क्षेत्र से बिक्री कर पर पूर्ण छूट दी जाती है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए के प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहनों पर भरोसा किया है।

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

139. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि कार्यक्रम योग्य निर्माता को मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क छूट प्रदान करता है। एमआईडीए निर्माता की स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक पत्र जारी करता है। इसके बाद निर्माता छूट का दावा करता है। छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, मशीनरी और उपकरण नए, अप्रयुक्त और अनुमोदित निर्माता के परिसर में तैयार उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे उपयोग किए जाने चाहिए। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी निर्माता इस योजना से लाभान्वित होंगे और एमआईडीए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करता है। कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। उनका यह भी अनुरोध है कि यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार (सब्सिडी परिभाषा का अपवाद) के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप है । इस कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले कानून और विनियम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 में निहित हैं।

140. जांच के तहत कंपनियां पात्रता मानदंडों के अनुरूप थीं जो एमआईडीए के क्षेत्र में हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 द्वारा शासित है। यह योग्य निर्माताओं को नए और अप्रयुक्त मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क छूट प्रदान करता है। योग्य निर्माता को मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क छूट का मूल्यांकन करने में शामिल है। यह कार्यक्रम मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकारी द्वारा प्रशासित किया जाता है।

142. कार्यक्रम राजस्व परित्याग के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है, जो अन्यथा देय है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उद्यमों तक सीमित है जो विनिर्माण गतिविधि के लिए नई मशीनरी और उपकरण आयात करते हैं। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य नोट किया जाता है।

143. **शिनयी सोलर:** इसने कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं उठाया है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए शिनयी सोलर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

144. **एसबीएच किबिंग एसडीएन बीएचडी**: निर्यातक द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में, साथ ही डेस्क सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की गई सूचना और दस्तावेज दर्शाते हैं कि निर्यातक ने कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की आवश्यकता है।

xxi. कार्यक्रम 21: कच्ची सामग्री/घटकों पर आयात शुल्क से छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

145. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत, कच्चे माल/घटकों पर आयात शुल्क से पूर्ण छूट आम तौर पर दी जाती है, बशर्ते कि कच्चे माल/घटक स्थानीय रूप से उत्पादित न हों या यदि स्थानीय रूप से उत्पादित हों, तो वे स्वीकार्य गुणवत्ता और कीमत के न हों। यह इस बात की परवाह किए बिना है कि तैयार

उत्पाद निर्यात या घरेलू बाजार के लिए हैं या नहीं। पात्रता यह है कि कंपनियां विनिर्माण गतिविधियों में शामिल होनी चाहिए।

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

146. मलेशिया सरकार ने उल्लेख किया है कि इस कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले कानून और विनियम सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) में निहित हैं। यह योग्य निर्माता को कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क छूट प्रदान करता है। शुल्क छूट संबंधी एक समिति गठित की गई है जिसमें वित्त मंत्रालय, एमआईटीआई, आरएमसीडी और एमआईडीए के प्रतिनिधियों से बने सदस्य शामिल हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी निर्माताओं को इस योजना से लाभ होगा और एमआईडीए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार (सब्सिडी परिभाषा का अपवाद) के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप हैं। जांचाधीन कंपनियां पात्रता मानदंडों के अनुरूप थीं जो एमआईडीए के क्षेत्र में हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 14(2) द्वारा शासित है। इस कार्यक्रम में उस कच्ची सामग्री/संघटक पर योग्य विनिर्माता को आयात शुल्क छूट दी जाती है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। कार्यक्रम राजस्व फोरगॉन के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है, जो अन्यथा देय है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह एक उद्यम तक सीमित है जो कच्चे माल का उपयोग करता है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य के रूप में नोट किया गया है। हालांकि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

xxii. कार्यक्रम 22: निर्यात के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

148. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के कर कटौती उन खर्चों के लिए निर्यातकों को दी जाती है, जिनका उद्देश्य निर्यातों का संवर्धन करना और विदेशों में सामान की आपूर्ति करना, सेवाओं के निर्यात के संवर्धन के लिए मलेशिया से किसी मीडिया में प्रचार और विज्ञापन करना, सेवाओं के संवर्धन के प्रयोजन के लिए विदेश में कार्यालय के रखरखाव की लागत पर खर्च करना है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप मे, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 41
- आयकर निर्यात संवर्धन नियमावली 1986
- डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/292
- डब्ल्यूटीओ-अधिसूचना-जी/एससीएम/एन/3/एमवाईएस-1995
- मलेशिया से यूएस कार्बन स्टील वायर रॉड

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

149. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि यह कार्यक्रम जिसका प्रावधान नियमावली 1986 के नियम 4(2) के साथ पठित निवेश संवर्धन अधिनियम (पीआईए), 1986 (अधिनियम 327) की धारा 41 में किया गया है, अवसर लेने के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से और प्रमुख रूप से आधार अवधि में किए गए खर्चों के संबंध में सभी आवासी ट्रेडिंग, विनिर्माण या कृषि कंपनियों के लिए या मलेशियाई विनिर्मित सामानों या कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मांग सृजित करने या बढ़ाने पर किए गए खर्चों के लिए लागू है। कार्यक्रम में कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं है। कटौती अग्रेणीत की जा सकती है।

150. यह भी अनुरोध किया गया है कि आवेदक कंपनियों को फॉर्म भरकर प्रोत्साहन के लिए दावा करना होगा और विज्ञापन, यात्रा और संबंधित निर्यात प्रचार व्यय के लिए विदेशों में किए गए खर्चों से संबंधित व्यावसायिक रसीदों की प्रतियों के साथ दावों को प्रमाणित करना होगा। मूल सहायक दस्तावेजों को आईआरबी द्वारा ऑडिट उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा रखा जाना चाहिए।

151. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने के मामले में, कंपनियों को मैट्रेड से अनुमोदन पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

152. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम निवेश संवर्धन अधिनियम (पीआईए) 1986 (अधिनियम 327) की धारा 41 और आयकर (निर्यात संवर्धन) नियमावली 1986 के नियम 4(2) द्वारा शासित है। इस कार्यक्रम के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए खर्चों के लिए विनिर्माण, व्यापार और कृषि गतिविधियों में शामिल उद्यम को आय से दोहरी कटौती उपलब्ध है। निर्यात की बढ़ती मांग के लिए किसी कंपनी द्वारा किए गए खर्चों को दोहरी कटौती के लिए अनुमति दी जाती है।

153. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में राजस्व परित्याग के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है, जो अन्यथा देय है, और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। इसका लाभ दोहरी कटौती के बाद भुगतान की गई आयकर की राशि और ऐसी दोहरी कटौती के अभाव में देय आयकर की राशि के बीच का अंतर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात निष्पादन पर निर्भर है और निर्यात संवर्धन गतिविधि में लगे उद्यम तक ही सीमित है। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य माना जाता है। हालाँकि, इस कार्यक्रम के तहत सहयोगी निर्यातकों द्वारा लाभ नहीं उठाया जाता है।

xxiii. कार्यक्रम 23: निर्यात कार्गो को बढ़ावा देने के लिए दोहरी कटौती

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

154. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत एक निर्यातक निर्यात कार्गो पर प्रीमियम बीमा के लिए कर योग्य आय से कटौती कर सकता है और कर बीमा के लिए क्षेत्रीय कर कटौती कर सकता है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

क) निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986

ख) आयकर निर्यात संवर्धन नियमावली 1986

ग) कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन

घ) प्राधिकारी के अन्य जांच परिणाम

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

155. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि मलेशिया से निर्यात किए गए माल के बीमा पर प्रीमियम लेने वाले व्यक्ति को दोहरी कटौती की अनुमति है, बशर्ते कि जोखिमों का बीमा मलेशिया में निगमित बीमा कंपनी के साथ किया गया हो। भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम 1967 की धारा 33 के अनुसार होना चाहिए। सहायता कर योग्य आय से कटौती है। कटौती को अग्रणीत किया जा सकता है।

156. इस कार्यक्रम को 2016 से रद्द कर दिया गया है। आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) (निरसन) नियमावली 2012 को प्रमाण के रूप में दिया गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

157. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) नियमावली 1995 द्वारा शासित था और आयकर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) (निरसन) नियमावली 2012 को 2016 से हटा दिया गया है।

xxiv. कार्यक्रम सं. 24: बढ़े हुए निर्यात के लिए भत्ता

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

158. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह कार्यक्रम आयकर अधिनियम 1967 की धारा 154(1) और आयकर (बढ़े हुए निर्यात के लिए भत्ता) नियमावली, 1999 के नियम 3 और आयकर (बढ़े हुए निर्यात के लिए भत्ता) संशोधन नियमावली 2003 के तहत कंपनियों को प्रदान किए गए कर प्रोत्साहन का रूप है। कोई निर्यातक बढ़े

हुए निर्यात के लिए कर योग्य आय से 70% कर कटौती का लाभ ले सकता है। साथ ही, यदि उक्त भत्ते का उपयोग अर्जित वर्ष के दौरान नहीं किया जाता है तो इसे अगले मूल्यांकन वर्ष में अग्रेणीत किया जा सकता है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

क) निवेश संवधर्न अधिनियम, 1986

ख) आयकर अधिनियम 1967

ग) सीमा शुल्क अधिनियम 1967

घ) बिक्री कर अधिनियम 1972

ड.) उत्पाद शुल्क अधिनियम 1976

च) मुक्त व्यापार क्षेत्र अधिनियम 1990

ख. मलेशिया सरकार /अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

159. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि एक आवासी विनिर्माण कंपनी या कृषि कंपनी जो निर्मित उत्पादों या कृषि उत्पादों का निर्यात करती है, उसे निर्यात में वृद्धि के लिए भत्ता दिया जाना होता है। यह सहायता कर योग्य आय से छूट है। यह भत्ता अग्रेणीत किया जा सकता है। कार्यक्रम में कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं है। आयकर (बढ़े हुए निर्यात के लिए भत्ता) नियमावली 1999 साक्ष्य के रूप में दी गई है। नियमावली में निम्नलिखित परिभाषाएँ निहित हैं:

क. कृषि उपज का अर्थ है ताजे और सूखे फल, ताजे और सूखे फूल, सजावटी पौधे और सजावटी मछली, जमे हुए कच्चे झींगे या झींगा, जमे हुए पके और छिले हुए झींगे और जमे हुए कच्चे मवेशी, मछली और स्क्विड;

ख. निर्यात का अर्थ सीधे निर्यात से है जिसमें मुक्त औद्योगिक क्षेत्रों और लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण गोदामों को बिक्री शामिल नहीं है;

ग. मूल्य वर्धित का अर्थ है कच्चे माल की कुल लागत से कम कारखानागत कीमत पर सामानों की बिक्री कीमत; और

घ. बढ़े हुए निर्यात का मूल्य अर्थ आधार अवधि में निर्यात किए गए उत्पादों के फ्री-ऑन-बोर्ड (एफओबी) मूल्य और तुरंत पहले की अवधि के मूल्य के बीच का अंतर है। एफओबी मूल्य में माल भाड़ा शुल्क और बीमा लागत शामिल नहीं होगी।

160. भत्ते का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

क. निर्मित उत्पाद

- कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के बढ़े हुए निर्यातों के मूल्य का 10% जहां निर्यातित उत्पादों ने कम से कम 30% का मूल्य वर्धन प्राप्त किया;
- कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के बढ़े हुए निर्यातों के मूल्य का 15% जहां निर्यातित उत्पादों ने कम से कम 50% मूल्य वर्धन प्राप्त किया।

ख. कृषि उत्पाद

- कंपनी द्वारा कृषि उत्पादों के बढ़े हुए निर्यातों के मूल्य का 10%

161. कंपनी की सांविधिक व्यापार आय के सत्तर प्रतिशत के लिए भत्ता दिया जाएगा। सेट ऑफ न किए गए किसी भी निर्यात भत्ते को भावी वर्षों में सांविधिक आय के सत्तर प्रतिशत के लिए सेट ऑफ होने हेतु अग्रेणीत किया जाएगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

162. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के साथ-साथ मलेशिया सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि एक आवासी विनिर्माण कंपनी या कृषि कंपनी जो निर्मित उत्पादों या कृषि उत्पादों का निर्यात करती है, उसे निर्यात में वृद्धि के लिए भत्ता दिया जाना होता है। भत्ता कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के मूल्य के 10% या 15% के बराबर है। सांविधिक व्यवसाय आय के 70% के लिए भत्ता दिया जाएगा।

163. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि इस कार्यक्रम में उस राजस्व परित्याग के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है, जो अन्यथा देय है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात निष्पादन पर निर्भर है। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार होने के रूप में नोट किया गया है। हालांकि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

xxv. कार्यक्रम 25: मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए कर छूट

ख. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

164. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मलेशिया 17 मुक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों और 18 मुक्त औद्योगिक क्षेत्रों से युक्त एक व्यापक मुक्त क्षेत्र व्यवस्था संचालित करता है, जो स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण राजकोषीय रियायतें प्रदान करके निर्यातोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मुक्त क्षेत्र अधिनियम, 1990 की धारा 4 के तहत, किसी भी विवरण की वस्तुओं और सेवाओं (जब तक कि विशेष रूप से निषिद्ध न हो) को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या सेवा कर के भुगतान के बिना एक मुक्त क्षेत्र के भीतर लाया, उत्पादित, निर्मित या प्रदान किया जा सकता है। ये सांविधिक छूटें सरकार द्वारा परित्यक्त राजस्व के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय अंशदान हैं जो अन्यथा देय हो, जिससे ऐसे क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले उद्यमों को लाभ होगा।

165. यह भी उल्लेख किया गया है कि पोर्ट क्लैंग जैसे प्रमुख केंद्रों सहित मुक्त वाणिज्यिक क्षेत्र, कंपनियों को अप्रत्यक्ष करों से मुक्त कच्चे माल, घटकों, उपकरणों और मशीनरी का आयात करने की अनुमति देते हैं, जिससे इनपुट लागत काफी कम हो जाती है और इन क्षेत्रों में स्थित निर्यातोन्मुख उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाती है। मुक्त क्षेत्रों के भीतर कर-मुक्त आयात और उत्पादन तक पहुंच, मुक्त क्षेत्र अधिनियम के तहत स्थान और अनुमोदन पर निर्भर है, जो इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले उद्यमों के लिए वास्तविक विशिष्टता को दर्शाता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग का तर्क है कि मुक्त क्षेत्र व्यवस्था एससीएम करार के अभिप्राय से एक सब्सिडी है, क्योंकि इसमें सरकार के राजस्व का परित्याग शामिल है, एक मापनीय लाभ प्रदान करता है, और मुक्त वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमों के एक परिभाषित समूह तक सीमित है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

166. मलेशिया सरकार ने विस्तृत क्षेत्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रम दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं बल्कि साक्ष्य के लिए एएससीएम अपेक्षाओं और किसी भी अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों को शामिल करने से पहले उचित औचित्य की आवश्यकता पर जोर दिया है। निर्यातकों ने इस योजना के तहत प्राप्त किसी भी लाभ से इनकार कर दिया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

167. प्राधिकारी ने मलेशिया सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी, प्रकृति और मात्रा निर्धारण के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच की है, जिसमें राजकोषीय प्रोत्साहन और कर संबंधी उपाय शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अनुरोध अन्य बातों के साथ-सा इस आधार पर मोटे तौर पर कथित कार्यक्रम के प्रतिकार योग्य विशेषता का विरोध करते हैं कि ये उपाय किसी वित्तीय योगदान में शामिल नहीं है या कोई मापनीय लाभ प्रदान नहीं करते है, लागू कानूनी ढांचे के अर्थ के भीतर विशिष्ट नहीं है, और किसी भी मामले में, जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का सब्सिडीकरण नहीं होता है।

168. प्राधिकारी यह पाते हैं कि मलेशिया सरकार ने इस कार्यक्रम पर विशिष्ट विवरण नहीं दिया है और एएससीएम के अनुच्छेद 11.2 के तहत प्रस्तुत किए जा रहे पर्याप्त साक्ष्य के बिना इसकी जांच में प्रक्रियात्मक आधारों पर आपत्ति की है। दोनों निर्यातकों ने इस योजना के तहत कोई लाभ लेने से इनकार किया है।

169. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना को नोट किया है और वे यह पाते हैं कि इस कार्यक्रम में उस परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है, जो अन्यथा देय है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह

निर्यात निष्पादन पर निर्भर है। अत:, यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है।

i. कार्यक्रम 26: लाइसेंस विनिर्माण भंडारगृह

170. इस कार्यक्रम का खुलासा निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर तथा मलेशिया सरकार के पूरक उत्तर के माध्यम से हुआ था। याचिकाकर्ता ने इस योजना के संबंध में कोई अनुरोध किया है। मलेशिया सरकार ने कार्यक्रम के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम का संचालन रॉयल मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 65 और धारा 65क द्वारा शासित है।

172. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत अनुमोदित उत्पादों के विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे उपयोग किए जाने वाले सभी कच्चे माल/घटकों को सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट दी जाती है। सहयोगी निर्यातक और मलेशिया सरकार के उत्तरों से यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत केवल अनुमोदित अंतिम उत्पादों की प्रत्यक्ष विनिर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण ही सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, एलएमडब्ल्यू में विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे उपयोग की जाने वाली मशीनरी/उपकरण को आयात शुल्क/बिक्री कर से छूट दी गई है।

173. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम अनुमोदित उत्पादों के विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे उपयोग किए जाने वाले सभी कच्चे माल/घटकों पर सीमा शुल्क और बिक्री कर की छूट प्रदान करता है। सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उत्पाद/उद्यम पर निर्भर है। ज़िनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने की बात स्वीकार की है। इसलिए, इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य होना नोट किया जाता है।

174. **शिनयी सोलर**: निर्यातक द्वारा अपने उत्तर में, साथ ही डेस्क सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की गई सूचना और दस्तावेज दर्शाते हैं कि निर्यातक ने कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की आवश्यकता है।

175. **एसबीएच किबिंग एसडीएन बीएचडी:** इसने कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के विरुद्ध निर्यातक पर नहीं लगाए जाने चाहिएं।

च.3.8 सब्सिडी मार्जिन

176. वर्तमान जांच में निर्धारित सब्सिडी मार्जिन इस प्रकार है:

<u>सब्सिडी मार्जिन: शिनयी सोलर</u>

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	रेंज %	सब्सिडी की प्रकृति
कार्यक्रम सं. 4	निवेश कर भत्ता	पूंजीगत व्यय पर 100% छूट। फरवरी 2015 से दस (10) वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन सुविधाओं पर किया गया कुल निवेश लागत वर्ष 2015 से संचित आईटीए का पूरी तरह से उपयोग होने तक अर्जित कर योग्य लाभ को ऑफसेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।	***	0-10	कर प्रोत्साहन/ परित्यक्त राजस्व
कार्यक्रम सं. 17	बिक्री कर छूट	कर योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में पूर्णत: और प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, घटकों और पैकेजिंग सामग्री के अधिग्रहण पर विशिष्ट व्यक्ति के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट	***	0-10	कर प्रोत्साहन/परित्यक्त राजस्व

कार्यक्रम सं. 26	लाइसेंस विनिर्माण गोदाम	अनुमोदित उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त पूरी कच्ची सामग्री/संघटकों के लिए सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि परिष्कृत उत्पादों तक निर्यातों के लिए हैं या स्थानीय बाजार के लिए हैं।	***	0-10	कर प्रोत्साहन/परित्यक्त राजस्व
		कुल		0-10	

सब्सिडी मार्जिन : एसबीएच किबिंग एसडीएन बीएचडी

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन	रेंज %	सब्सिडी की प्रकृति
कार्यक्रम सं. 1	प्राकृतिक गैस में सब्सिडी	सरकारी विनियमित कीमतों पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता	***	0-10	एलटीआर
कार्यक्रम सं. 4	निवेश कर भत्ता	पूंजीगत व्यय पर 100% छूट। फरवरी 2015 से दस (10) वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन सुविधाओं पर किया गया कुल निवेश खर्च वर्ष 2015 से संचित आईटीए का पूरी तरह से उपयोग होने तक अर्जित कर योग्य लाभ को ऑफसेट करने के लिए किया जा सकता है।	***	0-10	कर प्रोत्साहन/ परित्यक्त राजस्व
कार्यक्रम सं. 17	बिक्री कर छूट	कर योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में केवल और प्रत्यक्ष रूप से उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री, घटकों और पैकेजिंग सामग्री के अधिग्रहण पर विशिष्ट व्यक्ति के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट	***	0-10	कर प्रोत्साहन/ परित्यक्त राजस्व
कार्यक्रम सं. 20	संयंत्र और मशीनरी पर बिक्री कर छूट	कच्चे माल/घटक पर योग्य निर्माता को आयात शुल्क छूट जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है	***	0-10	कर प्रोत्साहन/ परित्यक्त राजस्व
		कुल		0-10	

भाग-III

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

छ.1 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

177. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के मुद्दे पर निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की उपस्थिति के बावजूद, आयात पूरे बाजार पर हावी रहा है। जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी का संबद्ध देश से आयात काफी बना रहा।

ख. सब्सिडी वाले आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं जो जांच की अवधि के दौरान काफी सकारात्मक हैं।

ग. संबद्ध आयात ने लगातार घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है क्योंकि वे पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर थी।

घ. जांच की अवधि में, संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम था। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव को दर्शाता है।

ड. सब्सिडी वाले आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है।

च. भारतीय मांग के पर्याप्त हिस्से को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी बहुत कम है।

छ. सब्सिडी वाले आयात के निरंतर दबाव के कारण, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का पर्याप्त रूप से निपटान करने में सक्षम नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को सामानों का ढेर लगने से बचने के लिए अपनी मालसूची का निपटान करने के लिए निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया था।

ज. जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग को भारी नकदी नुकसान और नकारात्मक आय हुई है।

झ. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद मलेशिया से आयात में काफी वृद्धि हुई है।

ञ. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और मात्रा बढ़ाने की काफी आवश्यकता है, ताकि घरेलू उद्योग की चीन और वियतनाम से शुल्कों के बाद सुरक्षा की जा सके। पर्याप्त संरक्षण के बिना, चीन से आयात मलेशिया से स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि मलेशिया में उत्पादक चीनी उत्पादकों अर्थात् शिनयी और किर्बिंग से 100% संबद्ध कंपनियां हैं।

ट. घरेलू उद्योग इस बात पर जोर देता है कि क्षति के मापदंडों का विश्लेषण अलग-थलग नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले में कीमत कटौती और कीमत ह्रास दोनों हैं। घरेलू उद्योग इस बात पर प्रकाश डालता है कि सभी संगत आर्थिक कारकों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, भले ही उनमें से सभी क्षति का संकेत न दें।

ठ. घरेलू उद्योग ने भी क्षति के सांख्यिकीय साक्ष्य प्रदान किए और अनुरोध किया कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संस्थापित क्षमता में वृद्धि को क्षति की अनुपस्थिति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है। उन्होंने यह भी उजागर किया है कि अधिक उत्पादन, बिक्री और मांग के बावजूद मालसूची में भारी वृद्धि हुई है, जो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के क्षतिकारक प्रभाव को दर्शाता है।

ड. यह भी अनुरोध किया गया है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सत्यापित आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को भारी क्षति हो रही है क्योंकि हानियां, निवेश पर नकारात्मक आय, बढ़ी हुई मालसूची और बिक्री प्राप्ति में गिरावट करती हुई कम हुआ क्षमता उपयोग तथा हानियां बिगड़ता हुआ वित्तीय निष्पादन और घटता बाजार हिस्सा है।

ढ. मांग और आपूर्ति के अंतराल के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि भारतीय उत्पादक भारतीय मांग के पर्याप्त हिस्से को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी वाले आयात के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह भी अनुरोध किया गया है कि अतिरिक्त मॉड्यूल विनिर्माण क्षमताओं के बावजूद, लगातार पाटन/सब्सिडी के कारण अलाभकारी कीमतों की वजह से घरेलू कांच उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है।

ण. गुणवत्ता दावों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उसके सामानों की गुणवत्ता आयातित सामानों के बराबर है। यह भी अनुरोध किया गया है कि कुछ पक्षकारों द्वारा घटिया गुणवत्ता में वास्तविक साक्ष्य का साक्ष्य का अभाव है, क्योंकि अंतिम उत्पादों पर कोई सहायक आंकड़ों या प्रभाव प्रदान नहीं किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दे उत्पाद से संबंधित नहीं हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि "ग्लास-टू-बैक शीट" से "ग्लास-टू-ग्लास" में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी ने मांग में वृद्धि की है और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं से असंबद्ध है। इसके अतिरिक्त, पेस्टिंग, लैमिनेशन के दौरान ब्लास्टिंग, चिपकने की विफलता से संबंधित मुद्दों को कांच की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत

नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों का उपयोग करने के कारण उनके प्रयोक्ताओं द्वारा गुणवत्ता सूचकांक में उनके मॉड्यूल को कम कर दिया गया था।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

178. विरोधी पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई, जिससे यह दावा गलत साबित हो गया कि आयात ने उत्पादन का न्यूनीकरण किया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि घरेलू उद्योग आयात से कथित क्षति के बावजूद उत्पादन बढ़ाने में कामयाब रहा, जिससे पता चलता है कि आयात ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित नहीं किया।

ख. आयात के कारण होने वाली क्षति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है क्योंकि यह कच्चे माल की कीमत में अस्थिरता, वैश्विक मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जैसे महत्वपूर्ण बाहरी कारकों पर विचार करने में विफल रहता है। इन कारकों ने स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाला।

ग. घरेलू उद्योग की हानियां क्षमता के अति-विस्तार जैसे निर्णयों से होती है, जिससे उनके वित्तीय संसाधनों पर दबाव पड़ा। इस विस्तार के परिणामस्वरूप उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत हुई, जिससे परिचालन अक्षमताएँ बढ़ गईं। इन स्व-प्रभावित मुद्दों को आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

घ. घरेलू उद्योग के क्षति के दावे मुख्य रूप से मलेशियाई आयात से कथित प्रतिकूल कीमत प्रभावों पर निर्भर करते हैं। तथापि, कुल मांग में मलेशिया की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आई है जिससे वास्तविक क्षति के दावों को अविश्वसनीय बना दिया गया है।

ड. भारत में मांग तेजी से बढ़ी है और नए घरेलू उत्पादकों ने बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जबकि घरेलू उद्योग उच्च क्षमता उपयोग पर काम करने के बावजूद ऐसा करने में विफल रहा है।

च. घरेलू उद्योग ने सब्सिडी या क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना सिद्ध करने वाला कोई विश्लेषण भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे निर्णायक समीक्षा की मूलभूत आवश्यकता विफल हो गई है।

छ. हितबद्ध पक्षकारों ने उन्नत सौर मॉड्यूल के लिए वैश्विक मानकों द्वारा आवश्यक सख्त विनिर्देशों को पूरा करने में घरेलू उत्पादकों की असमर्थता के बारे में चिंताओं को उजागर किया है।

ज. यह कि घरेलू उद्योग सब्सिडीरोधी नियमावली के अनुबंध-I के तहत अपेक्षानुसार वास्तविक क्षति का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं करता।। इसके अतिरिक्त, इसमें प्रमुख आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री, लाभ, क्षमता उपयोग, नकदी प्रवाह और निवेश पर आय का विश्लेषण नहीं है, और इसके बजाय व्यापक असमर्थित आरोपों पर निर्भर करता है। वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा समर्थित घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट दर्शाए बिना, जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए कानूनी शुरुआत पूरी नहीं की गई है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

179. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सब्सिडी वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच की है।

180. सब्सिडी नियमावली का नियम 13 क्षति के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

13. क्षति का निर्धारण-

(1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अगला जांच परिणाम देंगे कि भारत में ऐसे आयात के कारण भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा होता है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी होती है ।

(2) सिवाय इसके कि जब क्षति का जांच परिणाम उप नियम (3) के तहत किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ नियमावली के अनुबंध-1 में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में

रखते हुए किसी उद्योग की स्थापना को क्षति, क्षति का खतरा, वास्तविक मंदी और सब्सिडीयुक्त आयात तथा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निर्धारित करेंगे।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी वहां भी क्षति की मौजूदगी के संबंध में जांच परिणाम दे सकते हैं जहां घरेलू उद्योग का काफी भाग क्षतिग्रस्त नहीं है यदि-

(i) यदि अलग-थलग बाजार में सब्सिडीयुक्त आयातों का संकेन्द्रण है, और

(ii) सब्सिडी आयातों से उस बाजार के अंतर्गत लगभग पूरे उत्पादन के उत्पादकों को क्षति हो रही है।

181. गुणवत्ता के मुद्दों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा विशिष्ट गुणवत्ता विनिर्देशों को प्राप्त करने में तकनीकी कठिनाई से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।

182. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध यहां नीचे हल हो जाते हैं।

सब्सिडीकृत आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

183. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
मलेशिया से आयात	एमटी	91,949	81,937	-	18,916
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,06,487	3,13,588	8,52,440	7,01,564
कुल आयात	एमटी	1,98,436	3,95,524	8,52,440	7,20,480
कुल आयातों में आयात का हिस्सा %					
मलेशिया से आयात	%	46.34%	20.72%	0.00%	2.63%
अन्य देशों से आयात	%	53.66%	79.28%	100.00%	97.37%
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	240	404
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध			100	386
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	380	402

184. उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि क्षति की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों की मांग में काफी वृद्धि हुई है।

185. यह भी नोट किया गया है कि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयात में निरपेक्ष मूल्य में सापेक्षिक संदर्भ में दोनों में गिरावट आई है।

ख. मलेशिया से आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

186. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोधों को दर्ज करते हैं कि मलेशिया से आयात उस अवधि के दौरान बढ़ गया जब चीन के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू थे, अर्थात अगस्त 2017 से अगस्त 2022 तक, जो स्पष्ट रूप से मलेशिया में

100% संबद्ध कंपनियों के माध्यम से काम करने वाले चीन के उत्पादकों द्वारा व्यापार के विचलन को दर्शाता है। चीन के विरुद्ध शुल्क निरस्त करने और चीन के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा 100% निवेश वाली वियतनामी कंपनी से उत्पादन और निर्यात शुरू होने के बाद मलेशिया से आयात शून्य हो गया। तथापि, दिसंबर 2024 में चीन और वियतनाम पर अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, मलेशिया से आयात फिर से शुरू हो गया है, जो चीनी उत्पादकों द्वारा नियंत्रित स्रोतों से आयात की प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। यह शुल्क लगाने या शुल्क रद्द करने से प्रभावित व्यापार मार्गों के बदलाव को रोकने के लिए शुल्कों के विस्तार के महत्व को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका में भारत में कुल आयात और मांग में संबद्ध देश के आयातों की मात्रा और हिस्से के विवरण दिए गए हैं।

वर्ष	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
मलेशिया से आयात	एमटी	91,949	81,937	0	18,916
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,06,488	3,13,587	8,52,440	7,01,564
कुल आयात	एमटी	1,98,437	3,95,524	8,52,440	7,20,480
कुल मांग (एमटी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	380	617
मांग में % हिस्सा					
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	-	5
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	174	211	164

यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से आयात की मात्रा में पिछले वर्षों अर्थात 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

ग. <u>उत्पादन के संबंध में आयात</u>

187. जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्पादन से संबंधित संबद्ध देश से आयात की हिस्सेदारी आधार वर्ष यानी 2020-21 में 88.81% से घटकर 2022-23 में शून्य हो गई है।

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
संबद्ध देश से आयात	एमटी	91,949	81,937	-	18,916
घरेलू उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	225	360
उत्पादन में संबद्ध देश का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	-	6

घ. सब्सिडीकृत आयातों का कीमत प्रभाव

188. नियमावली के अनुबंध-I (3) के संदर्भ में, कीमतों पर सब्सिडी वाले आयात के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडी वाले आयात द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक तक हुई होती।

i. कीमत कटौती

189. जांच की अवधि के लिए आयात की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके मूल्य कीमत निर्धारित की गई है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पहुंच मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	-	73
घरेलू बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	78	77
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	-	93
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
कीमत कटौती %	रेंज	20-30	10-20	-	30-40

190. यह देखा जाता है कि मलेशिया से कीमत कटौती लगातार सकारात्मक बनी हुई है, जो यह दर्शाता है कि पूरी क्षति की अवधि के दौरान मलेशियाई आयात को घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम कीमत पर रखे गये है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि चीन और वियतनाम पर अनंतिम शुल्क लगाने के बाद, मलेशियाई निर्यातकों ने अपनी पहुंच कीमत को 2021-22 में ***रुपये/एमटी से घटाकर जांच की अवधि में ***/एमटी कर दिया, जिससे कीमत दबाव बढ़ा। इस तेज गिरावट से कटौती मार्जिन मे ***% की तेज वृद्धि हुई, जिससे घरेलू उद्योग की कीमत निर्धारण क्षमता और बाजार की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

ii. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

191. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सब्सिडी वाले आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक न्यूनीकृत करना है या कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई थी:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	96	86
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	78	77
पहुंच कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	-	73

192. प्राधिकारी उपरोक्त से नोट करते है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था। जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और उसके घरेलू बिक्री कीमत से कम रहा। इसने घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत के साथ अपनी कीमत को बनाए रखने से रोक दिया। अत:, यह नोट किया जाता है कि आयात ने कीमत वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा, हुई होती। इस प्रकार, आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव पड़ा है।

193. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि मलेशियाई निर्यातकों द्वारा आक्रामक कीमत निर्धारण से उनकी बिक्री कीमतें को काफी हो गई हैं, जिससे लाभप्रदता और वसूली कमजोर हुई है। इसके अतिरिक्त, इन निर्यातकों की कम

समय में आयात की मात्रा को तेजी से बढ़ाने की प्रदर्शित क्षमता से क्षति के तेज होने का खतरा और बढ़ जाता है। ये कारक स्पष्ट रूप से व्यापार उपचारात्मक उपायों के अभाव में निरंतर और बार-बार क्षति होने की प्रबल संभावना को दर्शाते हैं।

iii. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

194. सब्सिडीरोधी नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडी वाले आयात के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुनिष्ठ जांच शामिल हो। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडी वाले आयात के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों सूचकांकों का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव भी इसमें शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है:

iv. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

195. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार था:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
क्षमता (एमटी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	255	363
कुल उत्पादन (एमटी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	241	348
केवल विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन(एमटी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	225	360
क्षमता उपयोग (%)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	95	96
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	240	404
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	145	166

196. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि 2021-22 से जांच की अवधि तक मांग में छह गुना से अधिक की तेज वृद्धि के बावजूद, वे अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ थे, क्षमता उपयोग आधार वर्ष यानी 2021-22 में ***% से घटकर जांच की अवधि में ***% हो गया। यह भी अनुरोध किया गया है कि बढ़ती मांग और उप-इष्टतम उत्पादन के बीच यह बेमेल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग चीनी उत्पादकों के प्रभुत्व वाले व्यापार उपचारात्मक जांच के अधीन स्रोतों से अनुचित आयात के निरंतर हानिकारक प्रभावों के कारण बाजार के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ था। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि मौजूदा शुल्कों के विस्तार और वृद्धि के संदर्भ में मलेशिया के विरुद्ध इस बढ़े हुए सुरक्षा संरक्षण को पूरा करने के लिए नई क्षमताएं स्थापित की गई हैं और अधिक की योजना बनाई गई है।

v. बाजार हिस्सा

197. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आधार वर्ष यानी 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उनकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह भी अनुरोध किया गया है कि 2015 से, वे, या तो सीधे चीन से[1] अथवा मलेशिया और वियतनाम[2] में रणनीतिक निवेश के माध्यम से निरंतर दबाव में हैं। याचिकाकर्ता द्वारा बाजार हिस्सेदारी में परिवर्तन, चीन से आयात और अन्य देशों से आयात के संबंध में सूचना निम्नानुसार है।

निम्नलिखित का बाजार हिस्सा	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
मांग	एमटी	***	***	***	***
मांग में हिस्सा					
मलेशिया से आयात	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	-	5
अन्य देशों से आयात		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	174	211	164
कुल आयात		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	113	90
घरेलू बिक्री		***	***	***	***

198. उपर्युक्त से, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी जांच की अवधि के दौरान ***% रही, जो बढ़ती खपत से लाभ उठाने में इसकी अक्षमता को दर्शाती है। शुल्क लगने वाले देशों से आयातों में जांच की अवधि में ***% हिस्सा रखकर बाजार में प्रभाव बनाया, जबकि मलेशिया आयात, जिनका पूर्व में काफी हिस्सा था, पुन: ***% के साथ आए। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि चूंकि मलेशिया में निर्यातक चीनी उत्पादकों द्वारा नियंत्रित हैं, इसलिए किसी भी समय मलेशिया का हिस्सा काफी और प्रभावी नहीं होगा।

[1] चीनी आयात पर पाटनरोधी शुल्क 18.08.2017 से 17.08.2022 तक प्रभावी था और नए शुल्क 4.12.2024 से 3.12.2029 तक प्रभावी होंगे, जिसके दौरान चीन से आयात में काफी गिरावट आई है।

[2] वियतनाम के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क 4.12.2024 से 3.12.2029 तक प्रभावी।

199. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि आयात प्रभाव के सार्थक मूल्यांकन के लिए, प्राधिकारी को मलेशिया, चीन और वियतनाम से आयात के संयुक्त हिस्से पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभावी रूप से चीनी उत्पादकों के एक ही सेट द्वारा नियंत्रित हैं। ये निर्यातक, जो अक्सर हांगकांग में कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, भारत में अपने निर्यात को भेजने के लिए रणनीतिक रूप से कई न्यायधिकरणों का उपयोग करते हैं। यह समन्वित व्यवस्था आपूर्ति स्रोत चुनने की सुविधा को सक्षम बनाती है और बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की बाजार उपस्थिति का विस्तार करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है।

vi. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

200. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में सूचना इस प्रकार थी:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	78	77
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	96	86
कर पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-342	-499	-300
ब्याज	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	237	670	290
पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-348	-488	-301
मूल्यह्रास	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	54	174	257
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-523	-703	-327
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-166	-106	-99

201. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उन्हें मार्च 2021 में मलेशिया से आयात पर सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने के बाद सुधार की उम्मीद है। तथापि, डीजीटीआर की सकारात्मक सिफारिश के बावजूद चीन के विरुद्ध शुल्क ना बढ़ाने जाने के साथ-साथ वियतनाम से बढ़ते आयात ने चीनी निर्यातकों को इन वैकल्पिक मार्गों का फायदा उठाने और भारतीय बाजार में बाढ़ लाने की अनुमति दी। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि इस पूरी अवधि के दौरान, चीन, मलेशिया और वियतनाम के माध्यम से काम करने वाले चीनी मूल के निर्यातकों ने घरेलू कीमतों को कम करना जारी रखा, जिससे निरंतर क्षति हुई। अनुचित कीमत वाले आयात के इस प्रवाह ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को कम कर दिया, लाभकारी स्तर तक कीमत वृद्धि को प्रतिबंधित कर दिया, और नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की वसूली को रोक दिया। इसलिए, घरेलू उद्योग ने प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने और लंबे समय से बकाया वसूली को सक्षम करने के लिए सब्सिडीरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया।

vii. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

202. पूरी क्षति अवधि में उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	224	215
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	202	475
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/ दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	225	360

203. यह देखा जाता है कि क्षमताओं में वृद्धि के कारण क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि रोजगार में वृद्धि से उत्पादकता में कोई हानि नहीं हुई है। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई प्रदत्त मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।

viii. मालसूची

204. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह पाटित आयातों के क्षतिकार प्रभाव दर्शाता है। घरेलू उद्योग में मालसूची के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	278	415	506

205. आवेदक की मालसूची का स्तर पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी और सबसे अधिक है।

ix. वृद्धि

206. वृद्धि ने भी समान प्रवृत्ति अपनाई है जैसी कि लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और आरओसीई में अपनाई है। वृद्धि के मापदंड अधिकतर मापदंडों के लिए नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। विवरण नीचे दी गई तालिका में में दिए गए हैं।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	%	-	9%	106%	60%
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	-	-42%	8%	4%
क्षमता उपयोग	%	-	-3%	-3%	1%
मालसूची	%	-	178%	1534%	210%
लाभ	%	-	422%	-38%	6%
नकद लाभ	%	-	477%	-10%	1%
आरओसीई	%	-	137%	-34%	5%

x. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

207. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार में काफी कम कीमत वाले आयात की मौजूदगी ने किसी भी अतिरिक्त क्षमता विस्तार के लिए निवेश जुटाने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया है। यह अनुरोध किया गया है कि यदि वर्तमान परिदृश्य जारी रहता है, तो इसका निवेश अत्यधिक अप्रयुक्त रहने की संभावना है और कोई नया निवेश नहीं आएगा।

208. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर जोर देने के कारण सौर ऊर्जा में वृद्धि आसन्न है। चूंकि संबद्ध सामानों का उपयोग सोलर मॉड्यूल में किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में निवेश की अपार गुंजाइश है। यहां तक कि आवेदकों ने भी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता में वृद्धि की है। यह तथ्य कि उन्होंने चीन से पाटित आयातों के विरुद्ध और मलेशिया से सब्सिडीकृत आयातों के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त किया, नया निवेश नहीं आया था। इसके अतिरिक्त, चीन और वियतनाम के विरुद्ध शुल्क इस क्षेत्र में आगे के निवेश के लिए सकारात्मक है। तथापि, इस स्तर पर, यदि मलेशिया के विरुद्ध शुल्क जारी नहीं रखा जाता है, तो भारतीय बाजार में चीनी आयात फिर से भर जाएगा और चीन और वियतनाम के विरुद्ध दिया गया संरक्षण व्यावहारिक रूप से अप्रभावी हो जाएगा। सब्सिडीरोधी शुल्कों न होने पर, कोई नया निवेश नहीं होगा। इस दृष्टि से, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अनुचित व्यापार परिपाटियों के विरुद्ध सकारात्मक मांग और वैध संरक्षण को देखते हुए, घरेलू उद्योग के लिए निवेश विकल्प खुला रहता है। तथापि, यदि शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता गंभीर रूप से लड़खड़ा जाएगी।

xi. भौतिक क्षति पर निष्कर्ष

209. आयात की मात्रा और कीमत प्रभावों के साथ-साथ क्षति के विभिन्न मापदंडों की जांच से पता चलता है कि सब्सिडी-रोधी शुल्क के मौजूद होने के कारण जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात स्थिर रहा। तथापि, प्रतिकूल कीमत प्रभाव है जैसा कि कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण और ह्रास दर्शाने वाली तालिका से सिद्ध है। घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और आरओसीई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कारण लिंक

xii. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

210. नियमावली में प्राधिकारी के लिए संबद्ध आयतों को छोड़कर उन कारकों की जांच करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचा सकते हैं, ताकि सब्सिडीकृत आयातों में अन्य कारकों के हुई क्षति के त्रुटिपूर्ण आरोपण से बचा जा सके। सके।

211. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही एक निर्णायक समीक्षा है और सब्सिडी और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क पहले ही मूल जांच में सिद्ध किया जा चुका है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या नियमावली में प्रदान किए गए अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने की संभावना है।

(i) **तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत**

212. मलेशिया और उन देशों, जिन पर पहले से ही पाटनरोधी/सब्सिडीरोधी शुल्क लग रहे हैं, को छोड़कर अन्य देशों से आयात कुल आयात में 3% से कम हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयात वर्तमान में हानि पहुंचा रहे हैं।

(ii) **निर्यात निष्पादन**

213. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति की सूचना घरेलू प्रचालनों के लिए है और इसीलिए निर्यात की मात्रा में संभावित परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

(iii) **प्रौद्योगिकी का विकास**

214. किसी भी हितधारक पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दर्शाया जाए कि प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो। यह भी नोट किया गया है कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू को क्षति पहुंचाने का कारक नहीं है।

(iv) **कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन**

215. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संभावित कारण प्रतीत नहीं होता है।

(v) **विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और प्रतिस्पर्धा**

216. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं है और वे देश में स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन आया है।

(vi) **घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

217. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन के साथ-साथ प्रति दिन उत्पादन के संदर्भ में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में इस अवधि में वृद्धि हुई है।

(vii) **मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

218. यह नोट किया जाता है कि पूरी क्षति अवधि में संबद्ध सामानों की मांग लगातार बढ़ी है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

<u>क्षति की जांच और कारणात्मक संपर्क:</u>

219. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से यह पता नहीं चलता है कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण हानि हो सकती है। प्राधिकारी ने जांच की कि क्या उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है:

क) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर है;

ख) सब्सिडी वाले आयात के कारण सकारात्मक और महत्वपूर्ण कीमत कटौती घरेलू उद्योग को लाभकारी स्तर तक अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रही हैं;

ग) आयात कीमतों में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नुकसान उठाना पड़ता है;

घ) घरेलू उद्योग की वृद्धि लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ आदि जैसे कीमत संबंधी आर्थिक मापदंडों की संख्या के संदर्भ में, कम होती रही है, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का सब्सिडीकृत आयात होता है;

ड.) मांग में सब्सिडी वाले आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई।

च) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक था।

छ) विचाराधीन उत्पाद से संबंधित घरेलू उद्योग के प्रचालनों पर कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, कर, क्षमता/निवेश की कमी आदि जैसी कोई बाधाएं नहीं थीं।

xiii. इंजरी का मैग्नीट्यूड और इंजरी मार्जिन

220. अथॉरिटी ने समय-समय पर बदले गए नियमों के एनेक्सर-III के साथ पढ़े गए नियमों में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू इंडस्ट्री के लिए नॉन-इंजरियस प्राइस (NIP) तय किया है। घरेलू जैसे प्रोडक्ट का NIP जांच के समय के लिए बनाने और बेचने की लागत से जुड़ी वेरिफाइड जानकारी/डेटा को अपनाकर तय किया गया है। घरेलू इंडस्ट्री का NIP नियमों के एनेक्सर III के अनुसार निकाला गया है। NIP तय करने के लिए, इंजरी पीरियड में घरेलू इंडस्ट्री द्वारा कच्चे माल के सबसे अच्छे इस्तेमाल पर विचार किया गया है।

यूटिलिटीज़ के साथ भी ऐसा ही किया गया है। इंजरी पीरियड में प्रोडक्शन कैपेसिटी के सबसे अच्छे इस्तेमाल पर विचार किया गया है। POI में प्रोडक्शन की गणना सबसे अच्छे कैपेसिटी इस्तेमाल को ध्यान में रखकर की गई है और प्रति यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए उसी प्रोडक्शन पर विचार किया गया है। यह पक्का किया गया है कि प्रोडक्शन की लागत पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या नॉन-रिकरिंग खर्च नहीं लगाया गया है। विचाराधीन प्रोडक्ट के लिए औसत कैपिटल एंप्लॉयड (यानी एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस एवरेज वर्किंग कैपिटल) पर एक उचित रिटर्न (टैक्स-पूर्व @ 22%) की अनुमति दी गई थी ताकि ब्याज, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट की रिकवरी के लिए NIP पर पहुंचा जा सके, जैसा कि एनेक्सर-III में बताया गया है और अथॉरिटी द्वारा इसका लगातार पालन किया जा रहा है। इस तरह तय की गई नॉन-इंजुरियस कीमत की तुलना संबंधित देश से इंपोर्ट की लैंडेड कीमतों से की गई है ताकि इंजरी मार्जिन तय किया जा सके।

उत्पादक	उत्पादक	उत्पादक	उत्पादक	उत्पादक	उत्पादक
	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	रेंज (%)
किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	80-90
शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	40-50
अन्य उत्पादक	***	***	***	***	80-90

ज. सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना

221. नियम 24(3) के अनुसार, प्राधिकारी को शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना की जांच करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना के संबंध में रिकॉर्ड में रखी गई पूरी सामग्री की जांच उन अन्य कारकों के साथ की, जो संगत हैं और क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना पर प्रभाव डालते हैं।

i. निरंतर सब्सिडीकरण

222. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों का सब्सिडीकरण जारी रहा है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि सब्सिडीकरण जारी रहने की संभावना है।

ii. मलेशिया में नया निवेश

223. घरेलू उद्योग ने बाजार रिपोर्टों और सार्वजनिक सूचना के आधार पर अनुरोध किया कि नए उत्पादक अर्थात किबिंग सोलर ग्लास ने संबद्ध सामानों के निर्माण के लिए अपने नए संयंत्र स्थापित किए हैं। संबद्ध सामानों के नए निवेश का विवरण इस प्रकार है:

क. निप्पन शीट ग्लास[3] कंपनी लिमिटेड: उनकी क्षमताएं मलेशिया में 2024 की चौथी तिमाही से चालू हो जाएंगी।

ख. शिनयी सोलर मलेशिया, 1200 एमटी की क्षमता वाली दो लाइनें[4]।

ग. चीन स्थित किबिंग समूह[5] किमानिस, सबा में 25 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की संस्थापित क्षमता के साथ एक बड़ा सौर ग्लास विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है।

224. उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बढ़ी हुई क्षमता और सीमित मांग के साथ, यदि शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात भारतीय बाजार में बाढ़ ला देंगे जिससे भारतीय उत्पादकों को नुकसान होगा।

iii. भारतीय बाजार की आकर्षकता:

225. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय बाजार मलेशिया या चीन में स्थित चीनी निर्यातकों के लिए बहुत आकर्षक है। यह भी अनुरोध किया गया है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, उद्योग की विकास संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। यह भी अनुरोध किया गया है

[3] मलेशिया में सोलर ग्लास की नई उत्पादन लाइन (एनएसजी.कॉम)

[4] अंतरिम रिपोर्ट 2022 के पृष्ठ 11 . शिनयी सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड.

[5] https://www.saurenergy.asia/kibing-group-to-build-usd-1-5-billion-solar-glass-plant-in-malaysia/

कि भारत विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार बना हुआ है, जैसा कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद तब से निरंतर आयातों से सिद्ध है।

226. उपरोक्त के अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि व्यापार मानचित्र के आंकड़ों के आधार पर मलेशिया से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात गंतव्य में भारत चौथे स्थान पर है।

iv. चीन और वियतनाम के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद मलेशिया से बढ़े हुए आया:

227. यह नोट जाता है कि दिसंबर 2024 में चीन और वियतनाम के विरुद्ध अनंतिम शुल्क लगाने के बाद, मलेशिया से आयात कई गुना बढ़ गया है। जांच की अवधि दौरान और जांच की अवधि के बाद महीने-वार आयात मलेशिया से निर्यातकों की आक्रामकता दर्शाने के लिए नीचे दिया गया है।

मात्रा-एमटी	**माह**	**कुल आयात**
पीओआई	जन.-24	0
पीओआई	फर.-24	0
पीओआई	मार्च-24	0
पीओआई	अप्रैल-24	0
पीओआई	मई-24	0
पीओआई	जून-24	0
पीओआई	जुलाई-24	0
पीओआई	अगस्त-24	0
पीओआई	सित.-24	474
पीओआई	अक्त.-24	0
पीओआई	नव.-24	2,870
पीओआई / पीएफ	दिसं. -24	14,832
पीएफ के बाद	जन-25	29,352
पीएफ के बाद	फर.-25	67,908
पीएफ के बाद	मार्च -25	67,120
कुल योग		
पीओआई के दौरान आयात		**18,916**
आयात (जन.-मार्च 25) पीएफ लागू होने के बाद		**1,64,380**

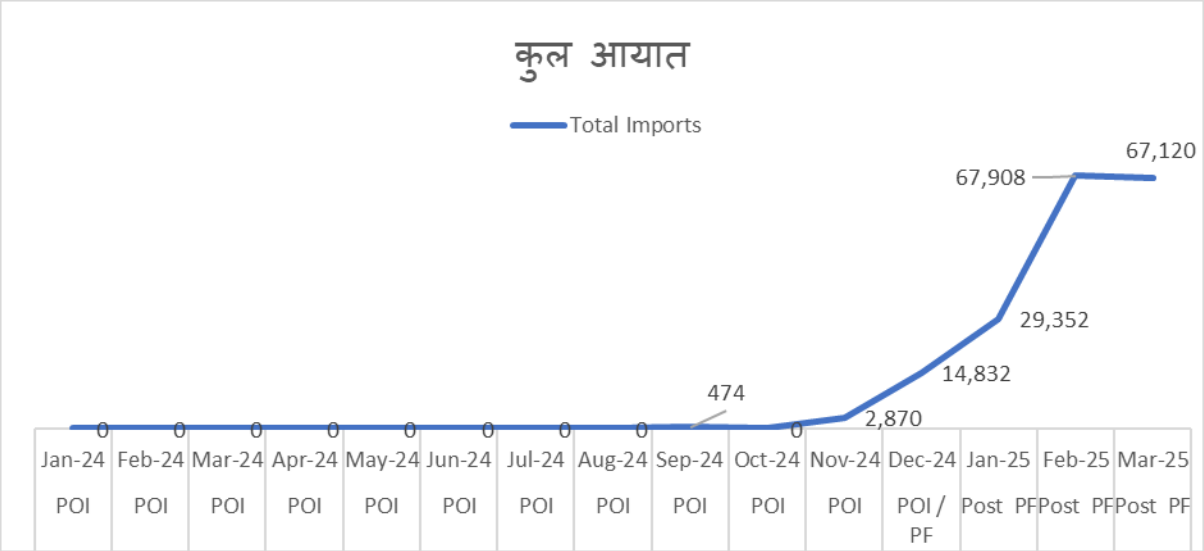

चीन और वियतनाम से आयात पर 5.12.2024 को पीएफ लगाया गया

228. उपर्युक्त ग्राफ से, प्राधिकारी यह देखते हैं कि दिसंबर 2024 में चीन और वियतनाम के विरुद्ध शुल्क लगाने के बाद आयात में काफी वृद्धि हुई है, जो सब्सिडी वाले आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति होने की स्पष्ट संभावना को दर्शाता है।

229. घरेलू उद्योग के अनुरोध पर भी प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मलेशिया में काफी अधिशेष क्षमताओं और जांच की अवधि के बाद आयात के बढ़ते रुझान को देखते हुए, इस बात की प्रबल संभावना है कि मलेशिया से निर्यात एक बार फिर भारतीय बाजार में बाढ़ लाएगा। यह सब्सिडीरोधी शुल्क के विस्तार को बढ़ाए जाने उसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता को पुष्ट करता है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वे जांच के दौरान इस संभावना और इसके दावों का और प्रमाण उपलब्ध कराएंगे। प्राधिकारी जांच प्रक्रिया के दौरान मलेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों/सरकार द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों के माध्यम से अनुमानों का सत्यापन करेंगे।

v. **घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम संभावित मात्राएँ**

230. सहयोगी निर्यातकों के उत्तरों से यह ज्ञात हुआ है कि मलेशियाई निर्यातकों ने भारत को छोड़कर अन्य देशों को *** एमटी संबद्ध सामानों निर्यात किया है। इस मात्रा में से, *** एमटी की कीमत प्राधिकारी द्वारा गणना की गई क्षतिरहित कीमत से कम है। विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	शिनयी	किबिंग	कुल
तीसरे देशों को निर्यातित मात्रा	एमटी	***	***	***
एनआईपी से कम निर्यातित मात्रा	एमटी	***	***	***
एनआईपी से कम मात्रा का % (क्षतिकारक मात्रा)	%	***	***	***
रेंज	%	70-80	70-80	70-80

vi. **घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम संभावित मात्राएँ**

231. यह सहयोगी निर्यातकों की प्रतिक्रियाओं से भी नोट किया गया है कि मलेशियाई निर्यातकों ने भारत को छोड़कर अन्य देशों को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। इस मात्रा में से, *** एमटी की कीमत घरेलू उद्योग के घरेलू बिक्री कीमतों से कम है। विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूओएम	शिनयी	किर्बिंग	कुल
तीसरे देशों को निर्यातित मात्रा	एमटी	***	***	***
घरेलू बिक्री कीमत से कम निर्यातित मात्रा	एमटी	***	***	***
घरेलू बिक्री कीमत से कम मात्रा का %	%	***	***	***
रेंज	%	30-40	60-70	40-50

झ. <u>भारतीय उद्योग के मुद्दे</u>

झ.1 दूसरी इंटरेस्टेड पार्टियों की तरफ से दी गई बातें

232. दूसरी इंटरेस्टेड पार्टियों, जिनमें यूज़र्स और डाउनस्ट्रीम सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं, ने दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी बताया है कि:

i. काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने या जारी रखने से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास ("TTG") की खरीद की लागत बढ़ सकती है, जो सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए एक ज़रूरी इनपुट है।

ii. इनपुट लागत में कोई भी बढ़ोतरी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में काम करने वाले डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स की कॉम्पिटिटिवनेस पर बुरा असर डाल सकती है।

iii. सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव और प्राइस सेंसिटिव है; इसलिए, ग्लास की ज़्यादा कीमतें मॉड्यूल की कीमत, एक्सपोर्ट और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पर असर डाल सकती हैं।

iv. यह तर्क दिया गया है कि TTG के खास वेरिएंट्स की घरेलू उपलब्धता, जिसमें नई मॉड्यूल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला एडवांस्ड या एप्लिकेशन-स्पेसिफिक ग्लास शामिल है, सीमित है और डाउनस्ट्रीम यूज़र्स बिना रुके प्रोडक्शन पक्का करने के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर रह सकते हैं।

v. यह भी चिंता जताई गई कि इम्पोर्ट पर रोक से मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और सप्लाई रिलायबिलिटी पर असर पड़ सकता है।

झ.2 घरेलू इंडस्ट्री की तरफ से दी गई बातें

233. घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि:

i. काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मकसद गलत सब्सिडी को खत्म करना और इंपोर्ट पर रोक लगाने के बजाय सही कॉम्पिटिशन वापस लाना है।

ii. घरेलू इंडस्ट्री ने TTG मैन्युफैक्चरिंग में काफी इन्वेस्टमेंट किया है और उसके पास भारतीय मार्केट में सप्लाई करने की टेक्निकल क्षमता है, जबकि चल रहे और प्लान किए गए कैपेसिटी बढ़ाने से सप्लाई की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है।

iii. एक कामयाब घरेलू इंडस्ट्री की मौजूदगी सोलर एनर्जी बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी प्रोडक्ट के लिए सप्लाई सिक्योरिटी पक्का करती है।

iv. डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी का असर बहुत कम होता है क्योंकि TTG सोलर मॉड्यूल की कुल लागत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा होता है।

v. गलत तरीके से सब्सिडी वाले इंपोर्ट जारी रहने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होगी, इन्वेस्टमेंट कम होंगे, और लंबे समय तक इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ेगी, जो सप्लाई चेन की मजबूती और "आत्मनिर्भर भारत" के राष्ट्रीय लक्ष्यों के खिलाफ होगा।

vi. एक हेल्दी घरेलू इंडस्ट्री ने ऐतिहासिक रूप से कीमत में स्थिरता और मार्केट के विकास में योगदान दिया है और इसलिए डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें सपोर्ट करती है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

234. अथॉरिटी ने नोट किया है कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट और एंटी-सब्सिडी रूल्स के तहत काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ का मकसद सब्सिडी वाले इंपोर्ट के नुकसानदायक असर को कम करना और घरेलू मार्केट में फेयर कॉम्पिटिशन की

स्थिति को फिर से बनाना है। ऐसे उपायों का मकसद सामान की अवेलेबिलिटी को रोकना या आर्टिफिशियल प्राइस एस्केलेशन करना नहीं है, बल्कि एक्शनेबल सब्सिडी से होने वाली गड़बड़ियों को न्यूट्रलाइज़ करना है।

235. अथॉरिटी ने प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, यूज़र और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ समेत सभी स्टेकहोल्डर से राय मांगी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्वेश्चनेयर भेजे, जिसमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी मांगी गई:

- सप्लाई की इंटरचेंजेबिलिटी,
- घरेलू प्रोडक्शन की उपलब्धता,
- डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ पर ड्यूटी का असर,
- यूज़र की एडजस्टमेंट क्षमता, और
- कंज्यूमर और नेशनल इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट पर असर

236. जबकि डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं ने संभावित लागत प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की, प्राधिकरण ने नोट किया कि लाभप्रदता, निर्यात या डाउनस्ट्रीम निर्माताओं के रोजगार पर भौतिक प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला कोई सत्यापन योग्य वित्तीय विश्लेषण या मात्रात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

झ.4 मांग, आपूर्ति और रणनीतिक विचार

237. अथॉरिटी का मानना है कि TTG सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाला एक ज़रूरी इनपुट है। यह सेक्टर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है। रिकॉर्ड में मौजूद सबूत बताते हैं कि डिमांड में बढ़ोतरी ग्लास-टू-ग्लास मॉड्यूल और ज़्यादा एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल की ओर टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से हो रही है, जिससे ग्लास की खपत बढ़ी है।

238. अथॉरिटी ने आगे कहा कि हालांकि डिमांड तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन गलत कीमतों पर सब्सिडी वाले इंपोर्ट जारी रहने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की संभावना कम हो जाएगी और मीडियम टर्म में डिमांड-सप्लाई के अंतर को पाटने के लिए ज़रूरी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे।

झ.5 उत्पाद की उपलब्धता

239. अथॉरिटी ने नोट किया है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने या जारी रखने से इम्पोर्ट पर रोक नहीं लगती है। इम्पोर्ट भारतीय बाज़ार में आते रह सकते हैं, हालांकि सही और बिना सब्सिडी वाली कीमतों पर। इसलिए, डाउनस्ट्रीम यूज़र्स के लिए TTG की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ने की संभावना नहीं है।

240. अथॉरिटी ने आगे देखा है कि सप्लाई के कई सोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें घरेलू प्रोड्यूसर, सही कीमतों पर संबंधित देश से इम्पोर्ट और दूसरे देशों से इम्पोर्ट शामिल हैं।

झ.6 डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव

241. अथॉरिटी ने डाउनस्ट्रीम सोलर प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी के संभावित असर की जांच की है। रिकॉर्ड में दी गई जानकारी के आधार पर, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स की कुल लागत में TTG का हिस्सा सीमित है। अनुमानित असर नीचे दिखाया गया है।

झ.7 डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्क का अनुमानित प्रभाव

हालांकि, अथॉरिटी ने नोट किया है कि नीचे दी गई टेबल में एंड कंज्यूमर्स पर एंटी-सब्सिडी ड्यूटी का संभावित असर:

विवरण UoM राशि	संदर्भ	UoM	राशि
M10 सोलर सेल पर आधारित 540 Wp सोलर मॉड्यूल की कीमत	A	₹ / मॉड्यूल	9,000
M10 सोलर सेल पर आधारित 540 Wp सोलर मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट सामान	B	किलोग्राम./ मॉड्यूल	20.05
विषयगत वस्तुओं की कीमत – लेपित	C	₹/ किलोग्राम	42.01

विवरण UoM राशि	संदर्भ	UoM	राशि
M10 सोलर सेल पर आधारित 540 Wp सोलर मॉड्यूल में बने सब्जेक्ट गुड्स की कॉस्ट	D=C*B	₹ /मीट्रिक टन	842
मॉड्यूल में विषय वस्तु की % लागत	E=D/A	%	9.36%
सब्जेक्ट गुड्स पर 10% एंटी सब्सिडी ड्यूटी के कारण मॉड्यूल पर एक्स्ट्रा कॉस्ट	F=D*10%	₹/मीट्रिक टन	84
मॉड्यूल में एंटी-डंपिंग ड्यूटी जोड़ने पर सब्जेक्ट गुड्स की कुल लागत	G=D+F	₹/मीट्रिक टन	927
मॉड्यूल में विषय वस्तु की % लागत	H=G/A	%	10.30%
एंटी-डंपिंग ड्यूटी के कारण हर सोलर मॉड्यूल पर अतिरिक्त असर	I=F/A	%	0.94%

स्रोत: रिकॉर्ड में मौजूद सबमिशन के आधार पर अथॉरिटी का एनालिसिस।

242. प्राधिकरण ने नोट किया है कि शुल्कों के पूर्ण पास-थ्रू को मान लेने पर भी, अंतिम डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर प्रभाव 1% से काफी नीचे रहता है, जो वैश्विक पॉलीसिलिकॉन, वेफर और लॉजिस्टिक्स लागतों द्वारा संचालित समग्र मॉड्यूल मूल्य निर्धारण में उतार-चढ़ाव की तुलना में आर्थिक रूप से महत्वहीन है।

ञ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

243. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, और यह नोट किया जाता है कि उठाए गए अधिकांश मुद्दे दोहराए गए हैं और पहले ही उठाए जा चुके हैं और उन्हें भी उचित रूप से हल किया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

ञ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

244. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. तथाकथित प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों, शिनयी और किबिंग द्वारा दायर उत्तरों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण सूचना रोक दी है और अधूरी और गलत सूचना प्रस्तुत करके प्राधिकारी को गुमराह किया है। इन कमियों का सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जांच की अखंडता को कमजोर करता है।

ii. निर्यातकों ने निर्यात बिक्री में संबंधित कंपनियों की भागीदारी का खुलासा करने में भी असफलता हासिल की है, जबकि किबिंग ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्यों के बावजूद क्षेत्रीय सब्सिडी की सूचना नहीं दी है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि ऐसे संकेत हैं कि शिनयी को गैस से संबंधित सब्सिडी से लाभ हो सकता है, जिसके सत्यापन की आवश्यकता है।

iii. यह कि ऐसे निर्यातकों को दी गई कोई भी रियायत गैर-अनुपालन और गलत बयानी को पुरस्कृत करने के समान होगी। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने पहले भी इसी तरह की स्थितियों में सख्त दृष्टिकोण अपनाया है और यहां भी वही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारण में केवल पूर्ण, सटीक और सत्यापन योग्य सूचना पर भरोसा किया जाए और एक्सिनी और किबिंग के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों को रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवशिष्ट सब्सिडीरोधी शुल्क के अधीन किया जाए।

iv. प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया जाता है कि अंतिम जांच परिणाम में पुष्टि करें कि संबद्ध सामानों को हीट-स्ट्रेन्थन्ड ग्लास के रूप में भी जाना जाता है। यह पुष्टि करने का भी अनुरोध किया जाता है कि मलेशिया सरकार सब्सिडी प्रदान करना जारी रखती है, और सब्सिडी वाले आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं।

ञ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

245. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. घरेलू उद्योग ने सब्सिडी के आरोपों के लिए भरोसा किए गए दस्तावेजों का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं करके और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय विवरणों को गोपनीय मानकर गोपनीयता प्रावधानों का उल्लंघन किया।

ii. घरेलू उद्योग ने पहले से ही पाटनरोधी शुल्क और सीवीडी उपायों के माध्यम से लंबे समय तक संरक्षण का लाभ उठाया है और व्यापार उपचार की अस्थायी और उपचारात्मक प्रकृति के विपरीत, आगे जारी रहना अनुचित और स्थायी संरक्षण के बराबर होगा।

iii. किबिंग का दावा है कि उसने पूरी तरह से सहयोग किया और प्राकृतिक गैस, निवेश कर नीतियों, बिक्री कर छूट और आयात शुल्क छूट जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी का खुलासा किया। इसमें तर्क दिया गया है कि निवेश कर योजना के तहत लाभ स्वयं प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हुए थे और मशीनरी आयात पर छूट एफटीए रियायतों (फॉर्म-ई) से उत्पन्न हुई थी, जो कथित तौर पर वित्तीय योगदान या विशिष्ट सब्सिडी नहीं हो सकती है।

iv. घरेलू उद्योग ने सकारात्मक निष्पादन प्रवृत्तियां दर्शाते हुए क्षमता, उत्पादन, निवेश, रोजगार और निर्यात का विस्तार किया है। उसका यह तर्क है कि लाभप्रदता में कोई भी गिरावट विस्तार लागत, आंतरिक अक्षमताओं और व्यावसायिक निर्णयों के कारण होती है, न कि मलेशियाई आयात के कारण, और यह कि क्षति के दावे अतिरंजित या कृत्रिम हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि मलेशिया से आयात में समग्र रूप से गिरावट आई है और कुल आयात में किसी भी वृद्धि का कारण चीन और वियतनाम हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि मांग-आपूर्ति अंतराल को पाटने के लिए मलेशिया से आयात आवश्यक था और अन्य देशों के साथ संचयी मूल्यांकन में साक्ष्ययुक्त आधार का अभाव है।

v. प्रकटन विवरण क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना सिद्धत नहीं करता है, यह तर्क देते हुए कि घरेलू उद्योग ने क्षमता और बिक्री का विस्तार किया है, मलेशिया से आयात में गिरावट आई है, और कोई कारणात्मक संपर्क नहीं दर्शाया गया है। उसका यह भी तर्क है कि प्राधिकारी के संभावना वाले निष्कर्ष अनुमानित हैं और अधिशेष क्षमता, भारत की ओर निर्यातोन्मुखता या आयात में संभावित वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किसी भी आधार के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

vi. किबिंग इस निष्कर्ष का खंडन करता है कि इसके निर्यात घरेलू कीमतों की कटौती या न्यूनीकरण करते हैं और दावा करता है कि इसका पहुंच मूल्य उचित बाजार कीमत निर्धारण को दर्शाता है और इस आधार पर जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है कि सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध सिद्ध नहीं हैं।

vii. शुल्कों की निरंतरता प्रतिस्पर्धी कीमत वाली कांच तक पहुंच को प्रतिबंधित करके, मॉड्यूल लागत बढ़ाकर और उपभोक्ताओं पर बोझ डालकर निचल स्तर के सौर और नवीकरणीय क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और इस उपाय को जारी रखने से उचित प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक हित कमजोर होंगे।

viii. शिनयी सोलर ने प्राधिकारी से एफओबी लेनदेन में माल भाड़ा और बीमा जोड़कर पहुंच मूल्य की पुन: जांच और पुन: गणना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वह परिसंपत्तियों के औसत उपयोगी जीवनकाल को 10 वर्षों के बजाय 16.72 वर्ष माने, क्योंकि यह जीएएपी के तहत तैयार कंपनी के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के असंगत है।

ix. निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री पर बिक्री और सेवा कर या तो छूट है या वापस कर दिया जाता है, इसलिए कोई अवशिष्ट कर बोझ नहीं रहता है। अत:, एसएसटी वित्तीय योगदान नही हो सकता या लाभ प्रदान नहीं कर सकता है और इसे प्रतिकार योग्य सब्सिडी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। शिनयी इस तंत्र की तुलना भारत के निर्यात की शून्य-रेटिंग जीएसटी से करते हैं।

x. शिनयी का तर्क है कि मूल जांच के निष्कर्ष सेस्टैट के समक्ष चुनौती के अधीन हैं और इसलिए उन्हें अंतिम नहीं माना जा सकता है। चूंकि कथित सब्सिडी की वैधता और परिमाणीकरण न्यायिक जांच के अधीन है, इसलिए उन जांच परिणामों के आधार पर शुल्क की निरंतरता समय से पहले और कानूनी रूप से सुभेद्य होगी।

ञ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

246. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुरावृत्ति के हैं और उन्हें पूर्व में प्रकटन विवरण में पहले ही हल कर दिया गया था। उपर्युक्त जांच परिणाम यथा-तथ्यत: हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यहां नीचे हितबद्ध पक्षकारों की जांच संगत सीमा तक की है और अन्यत्र कहीं हल नहीं किया है।

247. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा दायर किए गए उत्तर अपूर्ण और भ्रामक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच लागू नियमावली के अनुसार की गई है और जहां आवश्यक था, वहां व्यवहार्य सीमा तक सत्यापित की गई है। सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण रिकॉर्ड में सत्यापित सूचना के आधार पर किया गया है, जहां उचित हुआ, अंतराल या असंगतियों के उदाहरणों में उपलब्ध तथ्यों द्वारा पूरा किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी को निर्यातकों के उत्तरों को पूरी तरह से खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला है और निर्धारण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त मानी गई सूचना पर भरोसा किया गया है।

248. भारत को निर्यात में संबद्ध कंपनियों की भागीदारी, कथित क्षेत्रीय सब्सिडी की रिपोर्टिंग न करने और प्रतिभागी निर्यातक द्वारा संभावित गैस से संबंधित लाभों से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान जांच में सब्सिडी का आकलन निर्यातकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सूचना, सत्यापन प्रश्नों के उतर और जांच प्रक्रिया के दौरान जांचे गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जहां भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, प्राधिकारी ने संगत सूचना मांगी और उसका मूल्यांकन किया और तदनुसार सब्सिडी निर्धारण में अपने निष्कर्षों को दर्शाया है। केवल सांकेतिक या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री पर आधारित आरोप, वास्तविक लाभ प्राप्त करने का सत्यापन योग्य साक्ष्य दर्शाए बिना, रिकॉर्ड पर पहले से सिद्ध निष्कर्षों के संशोधन को स्वयं उचित नहीं ठहराते हैं।

249. घरेलू उद्योग के इस तर्क से प्राधिकारी सहमत नहीं है कि निर्यातक के उत्तरों पर निर्भरता गैर-अनुपालन को पुरस्कृत करने के समान होगी। प्राधिकारी का निर्धारण सहयोग की किसी धारणा पर आधारित नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड में रखी गई सूचना, सत्यापित आंकड़ों और जहां आवश्यक था, नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों की एक वस्तुनिष्ठ जांच पर आधारित है। प्राधिकारी ने प्रस्तुत सूचना की पूर्णता और विश्वसनीयता का का मूल्यांकन करने में पूरा परिश्रम लगाया है और सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाले हैं। तदनुसार, यह आरोप कि प्राधिकारी ने उदारता दिखाई है या अपनी स्थापित परिपाटी से विचलित हो गए हैं, सही नहीं है।

250. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के विवरण और सब्सिडी और क्षति की मौजूदगी के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच की है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में इन पहलुओं पर जांच परिणाम को हल किया गया है।

251. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में, प्राधिकारी यह देखते हैं कि गोपनीयता के दावों की जांच लागू नियमावली के अनुसार की जाती है, और सूचना को केवल तभी गोपनीय माना जाता है जब उचित कारण दर्शाया जाए। प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त अगोपनीय सार रखे जाएं ताकि हितबद्ध पक्षकार उन सूचनाओं के सार को उचित रूप से समझ सकें जिन पर भरोसा किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि उन्हें जांच में अपने हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने से रोका गया है और इसलिए, इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है।

252. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क जारी रखने से घरेलू उद्योग के लिए लंबे समय तक संरक्षण के होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपाय केवल वहां जारी रखे जाते हैं जहां, निर्णायक समीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ जांच पर, उपाय की समाप्ति से सब्सिडी और क्षति के जारी रहने और बार बार होने की संभावना हो। इस प्रकार किसी शुल्क का जारी रहना स्वचालित या प्रकृति में संरक्षणात्मक नहीं है, बल्कि अनुचित व्यापार परिपाटियों की मौजूदगी और उनके हानिकारक प्रभावों पर सख्ती से निर्भर है। निर्यातक ने यह दर्शाने करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि सब्सिडी समाप्त हो गई है या घरेलू उद्योग उपाय के अभाव में क्षति से

अछूता रहेगा। तदनुसार, प्राधिकारी पाते हैं कि जहां तथ्यों से आवश्यकता है, वहां शुल्क का जारी रहना अनुचित संरक्षण नहीं है, बल्कि एक वैध उपचारात्मक प्रतिक्रिया बनी हुई है, और इस प्रकार निर्यातकों का तर्क सही नहीं है।

253. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि किर्बिंग ने पूरी तरह से सहयोग किया है और यह कि कुछ कार्यक्रम या तो लाभ प्रदान नहीं करते हैं या केवल एफटीए रियायतों से उत्पन्न होते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सत्यापन के दौरान, इसने कुछ सब्सिडी तत्वों की मौजूदगी की पहचान की है, जिन पर शुरू में दावा नहीं किया गया था या निर्यातक द्वारा पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया गया था। वर्तमान जांच में सब्सिडी का निर्धारण इसलिए सत्यापन के दौरान प्राप्त सत्यापित सूचना पर आधारित है, जहां आवश्यक हुआ वहां उन उदाहरणों में उपलब्ध तथ्यों द्वारा पूरक है जहां पूरी या विश्वसनीय सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्राधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि सत्यापित आंकड़ों का प्रयोग और जहां आवश्यक था, वहां उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का प्रयोग, नियमावली के संगत है और यह सब्सिडीकरण का वस्तुनिष्ठ आंकलन सुनिश्चित करता है। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में भी निर्यातक ने अपने दावे सिद्ध नहीं किए हैं और इसीलिए यह तर्क कि किर्बिंग को सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण में पूर्वाग्रह हुआ है, आधारहीन है।

254. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है या मलेशिया के कारण कोई क्षति नहीं हुई है, यह नोट किया जाता है कि कुछ मापदंडों में सुधार क्षति की मौजूदगी को वहां नहीं रोकते, जहां रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के कीमत न्यूनीकरण, प्रतिकूल लाभप्रदता प्रवृत्तियों और सुभेद्यता दर्शाते हैं। निर्यातक ने यह दर्शाने के लिए ठोस साक्ष्य नहीं रखा है कि मलेशिया से आयात क्षतिरहित कीमतों पर थे या उन्हें मलेशिया सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, या उन्होंने घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव नहीं डाला। इसके अतिरिक्त, यह दावा कि आयात ने केवल मांग-आपूर्ति अंतराल को पाट दिया या संचयी मूल्यांकन अनुचित है, सत्यापन योग्य आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं है। अत: प्राधिकारी यह पाते हैं कि अनुरोध संकेतों के चुनिंदा निर्वचन पर आधारित हैं और रिकॉर्ड में क्षति और संभावना विश्लेषण का खंडन नहीं करते तथा तद्नुसार उसे रद्द करते हैं।

255. प्राधिकारी ने पहुंच मूल्य के परिकलन की जांच की है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए ठीक किए गए पहुंच मूल्य का प्रयोग किया है। औसत उपयोगी जीवन काल के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित सूचना के आधार पर 10 वर्षों के रूप में परिसंपत्तियों का औसत उपयोगी जीवन काल सही माना है।

256. निर्यातक का यह तर्क कि निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर बिक्री और सेवा कर (एसएसटी) या तो छूट प्राप्त हैं या वापस कर दिया गया है और इसीलिए प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं बन सकता है, गलत है। सब्सिडी कार्य-ढांचे के तहत, इनपुट पर अप्रत्यक्ष करों की छूट या छूट को वित्तीय योगदान के रूप में माना जा सकता है, जहां ऐसी छूट निर्यातित सामानों के उत्पादन में खपत किए गए इनपुट पर वास्तव में लगाए गई राशि से अधिक है या जहां योजना सख्ती से पूर्व-चरण के करों की तटस्थता तक सीमित नहीं है। निर्यातक ने सत्यापन योग्य साक्ष्य के साथ यह नहीं दर्शाया है कि एसएसटी छूट धनवापसी तंत्र निर्यातित उत्पाद में उपभोग में लाए गए इनपुट तक सीमित अनुमेय शुल्क वापसी प्रणाली के रूप में काम करता है। एक पारदर्शी और उत्पाद-विशिष्ट सत्यापन तंत्र के अभाव में यह सुनिश्चित करने के लिए कि छूट वास्तव में उपार्जित करों से अधिक नहीं है, इस तरह के प्रत्यक्त कर सरकार के कारण अन्यथा राजस्व हैं और इसीलिए लाभ प्रदान करने वाले वित्तीय योगदान दर्शाते हैं। भारत की जीएसटी शून्य रेटिंग कार्य-ढांचे की तुलना उपयुक्त नहीं है क्योंकि किसी उपाय की प्रतिकारणीयता की जांच निर्यातक देश में उसके डिजाइन, प्रचालन और सत्यापन के आधार पर की जानी चाहिए। तद्नुसार प्राधिकारी यह मानते हैं कि निर्यातक को दिया गया एसएसटी व्यवहार प्रकृति में प्रतिकार योग्य है।

257. जहां तक, शिनयी के इस तर्क का संबंध है कि मूल जांच के जांच परिणाम माननीय सेस्टैट के समक्ष चुनौती के अधीन हैं और इसलिए, उन्हें अंतिम नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में, प्राधिकारी का मानना है कि अपील के केवल लंबित होने तक मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम प्रचालनहीन नहीं हो जाते या कानूनी प्रभाव से बचते हैं।

जब तक जांच परिणामों को सक्षम अपीलीय मंच द्वारा अलग नहीं रखा जाता या संशोधित नहीं किया जाता, तब तक वे वैध और लागू बने रहते हैं।

258. जहां तक इस दलील का संबंध है कि संभावना संबंधी निष्कर्ष किसी भी सकारात्मक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं और मात्र एक दावा हैं, यह उल्लेखनीय है कि सनसेट समीक्षा में संभावना का विश्लेषण स्वभावतः भावी होता है। यह विश्लेषण सब्सिडीकरण, बाजार की परिस्थितियों तथा उपायों के अभाव में निर्यातकों की शिपमेंट बढ़ाने की क्षमता और प्रोत्साहन के उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होता है। प्राधिकारी ने सनसेट समीक्षा में यह परीक्षण किया है कि शुल्क की समाप्ति पर सब्सिडीकरण और क्षति समाप्त हो जाएगी या उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

259. शुल्क बढ़ाए जाने से संबंधी अनुरोध सार्वजनिक हित में नहीं होगा, यह नोट किया जाता है कि उक्त दावे रिकॉर्ड में किसी भी साक्ष्य से अप्रमाणित और असमर्थित हैं। सब्सिडी वाले आयात के क्षतिकारक प्रभावों को बेअसर करने और उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करने के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाया जाता है, और इसे वैध आपूर्ति पर प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है। निचले स्तर के उद्योगों या उपभोक्ताओं पर किसी भी असमान प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने वाले साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी इस तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते और इसे रद्द करते हैं।

ट. <u>निष्कर्ष</u>

260. प्राधिकारी, कार्यवाही के दौरान उठाए गए मुद्दों, सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों और रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों की जांच करने के बाद, निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए यह आवेदन-पत्र मेसर्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) और विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (वीजीपीएल) द्वारा दायर किया गया है। निर्धारित प्रारूपों के अनुसार लागत और क्षति के आंकड़े उनके आंकड़ों के आधार पर हैं। आवेदक सीवीडी नियमावली,1995 के नियम 6(3) और 2(ख) के अभिप्राय से आधार की अपेक्षा पूरी करता है और घरेलू उद्योग है।

ख. मूल जांच के समय निर्धारित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद 'कम से कम 90.5% ट्रांसमिशन के साथ टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई 4.2 मिमी से अधिक नहीं है (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे वह लेपित हो या बिना लेपित हो। तथापि, स्पष्टता के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के अन्य नामों में से एक के रूप में हीट स्ट्रेंथन्ड ग्लास को जोड़ा है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित सामान मलेशिया से आयातित संबद्ध सामानों की समान वस्तु हैं।

घ. मलेशिया सरकार ने निर्णायक समीक्षा में जांच की गई 'नई सब्सिडी' के लिए उत्तर दायर नहीं किया है। इसलिए, इन योजनाओं के संबंध में निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

ड. हितबद्ध पक्षकारों ने पहले प्रतिकारित योजनाओं की समाप्ति का कोई सबूत पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, पूर्व में प्रतिकारित योजनाओं को बाद की जांचों में प्रतिकारयुक्त किया गया है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि मूल जांच में प्रतिकारित योजनाएं जांच की वर्तमान अवधि में जारी हैं।

च. मलेशिया में संबद्ध सामानों के उत्पादक प्रतिकार योग्य सब्सिडियों से लाभ लेते रहे है।

छ. जांच की वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति कमजोर है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर, शुल्क बंद होने की स्थिति में मलेशिया से सब्सिडी और क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना के स्पष्ट संकेत हैं।

ज. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि मलेशिया के उत्पादक निर्यातोन्मुख हैं। उत्पादकों ने ऐसी क्षमताएं स्थापित की हैं जो देश में मांग से कहीं अधिक हैं।

झ. मलेशिया से अन्य देशों को निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं और उपायों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ठ. <u>सिफारिशें</u>

261. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही लागू कानून के अनुसार की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत अधिसूचित किया गया और उन्हें जांच के तहत मामलों पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, जिसमें सब्सिडी, क्षति, कारणात्मक संपर्क, सब्सिडी और क्षति के बार बार होने या जारी रहने की संभावना और भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल है। निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में प्रतिकारी शुल्क जारी रखे जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा प्राप्त वास्तविक सब्सिडी मार्जिन की सिफारिश की है।

262. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि मौजूदा प्रतिपूरक शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं तो सब्सिडीकरण और हानि की संभावना के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं, प्राधिकरण का मत है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर संबंधित देश से लागू सब्सिडी-विरोधी/प्रतिपूरक शुल्क को जारी रखना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकरण संबंधित देश से आयातित वस्तुओं पर मौजूदा सब्सिडी-विरोधी/प्रतिपूरक शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझता है। तदनुसार, मलेशिया के उत्पादकों के लिए सब्सिडी-विरोधी/प्रतिपूरक शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तालिका के अनुसार की जाती है।

263. यह निर्धारित करने के बाद कि यदि मौजूदा प्रतिपूरक शुल्क वापस ले लिया जाता है तो इस मामले में सब्सिडी जारी रहने/पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है, वर्तमान जांच के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, मलेशिया से आयातित संबंधित वस्तुओं पर मौजूदा प्रतिपूरक शुल्क को शुल्क की वर्तमान मात्रा में बिना किसी संशोधन के जारी रखना उचित समझा जाता है।

264. हालांकि, प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि किर्बिंग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी (किर्बिंग) नामक एक निर्यातक ने वर्तमान सनसेट रिव्यू जांच में भाग लिया है, जबकि मूल जांच के समय उसने भाग नहीं लिया था। निर्यातक ने वर्तमान सनसेट रिव्यू के दौरान सहयोग किया है और प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन के माध्यम से निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का भी सत्यापन किया है। वर्तमान जांच के तथ्यों के आधार पर, प्राधिकरण किर्बिंग के लिए अलग से प्रतिपूरक शुल्क दर निर्धारित करना उचित समझता है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जांच में मौजूदा प्रतिपूरक शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडी के जारी रहने/पुनरावृत्ति और नुकसान की संभावना है, उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए प्रतिपूरक शुल्क की मात्रा केवल सब्सिडी के मार्जिन के बराबर या उससे कम प्रतिपूरक शुल्क के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है, जैसा कि नियम 4 (घ) के तहत नई जांच में प्रावधान किया गया है। मलेशिया से आयातित वस्तुओं पर लागू वर्तमान प्रतिपूरक शुल्क में मूल जांच में भाग लेने वाले सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक शुल्क और गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू शुल्क दोनों शामिल हैं। चूंकि वर्तमान समीक्षा में संबंधित देश से आयातित वस्तुओं पर मौजूदा प्रतिपूरक शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जा रही है, इसलिए प्राधिकरण किर्बिंग के लिए भी सहयोगी निर्यातक पर लागू मौजूदा प्रतिपूरक शुल्क दर की सिफारिश करना उचित समझता है।

265. इस प्रकार, प्रतिकर शुल्क (एंटी-सब्सिडी) नियमावली के नियम 19(1)(ख) को नियम 24(3) के साथ पठित करते हुए, प्राधिकरण यह उपयुक्त एवं आवश्यक मानता है कि नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में दर्शित राशि के समतुल्य वर्तमान प्रतिकर शुल्क को मलेशिया से आयातित सभी विचाराधीन वस्तुओं पर पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की अनुशंसा की जाए। तदनुसार, उपर्युक्त स्थापित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, यह अनुशंसा की जाती है कि शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में निर्दिष्ट राशि के समतुल्य प्रतिकर शुल्क, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से, मलेशिया में उत्पन्न अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन वस्तुओं के सभी आयातों पर अधिरोपित किया जाए।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	प्रशुल्क शीर्ष/उपशीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश		निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के % के रूप में शुल्क
1	2	3	4		5	6	7
1	7003, 7005, 7007, 7016, 17020 और 8541*	टेक्स्चर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) कोटेड और अनकोटेड ग्लास**	मलेशिया		मलेशिया	शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी	9.71%
2	-वही-	-वही-	मलेशया		मलेशिया	एसबीएच किबिंग एसडीएन. बीएचडी	9.71%
3	-वही-	-वही-	मलेशिया		मलेशिया सहित सभी देश	क्रमांक 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई भी उत्पादक	10.14%
4	-वही-	-वही-	मलेशिया को छोड़कर कोई देश		मलेशिया	कोई	10.14%

**उपर्युक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन-पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा दिनांकित होगी, जो उसके नाम और कार्य द्वारा पहचाना जाएगा, जो इस प्रकार तैयार किया गया है: 'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस बीजक द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (उत्पाद संबंधित) की मात्रा मलेशिया में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।' यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी कंपनियों पर लागू शुल्क, लागू होगा। यह ज़रूरत लागू कस्टम कानून और नियमों के तहत कस्टम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए वेरिफिकेशन प्रोसेस पर कोई असर डाले बिना है।"*

*** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*

**** न्यूनतम 90.5% मोटाई के संचरण के साथ टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास 4.2 मिमी से अधिक नहीं (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे लेपित हो या बिना लेपित हो। उत्पाद को विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे सौर ग्लास, सौर ग्लास कम लोहा, सौर पीवी ग्लास, उच्च संचरण फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्परड कम लोहा पैटर्न वाले सौर ग्लास और हीट स्ट्रेंथन्ड ग्लास।*

266. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 88, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

267. इन जांच परिणामों के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

<u>NOTIFICATION</u>

New Delhi, the 3rd March, 2026

<u>(Final Findings)</u>

<u>Case No. CVD (SSR) – 01/2025</u>

Subject: Final Finding in Sunset Review investigation of Countervailing Duty/ Anti-subsidy concerning imports of "Textured Tempered Glass'" originating in or exported from Malaysia.

F. No. 7/10/2025-DGTR: - Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Anti-Subsidy Rules' or the 'Rules' (hereinafter referred to as "CVD Rules");

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Borosil Renewables Limited (BRL) and Vishakha Glass Pvt. Ltd. (VGPL) (hereinafter also referred to as "the domestic industry" or "the applicants") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-subsidy Duty on subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Rules') for sunset review of anti-subsidy investigation concerning the imports of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass (hereinafter referred as the "subject goods" or the "product under consideration or PUC"), originating in or exported from Malaysia (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The original anti-subsidy investigation into imports of the subject goods was initiated vide Notification No. 06/13/2019-DGAD dated 12.09.2019. Following a detailed investigation, the Authority concluded that (i) the government of the subject country was providing various subsidies to the producers of subject goods; (ii) the subsidies were countervailable in nature under CVD Rules; and (iii) imports of the subsidised subject goods were causing injury to the domestic industry. Therefore, the Authority recommended imposition of countervailing duties on the imports of subject goods *vide* Notification No. 06/13/2019 dated 11.12.2020. On the basis of the positive recommendation, following definitive countervailing measures were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 3/2021-Customs (CVD) dated 9.3.2021 and the measures were imposed till 8th June, 2026.

S. No.	Producers	Duty Amount as % of CIF value
1	M/s Xinyi Solar Sdn. Bhd., Malaysia	9.71%
2	All Others	10.14%

3. The applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of subsidisation of subject goods, originating and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation and enhancement of the anti-subsidy duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

4. In terms of Section 9(6) of the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 24(3) of the Customs Tariff Rules, 1995 countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of countervailing duties is likely to lead to continuation or recurrence of subsidized imports.

5. The applicants filed an application on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, requesting a sunset review of the countervailing duties on imports of subject goods originating in and exported from Malaysia. The applicants have sought continuation of the countervailing duties levied on imports of the subject goods on the grounds that expiry of the duties is likely to result in continuation of subsidized subject imports and consequent injury to the domestic industry. Further, the applicants have sought enhancement of duties.

6. The Authority examined the application filed on behalf of the domestic industry and found prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of subsidization and consequent injury to the domestic industry. Consequently, in accordance with the Rules, the Authority initiated the subject investigation vide Notification No. 07/10/2025-DGTR, dated 24.6.2025, published in the Gazette of India (Extraordinary), to review the need for continued imposition and enhancement of the countervailing duties in respect of the subject goods, and to examine whether the expiry of the said duties is likely to lead to continuation of subsidisation and injury to the domestic industry. Countervailing duty was extended by MOF on the recommendations of DGTR vide Notification No. 07/2025-Customs (CVD), and duty is effective till 8th June 2026.

7. The scope of the present review covers all aspects of the aforementioned original investigation concerning the subject goods.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

8.1 Initiation

a. The Authority issued a public notice dated 24th June 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-subsidy investigation concerning the imports of the subject goods from the subject county.

b. The Authority sent a copy of the initiation notification to the government of the subject country, through their embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users, the domestic industry, the other Indian producers as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limits.

8.2 Circulation of non-confidential version of the application

a. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject country, through their embassy in India, in accordance with Rule 7(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

8.3 Participation by Exporters of Subject Country

a. The Authority sent an Exporter's Questionnaire to exporters in subject country to elicit relevant information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:

b. The embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

c. In response, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire responses:

(i) Xinyi Solar (M) SDN. BHD,

(ii) SBH Kibing Solar New Materials (M) SDN. BHD.

8.4 Participation by Importers/Users

a. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(5) of the Rules.

(i) Mundra Solar PV Limited

(ii) Swelect Energy Systems Limited

(iii) Premier Energies Limited

(iv) Renewsys India Private Limited

(v) Goldi Solar Private Limited

(vi) Waaree Energies Limited

(vii) Alpex Exports Pvt Ltd

(viii) Vikram Solar Pvt Ltd

(ix) Emmvee Photovoltaic Power Pvt Ltd

(x) Navitas Green Solutions Pvt Ltd

(xi) Sova Power Limited

b. The following importers / users / consumers has filed the questionnaire response. The Authority has also considered their submissions accordingly.

i. Navitas Green Solutions Pvt. Ltd,

ii. Solex Energy Limited,

iii. Reliance Industries Limited.

8.5 Period of Investigation and Injury Period

a. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st January 2024 to 31st December 2024 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covers a period of FY 2021-22, FY 2022-23, FY 2023-24 and the period of investigation.

8.6 Further procedures

a. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

b. Request was made to the DG System to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG System data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

c. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure-III to the AD Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-subsidy duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

d. Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry and exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present findings.

e. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in the present findings.

f. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

g. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority provided the opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearings held on 28.10.2025 and 04.12.2025, which was attended by interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views. Non-confidential versions of the written submissions were circulated to the interested parties, and an opportunity was given to them to submit rejoinder submissions, if any.

h. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

i. The Authority provided time for providing comments on PUC/PCN. However, none of the interested parties provided any cogent submissions and therefore, no change in the product was made.

j. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority has examined the evidentiary documents submitted by the interested parties, which has formed the basis for conclusions for the present findings.

k. A Disclosure statement was issued to interested parties on 18th Feburary,2026 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 25th February 2026 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately in the present final findings.

l. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

m. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 84.58.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. The Authority, at the stage of the initiation notification, defined the product under consideration as follows:

3. "The product under consideration in the present application is "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "Product under Consideration"). The minimum level of transmission required in the subject good can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace, as it is essential for solar applications. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, Solar Glass Low Iron, Solar PV Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc.

4. The subject goods are used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace as it is essential for Solar applications. The glass used in these applications as per current trend is from 2MM to 4 MM in thickness. Size of the subject goods depends upon the purpose and module size. The glass is cut in various sizes as per customer requirement before tempering as such or after coating. Since this is the sunset review investigation, the product remains the same as was defined by the Authority in the final findings.

5. The subject goods are classified under chapter heading 70071900. However, it has been claimed by the Domestic Industry that the subject goods are also being imported under various other tariff headings like 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 etc. It is clarified that the HS codes are only indicative, and the product description shall prevail in all circumstances."

C.1 Submissions made on behalf of the other interested parties.

10. Other interested parties have not made any submission on the scope of the Product under consideration and like article.

C.2 Submissions made by the domestic industry.

11. The domestic industry made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and the like article:

a. The product under consideration is 'Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated' originating in or exported from Malaysia.

b. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Solar Glass Low Iron, Solar PV Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass, Heat Strengthen Glass etc. Textured Tempered Glass is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.

c. Domestic industry has also requested that the Authority should clarify that product under consideration is also known as Heat Strengthened Glass in the market parlance. Domestic Industry has also submitted that the Authority has considered Heat Strengthened Glass, as one of the commercial names in the recently concluded anti-dumping and anti-subsidy investigations concerning product under consideration against China and Vietnam. Moreover, there even no challenge has been raised against that determination. Therefore, there is no reason legal or otherwise for not mentioning Heat Strengthened Glass, in the final findings.

d. The subject products are predominantly imported under tariff classification at the 8-digit level, i.e. 70071900 even though the same are being classified and imported under various subheadings of the Customs Tariff Act, 1975, as can be seen from the import data. However, it is noted that subject goods are also being imported in the sub-headings 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 and 85414011 as evidenced by the import data. Moreover, it is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.

e. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The applicants have claimed that the subject goods, which are coming into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subsidized imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules.

C.3 Examination by the Authority.

12. The submissions made by the Domestic Industry with regard to the PUC related issues are examined and addressed hereunder:

13. The product under consideration in the present investigation was, at the stage of initiation, defined as 'Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated and there is no change in the scope of the product under consideration. The PUC is used as a component in solar photovoltaic panels and solar thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.

14. The PUC is also known by various other names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass etc. The

Domestic Industry has submitted that Heat Strengthened Glass is merely other name of PUC in the market parlance and no other interested parties protested for its clarification. The Authority analyzed all the submissions and material on record, there is no change in the scope of the product under consideration defined in the original investigation. Further, merely clarifying any name based on market parlance, does not modify the scope of the product under consideration. It also needs to be appreciated that any products to be classified as product under consideration, must pass the scope of the product under consideration. For instance, if any glass meets all the criteria (such as textured, toughened, having minimum of 90.5% transmission, thickness not exceeding 4.2 mm, whose at least one dimension exceeds 1500 mm with or without coating) then only, it can be considered as product under consideration irrespective of any name or understanding. In view thereof, the Authority clarifies that Heat Strengthened Glass is merely one of the names of the product under consideration, as defined in the PUC of the original investigation.

15. The product under consideration is classified under the category 'Glass and Glassware' in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

16. The Authority notes that there is no known difference in product under consideration produced by the Indian industry and exported from the subject country. Product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country in accordance with the Anti-Subsidy Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made on behalf of the other interested parties.

17. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:

a. That while the applicants collectively meet quantitative requirements, however, one of the applicants namely, Vishakha recently commenced production and was not part of prior investigations and therefore, the Authority should verify standing and assess injury parameters separately for each entity.

D.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

18. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

a. That the present application has been filed by Borosil Renewables Limited (BRL) and Vishakha Glass Private Limited (VGPL). They are the major producers of the subject goods in India.

b. The applicants have not imported the subject goods from the subject country and they are not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India.

D.3 Examination by the Authority

19. Rule 2(b) of the Anti-Subsidy Rules defines the domestic industry as under:

'(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers'.

20. The Authority notes that the application has been filed by Borosil Renewables Limited (BRL) and Vishakha Glass Private Limited (VGPL). It is further noted that apart from applicant industry, there are 3 other producers namely Govind Glass & Industries Ltd, Triveni Renewables Private Ltd. and Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd. who are producing the subject goods.

21. The Authority further notes that the applicants have not imported the subject goods from the subject country and that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Further, the production of the applicants account for a major proportion of the total domestic production. Thus, the Authority holds that applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Subsidy Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 6(3) of the Anti-Subsidy Rules.

22. Nevertheless, under the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Subsidy Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the requirement of standing of the domestic industry is specifically provided under Rule 6(3), which applies at the stage of initiation of an original investigation. Further, Rule 24(5), which governs the conduct of a sunset review, provides for mutatis mutandis application of the Rules excluding the entirety of Rule 6. Consequently, the standing requirement contained in Rule 6(3) does not apply to sunset review proceedings.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS ISSUES

E.1 Submissions made on behalf of the other interested parties.

23. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:

a. That the trade remedial measures on imports of textured tempered glass have been in place for over a decade. This prolonged reliance undermines the incentive for the domestic industry to improve efficiency and adapt to market changes, fostering dependency instead of competitiveness. It is further submitted that even WTO principles discourage the indefinite extension of trade remedies. Such prolonged measures distort market dynamics and reduce innovation, while unfairly impacting downstream industries dependent on imports.

b. It was also submitted that the Domestic Industry in previous investigations failed to prove that imports caused material injury to the domestic industry.

c. That responses filed by the exporters as well as the Government of Malaysia have been filed properly in terms of the practice of the Authority and therefore, responses cannot be ignored or rejected by the DGTR.

d. That the Domestic Industry has claimed unwarranted confidentiality and their non-confidential version is in stark violation of the practice followed by the DGTR.

E.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

24. The submissions of the domestic industry with regard to the miscellaneous submissions are as follows:

a. That none of the participating interested parties have filed proper non-confidential version of the submissions and this has severely affected the rights of the Domestic Industry to defend its right.

b. In relation to the issue of history of cases, Domestic Industry submitted that the history of the previous cases, that too, against different sources altogether, is of no legal or factual relevance to the fact of this case. The Authority is required only to see whether a case for imposition of anti-subsidy duties / extension of anti-dumping / subsidy duties is made out in the facts and circumstances of the case. It is further submitted that the previous measures are of no consequence in the present case, if the exporters are getting subsidy, then the domestic industry has no other option but to seek remedy under the laws of the land for appropriate relief. Since the exporters has not disputed receipt of benefit, the domestic industry has all the rights to seek protection against such practices.

c. In relation to submission of interested parties in the previous investigations, the Authority has not found any injury, the domestic industry submitted that at a mere glance of the previous investigations against China and Malaysia, it would be clear to interested parties that the Authority has found injury in all the cases. However, against Malaysia, the Authority did not find any dumping and therefore, no duties were imposed against it.

d. In relation to submission of excessive confidentiality by the Domestic Industry, it is submitted that the Domestic Industry has filed its non-confidential version in terms of the applicable Trade Notices and practice of the DGTR.

E.3 Examination by the Authority

25. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-subsidy Rules provides as follows:

Confidential information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3) and (7)of rule 7, sub-rule(2) of rule 14,sub-rule(4) of rule 17 and sub-rule (3) of rule 19, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 6, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as ,such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rate (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.'

26. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

27. It has been argued that the countervailing duty has remained in force for a considerable period. In this context, the Authority notes that the present investigation is a sunset review, in which the Authority examines the likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury, as sought by the applicant. An extension of the duty is recommended only if positive evidence establishing such likelihood is found. Further, where producers in the exporting country continue to benefit from subsidies provided by their government, the Domestic Industry retains the right to seek protection against subsidized imports. The Authority has conducted the present investigation in strict accordance with the provisions of the Anti-Subsidy Rules. The Authority also notes that the Domestic Industry is fully entitled to avail legal remedies and protection where it is established that exporters from any country are engaged in practices causing injury to the Domestic Industry.

SECTION – II

F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGINS

28. The producers and exporters from Malaysia were advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy programs for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.

29. The following producers/exporters from Malaysia, including the Governments of Malaysia, have filed questionnaire responses:

i. M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD
ii. SBH Kibing Solar New Materials (M) SDN. BHD.

General overview of the alleged Subsidy Programs

F.1 Submissions made by the domestic industry

30. The domestic industry has made the following submissions with regard to the subsidy and subsidy margin:

a. There is sufficient evidence showing that exporters/ producers/ their affiliates of the subject goods in the subject country have benefited from various countervailable subsidy programs.
b. Government of subject country has not filed a response/ nor provided any meaningful information. Only the government can provide detailed information related to whether the said scheme is countervailable or not. The responding exporter can only provide information whether any benefit was received or not. In other jurisdictions, where the Government of the exporting country does not cooperate, the investigating authorities rely on the facts available and determine the countervailability of the schemes.
c. It is submitted that the exporters from Malaysia as well as the Government of Malaysia have failed to respond to the questionnaire issued by the Authority in proper manner. They have either refused to provide the information relating to new schemes or have omitted to provide the same. It is respectfully submitted that such refusal to provide the information concerning new subsidy schemes or the omission thereto constitutes non-cooperation by the respective parties within the framework of the Rules.
d. As contained in the initiation notification as well as held by the Authority in the past cases, any new scheme introduced in Malysia is very well within the purview of the sunset review investigation. Therefore, it is not open for the Malaysian government to deliberately refuse the information regarding the new schemes. The Malaysian government as well as the exporters from Malaysia have to be considered as non-cooperative parties.
e. It is respectfully submitted that under the Agreement on Subsidies & Countervailing Measures as well as the Indian anti-subsidy laws, the government of any investigated country is as much an interested party as any other exporter, importer etc. Hence, the failure on the part of the Malaysian government has to be necessarily treated as a deliberate attempt to impede the investigations. Thus, the exporter also has to be treated as non-cooperative and face the consequence of deliberate non-cooperation by their government.
f. Assuming without accepting that some of the relevant subsidy schemes have actually ceased to exist, the same does not exclude the possibility or re-branding or renaming of such subsidy

schemes or the continued impact of the benefits derived. It was critical for the exporters as well as the Government of Malaysia to forthrightly inform the Authority about any new subsidy scheme that may have been introduced in Malaysia. However, their denial to fully cooperate with the Authority by withholding such information makes it extremely likely that new measures may have been implemented in the subject country providing financial assistance to the exporters in the form of actionable/prohibited subsidies.

g. As regards the allegation that the Domestic Industry has not disclosed all relevant documents to substantiate subsidization, it is submitted that the subsidization in the subject country stands substantiated in the original investigation itself. Further, such contention is based on incorrect understanding of legal threshold required to be met with by the domestic industry. In terms of the settled legal position, the domestic industry is only required to demonstrate a prima-facie case for initiation of the investigation and it is upon the relevant government and exporters to refute the contentions of the domestic industry. It is submitted that the legal thresholds for specificity, benefit, and injury nexus have been met by the domestic industry's evidence confirming subsidization and its injurious effect.

h. As per the information available in public domain, there are certain benefits available to the exporters of the subject goods in Malaysia. The government of Malaysia has also extended certain benefits to participating exporters also. Domestic Industry has humbly requested the Authority to calculate benefits for all the schemes irrespective of whether the same are identified by them or not in its application.

F.2 Submissions made on behalf of other interested parties.

31. The other interested parties have made the following submissions with regard to subsidy programs and margins.

a. The Authority has initiated an investigation without analyzing the programs adequately. The applicant did not establish the existence of the three elements comprising a countervailable subsidy, namely, (a) financial contribution, (b) benefit, and (c) specificity.

b. The allegations made by the Domestic Industry that the Government of Malaysia and the exporters have not provided complete information is completely baseless, unfounded, and contrary to the facts on record. The Producers/Exporters, as well as the Government of Malaysia, have extended full cooperation to the Designated Authority throughout the course of the present Sunset Review investigation. All information and data, as sought by the Authority, have been duly furnished within the prescribed timelines and in the formats required under the Rules.

c. The applicant failed to provide 'sufficient evidence' to support allegations. No justification is provided for tying the alleged program to the subject goods in Malaysia. Most of the subsidies alleged by the applicant are mere assertions without any actual evidence Therefore, the allegation is insufficient and ignores principles of ASCM.

d. The Authority should use the verified data filed by the exporters for analyzing the subsidy programs and margins for any purpose.

Examination by the Authority

F.3 Calculation Methodology

32. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the

investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

33. Further, the Authority has countervailed any admissible subsidy only once under a countervailable programme and not to undertake a double countervailability

F.3.1 **Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners:**
Following subsidy programs have been specifically alleged in the petition and are mentioned in the notice of initiation.

i. Program 1: Subsidies in Natural Gas

a. Submission by the Domestic Industry

34. The Domestic Industry has submitted that under this program, natural gas is provided at subsidized rate by the gas providing company to industrial users. The Domestic Industry further submitted that this subsidy is available for industries engaged in manufacturing activities. This, in turn, provides the industries in manufacturing sector access to cheap gas. As per the petitioner, the gas company is compensated by the government to the extent of subsidization. The domestic industry has provided supporting evidences in their application.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

35. It has submitted that from 1 January 2022, the gas price has been unregulated and determined on a willing-buyer, willing-seller basis, in accordance with the terms and conditions of the Gas sales agreement.

36. Ministry of External Affairs (MEA) and Energy Commission (EC) maintain records peratining to regulated gas prices, including revisions approval by the Government of Malaysia.

37. The gas price charged to industrial customers is based on tariff category. All the customers in the same tariff category will be imposed the same price.

c. Examination by Authority

38. The Authority in the original investigation recorded the following findings with respect to the present scheme:

"43. The Authority takes note of the fact that neither the Malaysian Government nor the cooperating producer from Malaysia has made any submission against the countervailability of this scheme. Nevertheless, the Authority examines the countervailability of the scheme below:

a) The response submitted by the GoM states that the gas prices in Malaysia are regulated by the Government.

b) The response submitted by the GoM acknowledges that there is a price differential in the market prices of gas and the prices of gas for industrial users.

c) Further, the response of GoM also states that the gas price charged to industrial customers is based on tariff category, indicating consumption-based tariff system.

39. It is noted from the response filed by the GoM in the present review investigation that:

a) Ministry of External Affairs (MEA) and Energy Commission (EC) maintain the record on regulated and gas prices revisions approval by the Government of Malaysia.

b) There is a price differential in the market prices of gas and the prices of gas for industrial users.

c) The gas price charged to industrial customers is based on tariff category.

40. Therefore, while the exporters and the GoM denies the existence of the subsidy under the present scheme and have stated that, since 2022 onwards, gas prices have been unregulated, the Authority has examined the responses submitted by both exporters and has also undertaken the desk verification in respect of each exporter. Upon such examination it has been found that:

41. **SBH Kibing Solar New Material :** The information furnished by the exporter during the desk verification denotes that it has procured gas from the government-owned company, Sabah Energy Corporation Ltd., at Less Than Adequate Remuneration (LTAR). It has also been observed that Sabah Energy Corporation Ltd. has issued a clarification stating that gas prices in the Sabah Region are less than 10% of the Malaysian Reference Price (MRP). The Authority therefore determines that the exporter has received gas from Sabah Energy Corporation Ltd. at Less Than Adequate Remuneration, and that this pricing is region-specific. The program is specific because it is limited to specific region that undertakes sales of gas at less than 10% of the Malaysian Reference Price. Accordingly, this constitutes a countervailable subsidy. The Authority notes that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

42. **Xinyi Solar:** Xinyi Solar SDN. BHD, Malaysia has submitted that it has not received any discounts, rebates, or special tariffs during the POI period. The natural gas supply is governed by the Gas Supply Agreement executed between the gas supplier and it's related company, under whose name the gas meter and supplier invoices are issued. The gas meter is shared between the company and its related company. Company does not receive any discount, rebate, concession, or preferential tariff from the gas supplier. Gas cost is allocated and back charged to our company strictly on the basis of actual consumption, without any mark-up, margin, or commercial adjustment. The Authority has verified from the historical prices published by its supplier and found that Xinyi has not received the Gas at LTAR. Thus, The Authority determines that countervailing duty should not be imposed against this program to Xinyi Solar.

ii. Program 2: The Market Development Grant

a. Submission by the Domestic Industry

43. The Petitioner submitted that the scheme is introduced by Malaysian Investment Development Authority (MIDA) for SMEs to promote export promotional activities. The maximum grant for an SME under the MDG program is RM 200,000. The SME should have been incorporated under the Companies Act, 1965 with at least 60% Malaysian equity ownership. The evidence and the legal basis are General Policies, Facilities, and Guidelines for Market Development Grants (MDG)-2016.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties:

44. Market Development Grant (MDG) was part of the SME Masterplan that will be the game changer in accelerating the growth of SMEs to achieve high income nation status.

45. The MDG provides an opportunity for Malaysian SMEs to apply for a reimbursable grant up to RM200,000 for participation in export promotional activities namely International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centers overseas.

c. Examination by Authority

46. The Authority notes that the Market Development Plan (MDP) is intended to increase the participation of SMEs in export promotional activities. The MDP provides SMEs with a reimbursable grant up to RM 2,00,000 for their participation in export promotional activities such as International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centers overseas. Government of Malaysia has stated that there are no anticipated changes to the program.

47. The subsidy program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred to the recipient. The subsidy program is also specific because it is contingent on export. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the participating exporters.

iii. Program 3: Pioneer Status

a. Submission by the Domestic Industry

48. The Domestic Industry has submitted that under this program a company granted Pioneer Status will enjoy tax exemption from corporate income tax. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. Five-year partial exemption is provided from payment of income tax. A company pays tax on 30% of its statutory income, with exemption period commencing from its Production Day. Unabsorbed capital allowances and accumulated losses incurred during the pioneer period can be carried forward and deducted from post pioneer income of company. As evidence of existence of the program, petitioners have relied on:

a) Promotion of Investment Act, 1986
b) Full notification pursuant to article xvi:1 of the GATT 1994 and article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures-Malaysia dt. 5 October, 2017
c) http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/
d) List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986
e) Laws of Malaysia Act 327 of Promotion of Investment act, 1986 Part-II Sec 5,6,7, deals with pioneer status
f) Web Report: EXIM Bank's Export Credit Refinancing
g) US Extruded through Malaysia

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

49. Pioneer Status may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia. Promoted activities and promoted products are determined by Minister of Finance and the Minister of Investment, Trade and Industry. The promoted products and activities cover all sectors among others, manufacturing, agricultural and services.

50. The major tax incentives for companies investing in the agricultural and manufacturing sectors are the Pioneer Status and Investment Tax Allowance. Companies can enjoy either one of the incentives as these incentives are mutually exclusive. Companies are required to submit the applications for the Pioneer Status program to the Malaysian Investment Development Authority (MIDA), an agency under Ministry of International Trade and Industry (MITI). The company will then be required to get the Pioneer Certificate from MIDA. This is to ensure that the company has complied with the conditions imposed. After MIDA is satisfied that the company has complied with the conditions, MIDA will determine the production date for the company and determine the start and ending date of the program. Later, companies approved with the program submit their claims to the Inland Revenue Board together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax deductions. The applicants will need to go through the Approval Committee also.

51. The major tax incentives for companies investing in the agricultural and manufacturing sectors are the Pioneer Status and Investment Tax Allowance. These incentives are mutually exclusive. Sections 5-25 Promotion of Investments Act 1986 are evidence of the same. The benefit is an exemption from taxes owed. Also, losses can be carried forward.

52. The eligibility criteria for the Pioneer Status are: Level of value-added (VA) percentage; and Level of technology as measured by the Managerial, Technical and Supervisory (MTS) Index.

c. Examination by Authority

53. The Authority notes that Sections 5 to 25 of the Promotion of Investment Act 1986 provides for Pioneer Status Program. The program provides for tax incentives in the form of exemption from income tax. Losses incurred during the exemption period can be carried forward for subsequent years to offset taxable income/net profit. The program is available for a pre-specified list of promoted products/activities.

54. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to promoted activity/product mentioned in the list. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

iv. Program 4: Investment Tax Policies

a. Submission by the Domestic Industry

55. The Petitioner submitted that under this program, a company granted Investment Tax Allowance (ITA) is entitled to offset this allowance against the statutory income for each year of assessment. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector, that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign

investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. An allowance of 60% on its qualifying capital expenditure incurred within 5 years from the date the first qualifying capital expenditure is incurred is given. Company can offset this allowance against 70% of its statutory income for each year of assessment. Remaining 30% of its statutory income will be taxed at the prevailing company tax rate. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

a) Promotion of Investment Act, 1986
b) Notification pursuant to article xvi:1 of the GATT 1994 and Article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures-Malaysia dt. 5 October, 2017
c) http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/
d) List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

56. Investment Tax Allowance (ITA) may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia. Promoted activities and promoted products are determined and gazetted by the Minister of International Trade and Industry. Sections 26 – 29 of the Promotion of Investments Act 1986 (Act 327) are evidence of the same.

57. The allowance is only given on capital expenditure incurred on industrial buildings, plant and machinery directly used for promoted activities or the production of the promoted products. Companies are required to submit the applications for ITA program to MIDA, an agency under MITI. The company will then be required to establish the commencement of ITA period which is on the incurrence of the first capital expenditure duly certified by MIDA. Later, companies approved with the program submit their claims to the Inland Revenue Board (IRB) together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax deductions.

58. The eligibility criteria for the ITA are value added (VA) percentage and level of technology as measured by the Managerial, Technical and Supervisory (MTS) Index.

59. Not all individuals/firms who applied and met all the eligibility criteria are approved. The applicants will need to go through the Approval Committee. The assistance is a deduction from statutory income. The allowance can be carried forward until fully utilized.

60. A company can elect to receive Pioneer Status but not receive the Investment Tax Allowance, or can elect to receive the Investment Tax Allowance, but not Pioneer Status.

c. Examination by Authority

61. The Authority notes that Sections 26 to 29 of the Promotion of Investments Act 1986 provides for Investment Tax Allowance program. Promoted activities and promoted products are granted a capital allowance. Value addition and technological requirements are also to be fulfilled. Investment Tax Allowance of 60% on the qualifying capital expenditure incurred within five years from the date the first qualifying capital expenditure is incurred. The allowance can be utilised to offset against 100% of the statutory income for each year of assessment. Any unutilised allowances can be carried forward to subsequent years until fully utilised. Even for companies that meet the listed criteria of

promoted activity, value addition and level of technology, the Authority retains the discretion to reject the applicant seeking benefit under this program.

62. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific since it is limited to certain enterprises, which meets the promoted product and are approved by the Authority. A company that has received income tax exemption from Pioneer Status cannot avail benefit under this program. The program is noted to be countervailable. It is further noted that any exporter can avail benefit under either of any two schemes and therefore, countervailing duty should be imposed for either of the schemes and not both.

63. **SBH Kibing Solar New Material:** The information and documents furnished by the exporter in its response and during the desk verification denotes that it has availed the benefit under the scheme. The Authority notes that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

64. **Xinyi Solar:** Xinyi Solar SDN. BHD, Malaysia has submitted that it has availed benefit under the present scheme whereby the total investment cost on production facilities incurred within the period of ten (10) years from January 2015 can be used to offset the taxable profit incurred since year 2015 till the accumulated ITA is fully utilized. It has been verified from the documents submitted by the exporter during the desk verification. Hence, the Authority notes that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

v. Program 5: Reinvestment Allowance

a. Submission by the Domestic Industry

65. Reinvestment Allowance (RA) is available for existing companies engaged in manufacturing and selected agricultural activities that reinvest for the purposes of expansion, automation, modernization or diversification into any related products within the same industry on condition that such companies have been in operation for at least 36 months. The RA is given at the rate of 60% on the qualifying capital expenditure incurred by the company, and can be offset against 70% of its statutory income for the year of assessment. Any unutilized allowance can be carried forward to subsequent years until fully utilised.

66. A company can offset the RA against 100% of its statutory income for the year of assessment if the company attains a productivity level exceeding the level determined by the Ministry of Finance.

67. The RA will be given for a period of 15 consecutive years beginning from the year the first reinvestment is made. Companies can only claim the RA upon the completion of the qualifying project, i.e. after the building is completed or when the plant/machinery is put to operational use.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

68. None of the interested parties including GoM, provided any details of this scheme. GoM has submitted that the inclusion of alleged subsidy programs that were not part of the original countervailing duty (CVD) investigation without proper justification violates fundamental principles of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) and established procedural requirements for evidence verification.

69. GOM views that the DGTR must conduct thorough verification of all evidence and cannot simply accept unsupported allegations, as this would violate the ASCM's fundamental requirements for proper countervailing duty investigations. The addition of new subsidy programs without meeting the evidentiary standards of Article 11.2 undermines the integrity of the investigation process and violates established WTO obligations.

70. Under Article 11.2, an application for initiation of an investigation "shall include evidence of (a) a subsidy and, if possible, its amount; (b) injury within the meaning of Article 15; and (c) a causal link between the subsidized imports and the alleged injury". The investigating authority cannot simply add new subsidy programs without meeting these fundamental evidentiary requirements.

c. Examination by Authority

71. The Authority notes that Reinvestment Allowance (RA) is provided under Schedule 7A of the Income Tax Act, 1967. It incentivizes existing manufacturing and certain agricultural companies to reinvest in expansion, modernization, automation or diversification into related products.

72. The Authority based on the Income Tax Act and publicly available guidance on Malaysian tax incentives, notes that RA: (i) is a long-duration allowance (15 years) for reinvestment; (ii) encourages capital reinvestment for capacity expansion and technological up-gradation; and (iii) provides significant tax savings for capital-intensive manufacturers.

73. Therefore, by applying the three-element test: (i) Financial Contribution: RA reduces the taxable income base, resulting in revenue foregone by the government; (ii) Benefit: RA allows companies to pay less income tax than they would under the standard regime. The benefit can be quantified as the tax saved due to the RA deduction; and (iii) Specificity: RA is available only to existing manufacturing companies, subject to a 36-month operations condition and reinvestment in specified projects. It is not a generally available measure. Reinvestment Allowance thus constitutes a countervailable subsidy in principle. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

vi. Program 6: Accelerated Capital Allowance

a. Submission by the Domestic Industry

74. The Domestic Industry has submitted that under this program a special allowance, where the capital expenditure is written off within 2 years, i.e. an initial allowance of 40% and an annual allowance of 20%, is given. After the 15-year period of eligibility for Reinvestment Allowance, companies that reinvest in the manufacture of promoted products are eligible to apply for Accelerated Capital Allowance. Applications have to be submitted to the IRB accompanied by a letter from MIDA certifying that the companies are manufacturing promoted activities/products. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

a) Promotion of Investment Act, 1986
b) http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/
c) List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

75. Accelerated Capital Allowance (ACA) provides allowances to write off the capital expenditure within two years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent. This program is available to all companies and the IRB applies objective criteria in granting ACA. The assistance is an accelerated capital allowance to be deducted from taxable income. The allowance can be carried forward. Generally, to be eligible for accelerated capital allowance (ACA), a person must meet the following conditions:
    a) He was carrying on a business during the basis period,
    b) He has incurred qualifying expenditure in the basis period,
    c) The asset was used for purposes of a business, and
    d) At the end of the basis period, he was the owner of the asset and the asset was in use.

76. Companies under investigation will be eligible to claim ACA if they fulfil the criteria and government doesn't exercise discretion as to which firm is eligible to benefit.

c. Examination by Authority

77. Authority notes that the program provides for capital allowance to write off the total capital expenditure within two years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent. Authority notes that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to certain enterprise carrying out a promoted activity that qualifies for using this allowance and does not qualify for re-investment allowance on account of expiry of 15 years period of eligibility. Therefore, the program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

vii. Program 7: Green Financing Initiatives

a. Submission by the Domestic Industry

78. As per the information provided by the petitioner, this scheme is administered by the Malaysian Investment Development Authority (MIDA) (https://www.mida.gov.my/), these fiscal incentives provide substantial tax benefits for renewable energy investments. The program offers capital allowances on qualifying green expenditures, while GITE exempts a percentage of income derived from eligible green activities from taxation, effectively accelerating the return on investment for solar projects, including PPA arrangements.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

79. GoM submitted that the inclusion of alleged subsidy programs that were not part of the original countervailing duty (CVD) investigation without proper justification violates fundamental principles of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) and established procedural requirements for evidence verification.

80. GOM views that the DGTR must conduct thorough verification of all evidence and cannot simply accept unsupported allegations, as this would violate the ASCM's fundamental requirements for proper countervailing duty investigations. The addition of new subsidy programs without meeting the evidentiary standards of Article 11.2 undermines the integrity of the investigation process and violates established WTO obligations.

81. Under Article 11.2, an application for initiation of an investigation "shall include evidence of (a) a subsidy and, if possible, its amount; (b) injury within the meaning of Article 15; and (c) a causal link between the subsidized imports and the alleged injury". The investigating authority cannot simply add new subsidy programs without meeting these fundamental evidentiary requirements.

82. None of the participating exporters have provided any information regarding this program, including whether they have refrained from availing any subsidy thereunder.

c. Examination by Authority

83. Authority notes that based on material placed by the Domestic Industry and general information on Malaysian tax incentives for green technology, the beneficiaries enjoy lower financing costs or reduced tax liabilities relative to normal market conditions; and such measures are specific to green technology and renewable energy activities, not generally available to all enterprises. The Authority therefore treats this Program as countervailable in principle. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

viii. Program 8: Net Energy Metering (NEM) & Solar incentives

a. Submission by the Domestic Industry

84. The petitioner has submitted that under the current program, the GoM provides incentives for solar generation (rooftop, onsite).

85. As per the information provided by the petitioner, NEM Rakyat initiative is part of Malaysia’s NEM 3.0 scheme, designed to incentivize rooftop solar installations through permitting net metering. Under this scheme, the Malaysian government had launched the Solar for Rakyat Incentive Scheme (SolaRIS), offering up to MYR 4,000 ($942.12) in rebates for household solar installations.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

86. GOM submitted that the inclusion of alleged subsidy programs that were not part of the original countervailing duty (CVD) investigation without proper justification violates fundamental principles of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) and established procedural requirements for evidence verification.

87. GOM views that the DGTR must conduct thorough verification of all evidence and cannot simply accept unsupported allegations, as this would violate the ASCM's fundamental requirements for proper countervailing duty investigations. The addition of new subsidy programs without meeting the evidentiary standards of Article 11.2 undermines the integrity of the investigation process and violates established WTO obligations.

88. Under Article 11.2, an application for initiation of an investigation "shall include evidence of (a) a subsidy and, if possible, its amount; (b) injury within the meaning of Article 15; and (c) a causal link between the subsidized imports and the alleged injury". The investigating authority cannot simply add new subsidy programs without meeting these fundamental evidentiary requirements.

c. Examination by Authority

89. The Authority notes that the NEM 3.0 and associated schemes such as SolaRIS in Malaysia provide incentives for rooftop solar installations by allowing net metering and direct rebates. The Domestic Industry alleges that the subject exporters have installed significant rooftop solar capacity and have benefited from these schemes The Authority treats this Program as countervailable in principle as benefit is given to only those entities who have installed solar installations. The benefit under this program, however, is not availed by the cooperating exporters.

ix. Program 9: Regional Incentives (Sabha / Melaka).

a. Submission by the Domestic Industry

90. The petitioner based on the information available in the public domain submitted that under the present scheme, both the exporters have been benefitted by the regional schemes such as state-level support by way of land subsidies, fast-tracked permits etc., and as per the information available one of the participating exporters is benefitting under the scheme through RM 7.2 billion investment in a new solar glass manufacturing facility in Kimanis.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

91. GoM has not provided detailed regional incentive program documentation, but has again stressed the ASCM requirements for evidence and the need for proper justification before including any additional subsidy programs. Moreover, both the exporters have also not provided any details of the scheme and denied that they have availed any such benefit.

a. Examination by Authority

92. The Domestic Industry alleges that regional incentive schemes at state or corridor level (e.g., Sabah, Melaka) provide land subsidies, infrastructure support, and fast-tracked permits to attract large investments in designated regions. One of the participating exporters benefited from such regional incentives in relation to a large solar glass manufacturing facility in Kimanis (Sabah), involving investments of about RM 7.2 billion.

93. The Authority notes that Malaysia has designated economic corridors and state-level schemes aimed at attracting investments through: (i) below-market provision of land; (ii) government-funded or co-funded infrastructure; and (iii) simplified and accelerated permitting procedures. Conceptually, such measures could satisfy the three-element test if: (i) land and infrastructure are provided at less than adequate remuneration, implying revenue foregone or government cost assumption; (ii) the investor's capital costs are reduced, conferring a measurable benefit; and (iii) the incentives are specific to designated regions and particular projects, and not generally available to all firms nationwide. However, specific legislative texts, loan agreements, and actual utilization data are not on record. Though the authority treats this Program as countervailable in principle, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

x. Program 10: Supply Chain facilitation Program

a. Submission by the Domestic Industry

94. The applicant has submitted that under this scheme the GoM is providing Support for local vendor development. As per the information provided by it, this program aims to create opportunities for domestic companies, narrow gaps in the supply chain, support multinational companies (MNCs) and Limited Liability Companies (LLCs) in outsourcing their manufacturing activities to domestic companies, as well as develop and upgrade the domestic companies. It has alleged that Malaysian Investment Development Authority (MIDA) is extending its support to Xinyi Energy for the purpose of this program.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

95. GOM submitted that the inclusion of alleged subsidy programs that were not part of the original countervailing duty (CVD) investigation without proper justification violates fundamental principles of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) and established procedural requirements for evidence verification.

96. GOM views that the DGTR must conduct thorough verification of all evidence and cannot simply accept unsupported allegations, as this would violate the ASCM's fundamental requirements for proper countervailing duty investigations. The addition of new subsidy programs without meeting the evidentiary standards of Article 11.2 undermines the integrity of the investigation process and violates established WTO obligations.

97. Under Article 11.2, an application for initiation of an investigation "shall include evidence of (a) a subsidy and, if possible, its amount; (b) injury within the meaning of Article 15; and (c) a causal link between the subsidized imports and the alleged injury". The investigating authority cannot simply add new subsidy programs without meeting these fundamental evidentiary requirements.

c. Examination by Authority

98. The Supply Chain Facilitation Program is alleged to be a MIDA-administered initiative intended to upgrade domestic vendors, and support multinational company (MNC)/LLC outsourcing to domestic suppliers. Companies in the logistics and supply chain industry in Malaysia are stated to be eligible for facilitation services from MIDA including various tax incentives, and/or customs duty exemptions. However, specific legislative texts, loan agreements, and actual utilization data are not on record. The Authority therefore treats this Program as countervailable in principle. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

xi. Program 11: Group Relief

a. Submission by the Domestic Industry

99. The petitioner has submitted that Group Relief is provided under the Income Tax Act 1967 to all locally incorporated resident companies. It allows related companies to offset losses of one group entity against profits of another, the claimant and surrendering companies each must have a paid up share capital of ordinary shares exceeding RM 2.5Million. Both the claimant and the surrendering companies must have the same accounting period. The Shareholding, whether direct or indirect, of the

claimant and the surrendering companies in the group must not be less than 70%. Losses resulting from the acquisition of the proprietary rights or a foreign owned company should be disregarded for the purpose of group relief.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

100. GoM has not provided detailed program documentation, but has again stressed the ASCM requirements for evidence and the need for proper justification before including any additional subsidy programs. Both the exporters have simply denied any benefit received under this scheme.

c. Examination by Authority

101. The Authority notes that Group Relief, under the Income Tax Act, 1967, allows related companies to offset losses of one group entity against profits of another, thereby reducing the overall tax burden at the group level. As per general understanding of Group Relief regimes and the material on record: (i) group relief is a generally available mechanism for resident companies meeting shareholding and control thresholds; (ii) it is not contingent upon export performance or any specific sector; and (iii) it does not appear to discriminate between industries or regions.

102. Applying the three-element test: (i) while Group Relief may involve some element of revenue foregone, it does not appear to be limited to specific enterprises or industries; (ii) it is a general feature of the income tax system for group companies; and (iii) therefore, the specificity requirement for countervailability is not met.

103. The Authority therefore regards this Program as not countervailable for purposes of this investigation.

xii. Program 12: Allowance Industrial Building (IBA)

a. Submission by the Domestic Industry

104. The Domestic Industry has claimed that IBA is granted to companies incurring capital expenditure on the construction or purchase of a building that is used for specific purposes, including manufacturing, agriculture, mining, infrastructure facilities, research, approved service projects and hotels that are registered with the Ministry of Tourism.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

105. GoM has not provided detailed program documentation, but has again stressed the ASCM requirements for evidence and the need for proper justification before including any additional subsidy programs. Both the exporters have simply denied any benefit received under this scheme.

c. Examination by Authority

106. The Authority notes that the claim relating to Industry Building Allowance (“IBA”) has been made by the Domestic Industry in generic terms, without placing on record any transaction-specific or company-specific evidence to establish that the subject exporters have actually availed or benefitted from the said scheme during the period of investigation.

107. It is further noted that the Government of Malaysia has not furnished any detailed documentation demonstrating the operational framework, eligibility conditions, grant mechanism, or actual disbursement/availing of benefits under the alleged incentive program in respect of the participating exporters. The exporters, on their part, have categorically denied receipt of any benefit under the IBA scheme, and no contrary evidence has been placed on record to rebut such denial. In the absence of verifiable information substantiating actual receipt of benefits by the participating exporters, the Authority is unable to conclude that the alleged IBA scheme has resulted in any countervailable subsidy to the participating exporters during the period of investigation. Accordingly, the claim relating to IBA is not accepted for the purpose of the present investigation.

xiii. Program 13: Allowance for plants and Machinery

a. Submission by the Domestic Industry

108. The Domestic Industry has claimed that capital allowance is a relief for wear and tear of fixed assets for business. In order to qualify, expenditure must be capital in nature and used for business purposes. Qualifying Expenditure (QE) includes costs of assets used in business such as plants and machinery, office equipment, furniture, fittings, motor vehicles etc. Where an asset is acquired on a hire purchase term, the QE for a particular basis period is based on amount of capital repayment made during that basis period. Initial allowance is fixed at 20% based on the cost of the asset at the time when the capital expenditure is incurred. Annual allowance is a flat rate given every year based on the original cost of the asset and varies accordingly.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

109. GoM has not provided detailed program documentation, but has again stressed the ASCM requirements for evidence and the need for proper justification before including any additional subsidy programs. Both the exporters have simply denied any benefit received under this scheme.

c. Examination by Authority

110. The Authority notes that the claim relating to Allowance for Plant and Machinery has been made by the Domestic Industry in generic terms, without placing on record any transaction-specific or company-specific evidence to establish that the participating exporters have actually availed or benefitted from the said scheme during the period of investigation.

111. It is further noted that the Government of Malaysia has not furnished any detailed documentation demonstrating the operational framework, eligibility conditions, grant mechanism, or actual disbursement/availing of benefits under the alleged incentive program in respect of the participating exporters. The exporters, on their part, have categorically denied receipt of any benefit under this scheme, and no contrary evidence has been placed on record to rebut such denial. In the absence of verifiable information substantiating actual receipt of benefits by the participating exporters, the Authority is unable to conclude that this scheme has resulted in any countervailable subsidy to the participating exporters during the period of investigation. Accordingly, the claim relating to this scheme is not accepted for the purpose of the present investigation.

xiv. Program 14: Double Deduction for Promotion of Malaysian brand

a. Submission by the Domestic Industry

112. The Domestic Industry has submitted that under this program, expenditure incurred on advertising local brand products domestically is allowed double deduction i.e. expenses incurred on certain activities can be set off twice as against taxable profits. The local brand must be owned more than 50% by the registered proprietor of the Malaysian brand name which should be owned by a company that's locally incorporated with at least 70% Malaysian owned and registered in Malaysia or overseas. The deduction can only be claimed by one company in a year of assessment. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

a) Promotion of Investment Act, 1986
b) Income tax promotion of export rules 1986
c) Inland Revenue Board of Malaysia Public Ruling No.1/2013

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

113. GOM has submitted that the expenditure for qualifying advertisements in advertising Malaysian brand name goods is eligible for a double deduction in arriving at adjusted income from a business. Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002 are given in evidence. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred within Malaysia for advertising Malaysian brand goods. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB. The claim can be made in the annual tax returns for the fiscal year (basis period) in which the expenditure is incurred. The companies under investigation will be eligible to claim the deductions if they fulfill the criteria. The assistance is a deduction from taxable income. The deduction can be carried forward.

c. Examination by Authority

114. The Authority notes that this program is governed by Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002. Under this program, expenditure incurred in advertising Malaysian brand is eligible for double deduction from business income. To qualify for this double deduction, the company must have 70% Malaysian equity and the brand name should be of goods of export quality. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to an enterprise that incurs expenses on advertising Malaysian brand. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

xv. Program 15: Incentive for manufacturing and manufacturing related service in East Cost Economic Corridor

a. Submission by the Domestic Industry

115. The Domestic Industry submits that the incentive scheme for manufacturing and manufacturing-related services in the East Coast Economic Corridor constitutes a countervailable subsidy, as it involves a financial contribution by the Government of Malaysia in the form of tax incentives, income tax exemptions, stamp duty exemption and other fiscal concessions. The scheme is region-specific and

limited to enterprises located within the EEC, thereby satisfying the test of specificity. Further, the incentives are aimed at promoting manufacturing of selected and agro based products.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

116. GOM has submitted that the inclusion of alleged subsidy programs that were not part of the original countervailing duty (CVD) investigation without proper justification violates fundamental principles of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) and established procedural requirements for evidence verification.

117. GOM views that the DGTR must conduct thorough verification of all evidence and cannot simply accept unsupported allegations, as this would violate the ASCM's fundamental requirements for proper countervailing duty investigations. The addition of new subsidy programs without meeting the evidentiary standards of Article 11.2 undermines the integrity of the investigation process and violates established WTO obligations.

118. Under Article 11.2, an application for initiation of an investigation "shall include evidence of (a) a subsidy and, if possible, its amount; (b) injury within the meaning of Article 15; and (c) a causal link between the subsidized imports and the alleged injury". The investigating authority cannot simply add new subsidy programs without meeting these fundamental evidentiary requirements.

c. Examination by Authority

119. The Authority has examined the submissions of the Domestic Industry as well as those of the Government of Malaysia and other interested parties. The Authority notes that while the EEC incentive scheme appears to be geographically limited, determination of its countervailable nature requires establishment of a financial contribution, conferral of a benefit, and specificity, along with a quantifiable benefit to the exporters of the subject goods during the period of investigation. The Authority observes that no verified, exporter-specific information has been furnished demonstrating actual receipt and utilization of benefits under the scheme or establishing a clear nexus and allocation of any alleged benefit to the subject goods. The Authority is unable to conclude that this scheme has resulted in any countervailable subsidy to the participating exporters during the period of investigation. Accordingly, the claim relating to this scheme is not accepted for the purpose of the present investigation.

xvi. Program 16: Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty

a. Submission by the Domestic Industry

120. The Domestic Industry has submitted that under this program, drawback on import duty, sales tax and excise duty that have been paid may be claimed by a manufacturer if the parts, raw materials or packaging materials are used in the manufacture of goods for export within a year based on conditions stipulated in the acts. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

a) Section 99 of the Customs Act 1967
b) Section 29 of the Sales tax Act 1972
c) Section 19 of the Excise Act 1976

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

121. GOM has submitted that the Drawback programme, administered by the Royal Malaysian Customs Department (RMCD) on a case-by-case basis, provides for refund of import duties on goods that are subsequently re-exported and operates strictly upon application supported by verifiable import and export documentation under sections 93, 95 and 99 of the Customs Act, 1967

122. GOM further submits that the program is not countervailable as it falls within the exceptions under Annexes I, II and III of the SCM Agreement, applying the excess remission principle. In this regard, it is well-settled, including by the WTO Panel and Appellate Body in EU – Countervailing Measures on Certain PET from Pakistan, that duty drawback schemes are countervailable only to the extent of remission in excess of duties actually accrued, and only where there is a proper evidentiary basis.

123. The GOM and the participating exporters have categorically stated that no benefit has been availed under the program during the period of investigation.

c. Examination by Authority

124. The Drawback program allegedly permits refund of import duty, sales tax and excise duty paid on parts, raw materials or packaging materials used in the manufacture of goods exported within the prescribed period, in accordance with the conditions stipulated under Section 99 of the Customs Act, 1967, Section 29 of the Sales Tax Act, 1972 and Section 19 of the Excise Act, 1976, thereby establishing the existence of the program.

125. The Authority further notes that the program is administered by the Royal Malaysian Customs Department (RMCD) on a case-by-case basis and operates only upon submission and verification of complete import and export documentation. In principle, Drawback program may be countervailable only where there is remission of duties in excess of those actually accrued, in terms of Annexes I, II and III of the SCM Agreement, and subject to a proper evidence. In the present case, both the subject exporters have categorically stated that they did not avail or receive any benefit under the Drawback program during the period of investigation, and no evidence has been placed on record to contradict such statements. Accordingly, the Authority concludes that the program is not countervailable for the purpose of the present investigation.

xvii. Program 17: Sales Tax Exemption

a. Submission by the Domestic Industry

126. The Domestic Industry has submitted that in order to reduce cost of doing business and enhance competitiveness the government has exempted the sales tax. This program is approved and administrated by RMCD and established in 1.9.2018. The Domestic Industry has submitted that under this scheme manufacturers with an annual sales turnover of less than RM 100,000 are exempted from licensing and are thus exempted from paying sales tax on their output. However, these manufacturers can opt to be licensed and obtain sales tax exemption on their inputs instead.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

127. GOM has submitted that the Sales Tax exemption scheme provides relief from payment of sales tax on importation and purchase of locally manufactured goods to specified persons and manufacturers under the Sales Tax (Person Exempted from Payment of Tax) Order, 2018. The exemptions are structured under three schedules: Schedule A covering classes of persons meeting prescribed criteria

and conditions; Schedule B covering manufacturers of specific non-taxable goods, granting exemption on acquisition of all goods (excluding petroleum) used solely and directly in the manufacture of non-taxable goods; and Schedule C covering registered manufacturers of taxable goods, granting exemption on raw materials, components and packaging materials used solely and directly in the manufacture of taxable goods. The programme is approved and administered by the Royal Malaysian Customs Department (RMCD) and operates on the basis of applications, with eligibility contingent upon fulfilment of the prescribed criteria by the companies concerned. It has also stated that none of the companies under investigation applied for, accrued or received benefit from this program.

c. Examination by Authority

128. The Authority has examined the submissions made by the domestic industry as well as those of the GOM and other interested parties. The Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Custom Department. The program provides exemption from payment of sales tax, to persons or manufacturers who meet the eligibility criteria and conditions. This exemption is on import of plant and machinery and on purchase of locally manufactured goods in the domestic market. The benefit is in the form of revenue forgone as it provides exemption of Sales tax to exporters which is otherwise due. The program is also specific because it is available to certain enterprise who meet the eligibility criteria. Therefore, this program is noted to be countervailable.

129. **Xinyi Solar** : The information and documents furnished by the exporter in its response, as well as during the desk verification, denote that the exporter has availed benefits under the program. Accordingly, the Authority notes that countervailing duty is warranted against this program.

130. **SBH Kibing Solar New Materials (M) SDN. BHD**: The information and documents furnished by the exporter in its response, as well as during the desk verification, denote that the exporter has availed benefits under the program. Accordingly, the Authority notes that countervailing duty is warranted against this program.

xviii. Program 18: Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities

a. Submission by the Domestic Industry

131. The Domestic Industry has submitted that under this program, to reduce cost of doing business and enhance competitiveness, import duty and sales tax exemption are given to Malaysian brands with at least 60% Malaysian equity who outsource manufacturing activities. Import duty and sales tax exemption on raw materials and components used in manufacturing of finished products by their contractual manufacturers locally/abroad and import duty and sales tax exemption on semi-finished goods from their contract manufacturers abroad to be used by their local contract manufacturers to manufacture finished products are available.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

132. GOM has submitted that the program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD, MIDA and IPC. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from scheme and the authorities do not exercise discretion. No changes are anticipated to the program.

133. It has also stated that this program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annex I, II and III of the SCM Agreement. To qualify for the exemption:
   a) Imported raw materials and components which are used to manufacture finished products with nil import duty.
   b) Semi-finished products are imported from contract manufacturers abroad and are used in the manufacture of finished products by local contract manufacturers.

c. Examination by Authority

134. Authority notes that the program is administered by the Malaysian Investment Development Authority. The program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semifinished products for outsourcing manufacturing activities. Raw materials which are used in the production of the exported product and semi-finished goods which are imported from contract manufacturers for use by local manufacturers qualify for this exemption Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

xix. Program 19: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables

a. Submission by the Domestic Industry

135. The Domestic Industry has submitted that since it is the policy of the government not to impose taxes on spares and consumables used directly in manufacturing process where import duties are nil and not produced locally, tax exemption-Revenue forgone is given where imported spares and consumables are taxable but not available locally. An exemption is given on import duty and sales tax. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

136. GOM has stated that the program provides import duty exemption on spares and consumables to qualified manufacturer. MIDA issues a letter to confirm the status of the manufacturer. The program involved evaluating import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD, MIDA and IPC. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. No changes are anticipated to the program. It has also stated that this program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The laws and regulations governing this program are contained in Customs Duties (Exemption) Order 2017.

c. Examination by Authority

137. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on spares and consumables. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority (MIDA). The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is subject to fulfilment of certain criteria. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

xx. Program 20: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment

a. Submission by the Domestic Industry

138. The Domestic Industry has submitted that since it is the policy of the government not to impose taxes on machinery and equipments used directly in manufacturing process and not produced locally, tax exemption-Revenue forgone is given where imported machinery and equipment are taxable but not available locally. Full exemption is given on import duty and sales tax. For locally purchased machinery and equipment full exemption is given on sales tax from Licensed Manufacturing Warehouse, Bonded Warehouse or Free Zone. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

139. GOM has submitted that the program provides import duty exemption on machinery and equipment to qualified manufacturer. MIDA issues a letter to confirm the status of the manufacturer. The manufacturer then claims for exemption. To qualify for the exemption, the machinery and equipment must be new, unused and directly used in the manufacturing process of the finished product at the approved manufacturer's premise(s). All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. No changes are anticipated to the program. It also submits that this program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The laws and regulations governing this program are contained in Customs Duties (Exemption) Order 2017.

140. The companies under investigation conformed with the eligibility criteria which are under MIDA's purview.

c. Examination by Authority

141. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on new and unused machinery and equipment to qualified manufacturer. involved evaluating import duty exemption on machinery and equipment to qualified manufacturer. The program is administered by the Malaysian Investment Development Authority.

142. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to certain enterprises that import new machinery and equipment for manufacturing activity. Therefore, this program is noted to be countervailable.

143. **Xinyi Solar**: It has not availed the benefit under the program. The Authority determines that countervailing duty should not be imposed against this program to Xinyi Solar.

144. **SBH Kibing Solar New Materials (M) SDN. BHD**: The information and documents furnished by the exporter in its response, as well as during the desk verification, denote that the exporter has availed benefits under the program. Accordingly, the Authority notes that countervailing duty is warranted against this subsidy program.

xxi. Program 21: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components

a. Submission by the Domestic Industry

145. The Domestic Industry has submitted that under this program, full exemption from import duty on raw materials/components is normally granted, provided raw materials/components are not produced locally or if produced locally, they aren't of acceptable quality and price. This is regardless of whether the finished products are meant for export or domestic market. The eligibility is that the companies should be involved in manufacturing activities.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

146. GOM has stated that the laws and regulations governing this program are contained in section 14(2) of Customs Act 1967. It provides for import duty exemption on raw material and components to qualified manufacturer. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD and MIDA. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. It has also stated that this program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The companies under investigation conformed with the eligibility criteria which are under MIDA's purview.

c. Examination by Authority

147. Authority notes that the program is governed by Section 14(2) of Customs Act 1967. The program provides for import duty exemption to the qualified manufacturer on raw materials / component that are not locally available. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to an enterprise that uses raw material that are not locally available. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

xxii. Program 22: Double Deduction for Promotion of Exports

a. Submission by the Domestic Industry

148. The Domestic Industry has submitted that under this program tax deduction is given to exporters for expenses which are aimed at promoting exports and supply of goods overseas, cost of maintaining office overseas for purpose of promotion of services, publicity and advertisements in any media outside Malaysia for promotion of export of services. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- Section 41 of Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax promotion of export rules 1986
- WT/TPR/S/292
- WTO-Notification-G/SCM/N/3/MYS-1995
- US carbon steel wire rod from Malaysia

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

149. GOM has submitted that the program which is provided under section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) read together with rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986 is applicable to all resident trading, manufacturing or agricultural companies in respect of expenses incurred in the basis period primarily and principally for the purpose of seeking opportunities, or in creating or increasing a demand for the export of Malaysian manufactured goods or agricultural products. There are no anticipated changes to the program. The deduction can be carried forward.

150. It has further submitted that the applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred overseas for advertising, travelling and related export promotional expenditure. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB.

151. In the case of participation in an international trade fair, companies are required to get a letter of approval from MATRADE.

c. Examination by Authority

152. Authority notes that the program is governed by Section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) & Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986. Under this program double deduction from income to enterprise involved in manufacturing, trading and agricultural activities is available for expenses incurred for promotion of export. Expenses incurred by a company for increasing demand for exports are allowed for double deduction.

153. The Authority further notes that the program provides for financial contributions the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. The benefit is the difference between the amount of income tax paid after double deduction and the amount of income tax that would have been payable in absence of such double deduction. The program is also specific because it is contingent on export performance and is limited to an enterprise engaged in export promotion activity. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters.

xxiii. Program 23: Double Deduction for Promotion of Exports Cargo

a. Submission by the Domestic Industry

154. The Domestic Industry has submitted that under this program an exporter may make a deduction from taxable income for premium insurance on export cargo and regional tax deduction for tax insurance. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

a) Promotion of Investment Act, 1986
b) Income tax promotion of export rules 1986
c) Tax incentives for Companies
d) Other Authority findings

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

155. GOM has submitted that adouble deduction is allowed to a person who incurs premium on the insurance of cargo exported from Malaysia provided that the risks are insured with an insurance company incorporated in Malaysia. The premium paid must be in accordance to section 33 of Income Tax Act 1967. The assistance is a deduction from taxable income. The deduction can be carried forward.

156. This program has been revoked since 2016. Income Tax (Deductions of Insurance Premiums for Exporters) (Revocation) Rules 2012 is given as evidence.

c. Examination by Authority

157. The Authority notes that the program was governed by Income Tax (Deductions of Insurance Premiums for Exporters) Rules 1995 and is revoked by Income Tax (Deductions of Insurance Premiums for Exporters) (Revocation) Rules 2012 since 2016.

xxiv. Program 24: Allowance for Increased Export

a. Submission by the Domestic Industry

158. The Domestic Industry has submitted that this program is a form of tax incentive granted to companies under section 154(1) of Income Tax Act 1967 and Rule 3 of Income Tax (Allowance for increased exports) Rules 1999 and Income Tax (Allowance for increased exports) amendment Rules 2003. An exporter can avail 70% tax deduction from taxable income for increased exports. Also, if the said allowance is not used during the earned year that can be forwarded to the following assessment year. As evidence of existence of the program. Petitioners have relied on:

a) Promotion of Investment Act, 1986
b) Income tax act 1967
c) Customs Act 1967
d) Sales tax Act 1972
e) Excise Act 1976
f) Free trade zones Act 1990

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

159. GOM has submitted that a resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The assistance is an exemption from taxable income. The allowance can be carried forward. There are no anticipated changes to the program. Income Tax (Allowance for Increased Exports) Rules 1999 is given in evidence. The Rules contain the following definitions:

a. agricultural produce means fresh and dried fruits, fresh and dried flowers, ornamental plants and ornamental fish, frozen raw prawn or shrimp, frozen cooked and peeled prawn and frozen raw cattle, fish and squid;
b. export means direct exports not including sales to Free Industrial Zones and Licensed Manufacturing Warehouses;
c. value added means the sale price of goods at ex-factory price less the total cost of raw materials; and

d. value of increased export means the difference of the Free-On- Board (FOB) value of products exported in the basis period and that of the immediately preceding period. FOB value will exclude the freight charges and insurance cost.

160. The allowance is determined as follows:

a. **Manufactured products**

- ➢ 10% of the value of increased exports of the manufactured products by the company where the products exported attained at least 30% of value added;
- ➢ 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company where the products exported attained at least 50% of value added.

b. **Agricultural products**

- ➢ 10% of the value of increased exports of agricultural produce by the Company.

161. The allowance will be given against seventy per cent of statutory business income of the company. Any export allowance not set off would be carried forward to be set-off against seventy per cent of the statutory income in future years.

c. Examination by Authority

162. Authority has examined the submissions of the Domestic Industry as well as the GOM and the other interested parties. It is noted that a resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The allowance is equivalent to 10% or 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company. Allowance will be given against 70% of the statutory business income.

163. Authority further noted that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific because it is contingent on export performance. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporters**.**

xxv. Program 25: Tax Exemptions for Exporters in Free Trade Zones

a. Submission by the Domestic Industry

164. The Domestic Industry submits that Malaysia operates an extensive free zone regime comprising 17 free commercial zones and 18 free industrial zones, which are expressly designed to promote export-oriented activities by providing significant fiscal concessions. Under Section 4 of the Free Zones Act, 1990, goods and services of any description (unless specifically prohibited) may be brought into, produced, manufactured or provided within a free zone without payment of customs duty, excise duty, sales tax or service tax. These statutory exemptions constitute a direct financial contribution by the Government in the form of foregone revenue that would otherwise be due, thereby conferring a benefit on enterprises operating within such zones.

.

165. It is further stated that free commercial zones, including major hubs such as Port Klang, permit companies to import raw materials, components, equipment and machinery free of indirect taxes, substantially lowering input costs and enhancing the competitiveness of export-oriented producers

located in these zones. Access to tax-free imports and production within the free zones is contingent upon location and approval under the Free Zones Act, indicating de facto specificity to enterprises operating within these designated areas. Accordingly, the Domestic Industry contends that the free zone regime amounts to a subsidy within the meaning of the SCM Agreement, as it involves government revenue foregone, confers a measurable benefit, and is limited to a defined group of enterprises operating in free commercial and industrial zones.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

166. GoM has not provided detailed regional incentive program documentation, but has again stressed the ASCM requirements for evidence and the need for proper justification before including any additional subsidy programs. Both the exporters have simply denied any benefit received under this scheme.

c. Examination by Authority

167. The Authority has examined the submissions made by the Government of Malaysia and other interested parties concerning the existence, nature, and quantification of the alleged subsidy programmes, including fiscal incentives and tax-related measures. The Authority notes that the submissions broadly contest the countervailable character of the alleged program, inter alia, on the grounds that such measures do not involve a financial contribution or confer any measurable benefit, are not specific within the meaning of the applicable legal framework, and, in any event, have not resulted in subsidization of the subject goods during the period of investigation.

168. The Authority observes that the Government of Malaysia has not provided specific details on this program and has objected, on procedural grounds, to its examination without sufficient evidence being submitted under Article 11.2 ASCM. Both the exporters have denied having any benefit under this scheme.

169. The Authority has taken note of the information available on record and finds that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific because it is contingent on export performance. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the participating exporters.

i. Program 26: License Manufacturing Warehouse

170. This program was disclosed through the questionnaire response of the exporter as well as the supplementary response of GoM. The petitioner has not made any submission with respect to this plan. The GoM has not provided any submissions with respect to the program.

c. **Examination by Authority**

171. The Authority notes that the program is administered by Royal Malaysian Customs Department. The program is governed by Section 65 and Section 65A of the Customs Act, 1967.

172. The Authority notes that under this program exemption from customs duties and sales tax is given to all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products. It is noted from the responses of the cooperating exporter and GoM that only machinery and equipment required for direct manufacturing process of approved final products are eligible for exemption from customs duty and sales tax under this program. Further, machinery/equipment used directly in the manufacturing process in the LMW is exempted from import duty/sales tax.

173. The Authority notes that this program provides exemption of customs duty and Sales tax on all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products. The subsidy program is also specific because it is contingent on product/enterprise. Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD has admitted to receiving benefit under this program. Therefore, this program is noted to be countervailable.

174. **Xinyi Solar**: The information and documents furnished by the exporter in its response, as well as during the desk verification, denote that the exporter has availed benefits under the program. Accordingly, the Authority notes that countervailing duty is warranted against this subsidy program.

175. **SBH Kibing Solar New Materials (M) SDN. BHD**: It has not availed the benefit under the program. The Authority determines that countervailing duty should not be imposed against this program to the exporter.

F.3.8 Subsidy margin.

176. The subsidy margin determined in the present investigation are as follows:

Subsidy Margin: Xinyi Solar

Program No.	Name of Program	Brief Description	Subsidy Margin	Range %	Nature of Subsidy
Program No. 4	Investment Tax allowance	Exemption of 100% on capital expenditures. The total investment cost on production facilities incurred within the period of ten (10) years from February 2015 can be used to offset the taxable profit incurred since year 2015 till the accumulated ITA is fully utilised.	***	0-10	Tax Incentive/ Revenue Foregone
Program No. 17	Sales tax Exemption	Exemption from payment of sales tax for specific person on acquisition of raw materials, components and packaging material to be used solely and directly in manufacture of taxable goods	***	0-10	Tax Incentive/ Revenue Foregone
Program No. 26	License Manufacturing	Exemption from custom duties and sales tax to all raw	***	0-10	Tax Incentive/

	Warehouse	materials/components used directly in the manufacturing process of approved products regardless of whether the finished products are meant for exports or local market from the initial stage of manufacture until the finished products			Revenue Foregone
			***	0-10	

Subsidy Margin: SBH Kibing SDN BHD

Program No.	Name of Program	Brief Description	Subsidy Margin	Range %	Nature of Subsidy
Program No. 1	Subsidies in Natural Gas	Availability of natural gas at government regulated prices	***	0-10	LTAR
Program No. 4	Investment Tax allowance	Exemption of 100% on capital expenditures. The total investment cost on production facilities incurred within the period of ten (10) years from February 2015 can be used to offset the taxable profit incurred since year 2015 till the accumulated ITA is fully utilised.	***	0-10	Tax Incentive/ Revenue Foregone
Program No. 17	Sales tax Exemption	Exemption from payment of sales tax for specific person on acquisition of raw materials, components and packaging material to be used solely and directly in manufacture of taxable goods	***	0-10	Tax Incentive/ Revenue Foregone
Program No. 20	Sales tax Exemption on Plant and Machinery	Import duty exemption to the qualified manufacturer on raw materials / component that are not locally available	***	0-10	Tax Incentive/ Revenue Foregone
Total			***	0-10	

SECTION III

G. INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made on behalf of the domestic industry.

177. The domestic industry has submitted as follows on the issue of injury and causal link:

a. Despite the presence of the domestic industry and other producers, the imports have dominated the entire market. The imports from subject country constitute remained significant of the market share during the period of investigation.
b. The subsidized imports are undercutting the prices of the domestic industry which is significantly positive during the period of investigation.
c. The subject imports have continuously caused strain on the prices of the domestic industry as they were priced lower than the selling price of the domestic industry throughout the injury period.
d. In the period of investigation, the landed value of the subject goods was below the cost of sales and selling price of the domestic industry. This clearly shows the price pressure on the domestic industry.
e. The subsidized imports have had a suppressing effect on the prices of the domestic industry.
f. The share of the domestic industry in the demand is a meagre, despite having sufficient capacity to meet the substantial portion of the Indian demand.
g. Due to the constant pressure of subsidized imports, the domestic industry has not been able to dispose of its production sufficiently. As a result, the domestic industry was forced to undertake exports to dispose of their inventories to avoid piling up the goods.
h. In the period of investigation, domestic industry has suffered significant cash losses and a negative return.
i. The domestic industry has also submitted that post POI, imports from Malaysia increased significantly.
j. There is a critical need for the continuation of anti-subsidy duty and enhance the quantum, so that Domestic Industry can be adequately protected post duties from China and Vietnam. Without adequate protection, imports from China would shift from Malaysia, as producers in Malaysia are 100% related companies to Chinese producers namely Xinyi and Kibing.
k. The Domestic Industry emphasizes that injury parameters cannot be analyzed in isolation. Domestic Industry has submitted that both price undercutting and price depression exist in the present case. Domestic Industry highlights that all relevant economic factors must be evaluated collectively, even if not all of them may indicate injury.
l. Domestic Industry also provided statistical evidence of injury and submitted that increased installed capacity to meet increasing demand, should not be interpreted as an absence of injury, as claimed by the interested parties. They have also highlighted that there is huge increase in the inventories despite higher production, sales and demand, indicating injurious impact of subject goods from subject countries.
m. It is further submitted that verified data on record shows that Domestic Industry is suffering critically as there are losses, negative return on investment, coupled with increased inventories and reduced capacity utilization declining sales realization and losses, worsening financial performance, and reduced market share.
n. In relation to demand and supply gap, the Domestic Industry submitted that Indian producers can meet substantial portion of Indian demand but has faced challenges due to subsidized imports. It is further submitted that despite added module manufacturing capacities, domestic

glass production has not gone up essentially due to unremunerative prices on account of incessant dumping / subsidy.

o. In relation to quality claims, Domestic Industry submitted that the quality of its goods is at par with imported goods. It is further submitted that the claims of inferior quality by some parties lack factual evidence, as no supporting data or impact on final products has been provided. In relation to specific issues raised by the interested parties, the Domestic Industry has submitted that most of the issues raised by the interested parties barring some stray instances, are not concerned with the product as such. It has been further submitted that transition from "glass-to-back sheet" to "glass-to-glass", technology has increased demand and is unrelated to quality concerns. Further, issues relating to pasting, blasting during lamination, adhesive failure cannot be attributed to quality of glass. None of the interested parties has provided any evidence to show that their modules were downgraded in quality index by their users because of using subject goods produced by Domestic Industry.

G.2 Submissions made on behalf of the other interested parties.

178. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link.

a. Domestic production volumes rose consistently during the period under investigation, disproving claims that imports suppressed production. This growth indicates that the domestic industry managed to increase output despite alleged injury from imports, suggesting that imports did not impede their competitiveness.

b. The injury attributed to imports is overstated because it fails to consider significant external factors, such as raw material price volatility, global inflation, and supply chain disruptions. These factors independently impacted the domestic industry's financial health.

c. The domestic industry’s losses stem from decisions like capacity over-expansion, which strained their financial resources. This expansion resulted in higher depreciation and interest costs, compounding operational inefficiencies. These self-inflicted issues cannot be attributed to imports.

d. The Domestic Industry's claims of injury rely primarily on alleged adverse price effects from Malaysian imports. However, Malaysia’s share in total demand has declined sharply rendering claims of material injury implausible.

e. Demand in India has expanded exponentially and new domestic producers have captured market share, while the Domestic Industry has failed to do so despite operating at high-capacity utilization.

f. The Domestic Industry has also not furnished any analysis establishing likelihood of continuation or recurrence of subsidy or injury, thereby failing the fundamental requirement of a sunset review.

g. Interested parties have highlighted concerns regarding the inability of domestic producers to meet the strict specifications required by global standards for advanced solar modules.

h. That the Domestic Industry does not provide adequate evidence of material injury as required under Annexure I to the Anti-Subsidy Rules. Further, it lacks analysis of key economic parameters such as output, sales, profits, capacity utilization, cash flow, and return on investment, and relies instead on broad unsupported allegations. Without demonstrated deterioration in the domestic industry's performance backed by objective data, the legal threshold to justify initiation is not satisfied.

G.3 Examination by the Authority

179. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject countries.

180. Rule 13 of the Subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provides as follows:

13. Determination of injury-

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the casual link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if –

(i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and

(ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.

181. In relation to quality issues, it is noted that none of the interested parties has provided any concrete evidence related to technical difficulty in achieving specific quality specifications by the Domestic Industry.

182. The Authority has examined the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

Volume effect of the subsidized imports

a. Assessment of demand / apparent consumption

183. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports from Malaysia	MT	91,949	81,937	-	18,916
Imports from Other Countries	MT	1,06,487	3,13,588	8,52,440	7,01,564
Total Imports	MT	1,98,436	3,95,524	8,52,440	7,20,480
% Share of Imports in Total Imports					
Imports from Malaysia	%	46.34%	20.72%	0.00%	2.63%
Imports from Other Countries	%	53.66%	79.28%	100.00%	97.37%
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	240	404
Sales of the Other Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed			100	386
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	169	380	402

184. From the above table, it is clear that the demand of subject goods in India has increased significantly during the injury period.

185. It is also noted that import of subject goods has declined during the injury period both in absolute value and also in relative terms.

b. Volume of Import and Market Share from Malaysia

186. The Authority records the submission of the Domestic Industry that imports from Malaysia surged during the period when anti-dumping duties were in force against China i.e., from August 2017 to August 2022, clearly indicating diversion of trade by producers from China operating through 100% affiliated entities in Malaysia. Following the revocation of duties against China and the commencement of production and exports from Vietnamese company having 100% investment by China-owned companies, imports from Malaysia dropped to zero. However, post imposition of provisional anti-dumping duties on China and Vietnam in December 2024, imports from Malaysia have resumed, reaffirming the pattern of shifting to imports from the sources-controlled by Chinese producers. This demonstrates the significance of extension of duties, to arrest the shifting trade routes influenced by the imposition or revocation of duties. The below-mentioned table provides details of the volume of imports and share of subject country in total imports and demand in India.

Year	**UoM**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI**
Imports from Malaysia	MT	91,949	81,937	0	18,916
Imports from Other countries	MT	1,06,488	3,13,587	8,52,440	7,01,564
Total Imports	MT	1,98,437	3,95,524	8,52,440	7,20,480
Total Demand (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	169	380	617
% Share in Demand					
Subject country	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	-	5
Other Countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	174	211	164

It is noted that the volume of imports from Malaysia has shown increasing trend in the POI as compared to the immediately preceding years i.e., 2022-23.

c. Imports in relation to Production

187. As stated above, the share of imports from the subject country related to the production has declined to zero in 2022-23 from 88.81% in the base year i.e., 2020-21.

Particulars	UoM	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**POI**
Imports from subject country	MT	91,949	81,937	-	18,916
Domestic production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	225	360
% Share of subject country in production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	-	6

d. Price effect of subsidized imports

188. In terms of Annexure I (3) of the Rules, with regard to the effect of the subsidized imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

i. Price undercutting

189. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. It is seen that the price undercutting is positive during the period of investigation.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Landed value	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	-	73
Domestic selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	78	77
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	52	-	93
Price Undercutting %	%	***	***	***	***
Price Undercutting %	Range	20-30	10-20	-	30-40

190. It is seen that the price undercutting from Malaysia has consistently remained positive, indicating that Malaysian imports have been priced below the Domestic Industry's selling price throughout the injury period. The Domestic Industry has also claimed that post imposition of provisional duties on China and Vietnam, Malaysian exporters significantly reduced their landed price from Rs. ***/MT in 2021–22 to Rs***/MT in the POI, intensifying price pressure. This sharp decline led to a steep increase in undercutting margin to ***%, severely impacting the Domestic Industry's pricing ability and market position.

ii. Price suppression/depression

191. In order to determine whether the subsidized imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales Domestic	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	96	86
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	78	77
Landed Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	-	73

192. The Authority notes from the above that the landed value of the imports was below the selling price of the domestic industry throughout the injury period. During the period of investigation, the landed value of the subject goods remained lower than the cost of sales of the domestic industry and its domestic selling price. This prevented the domestic industry from keeping its price in tandem with the cost of sales. It is, therefore, noted that the imports have prevented price increase, which otherwise, would have occurred. Thus, the imports have had suppressing effect on the prices of the domestic industry.

193. Domestic Industry has further submitted that the aggressive pricing by Malaysian exporters has significantly depressed their selling prices, undermining profitability and recovery. Moreover, the demonstrated ability of these exporters to rapidly scale up import volumes within a short span further heightens the threat of intensified injury. These factors clearly indicate a strong likelihood of continued and recurring injury in the absence of trade remedial measures.

iii. **Economic parameters related to the domestic industry**

194. Anti-Subsidy Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of subsidized imports on domestic producers of the subject goods. The Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of subsidy; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

iv. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

195. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	UoM	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
Capacity (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	255	363
Total Production (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	109	241	348
Production of PUC only (MT)	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	109	225	360
Capacity utilization (%)	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	95	96
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	240	404
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	137	145	166

196. It has been submitted by the Domestic Industry that despite a sharp rise in demand more than sixfold from 2021–22 to the POI, they were unable to fully utilize their capacities, with capacity utilization falling from ***% in the base year i.e., 2021-22 to ***% in the POI. It is further submitted that this mismatch between surging demand and suboptimal production clearly indicates that the Domestic Industry could not capitalize on market opportunities due to continued injurious effects of unfair imports from sources subject to trade remedial investigations dominated by Chinese producers. It is further submitted by the Domestic Industry that new capacities have been set up and more are planned to meet this increased protection against Malaysia in terms of extension and enhancement of existing duties.

v. Market share

197. The Domestic Industry has claimed that their market share has declined during the POI as compared to the base year i.e., 2021-22. It is further submitted that since 2015, they are under the continued pressure from Chinese exporters, either directly from China[6] or through strategic investments in Malaysia and Vietnam[7]. The information with respect to change in the market share held by the petitioner, imports from China and imports from other countries is as below.

Market share of	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Demand	MT	***	***	***	***
Share in Demand					
Imports from Malaysia	Indexed	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	-	5
Imports from Other Countries		***	***	***	***
Trend	Indexed	100	174	211	164
Total Imports		***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	113	90
Domestic Sales		***	***	***	***
Trend	Indexed	100	58	63	100
Sales of the Other Producers		***	***	***	***
Trend	Indexed			100	365

198. From the above, it is noted that despite a substantial increase in demand of the subject goods the Domestic Industry's market share remained stagnant at ***% during the POI, reflecting its inability to benefit from rising consumption. Imports from countries attracting duties dominated the market, holding a ***% share in the POI, while Malaysian imports, which previously held a significant share, re-entered with ***%. Domestic Industry further submitted that since exporters in Malaysia are controlled by Chinese producers, in no time share of Malaysia will be significant and dominant.

[1]. Anti-dumping duties on Chinese imports were in effect from 18.08.2017 to 17.08.2022 and fresh duties will be effective from 4.12.2024 to 3.12.2029. during which imports from China declined significantly.
[2]. Anti-dumping duties against Vietnam effective from 4.12.2024 to 3.12.2029.

199. The Domestic Industry has further submitted that, for a meaningful assessment of import impact, the Authority should consider the combined share of imports from Malaysia, China, and Vietnam, as these are effectively controlled by the same set of Chinese producers. These exporters, often operating through entities in Hong Kong, strategically use multiple jurisdictions to channel their exports into India. This coordinated arrangement enables convenience of choosing supply source and continues to severely restrict the Domestic Industry's ability to expand its market presence despite rising demand.

vi. Profitability, cash profits and return on investment.

200. Information with respect to profitability, return on investment and cash profits was as follows:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Net Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	78	77
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	108	96	86
Profit before Tax	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-342	-499	-300
Interest	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	237	670	290
PBIT	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-348	-488	-301
Depreciation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	54	174	257
Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-523	-703	-327
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-166	-106	-99

201. The Domestic Industry has submitted that they have expected recovery following the imposition of anti-subsidy duties on imports from Malaysia in March 2021. However, the non-extension of duties against China despite DGTR's positive recommendation alongside increasing imports from Vietnam, allowed Chinese exporters to exploit these alternate routes and flood the Indian market. Domestic Industry has further submitted that throughout this period, Chinese-origin exporters, operating through China, Malaysia, and Vietnam, continued to depress domestic prices, causing sustained injury. This influx of unfairly priced imports eroded the Domestic Industry's profitability, restricted price increases to remunerative levels, and prevented recovery of cash profits and return on capital employed. The Domestic Industry, therefore, requested the Authority to recommend continuation of anti-subsidy duties to provide effective protection and enable long-overdue recovery.

vii. Productivity, employment, and wages

202. Information with respect to productivity, employment and wages over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No of employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	138	224	215
Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	77	202	475
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	225	360

203. It is seen that the number of employees increased over the injury period due to enhancement of the capacities. It is submitted that the productivity of the domestic industry has also increased indicating that increase in employment has not cause any productivity loss. The wages paid have also increased during such period.

viii. Inventories

204. The inventories of the domestic industry have increased in the period of investigation as compared to any of the previous years. The domestic industry has claimed that this shows the injurious effect of the dumped imports. Information with respect to the inventory with the domestic industry is as below:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	278	415	506

205. The level of inventory of the applicant is significant and highest during the POI as compared to any of the previous years.

ix. Growth

206. The growth also follows the same trend as followed by profitability, cash flow and ROCE. The growth parameters show a negative growth for most of the parameters. The details are provided in the table below.

Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Production	%	-	9%	106%	60%
Market share of Domestic Industry	%	-	-42%	8%	4%
Capacity utilization	%	-	-3%	-3%	1%
Inventory	%	-	178%	1534%	210%
Profit	%	-	422%	-38%	6%
Cash Profit	%	-	477%	-10%	1%
ROCE	%	-	137%	-34%	5%

x. Ability to Raise Capital Investments

207. The applicant has also claimed that presence of significantly low-priced imports in the market has impacted its ability to raise investments for any additional capacity expansions. It has been submitted that if the present scenario continues, its investment is likely to be highly unutilized and no new investment will come.

208. The Domestic Industry submitted that due to the emphasis of the Government of India on renewable sources of energy, the growth in the Solar energy is imminent. Since the subject goods are used in Solar Module, there is a huge scope of investment in this sector. Even applicants have also increased its capacity to cater to the increased demand. The fact that they got protection against dumped imports from China and also against subsidized imports from Malaysia, new investment had come. Further, duties against China and Vietnam the sector is positive for further investments. However, at this stage, if duties are not continued against Malaysia, Indian market will again be flooded by Chinese imports and protection given against China and Vietnam, will practically become ineffective. In the absence of anti-subsidy duties, there will be no new investment. In view thereof, it has been submitted by the Domestic Industry that seeing the positive demand and legitimate protection against unfair trade practices, the investment option remains open for the Domestic Industry. However, in the event duties are not extended, the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector will be seriously jeopardized.

Conclusion on material injury

209. An examination of the various parameters of injury along with the volume and price effects of imports reveals that imports of subject goods from the subject country during the POI remained constant due to existence of the anti-subsidized duties. However, there is an adverse price effect as evidenced from the table showing price undercutting and price suppression and depression. With regard to impact of adverse price effect on the domestic industry, it is noted that capacity utilization has declined despite increase in demand. Further, it is also noted that profitability, cash profit and ROCE of the domestic industry have been adversely affected on account of dumped imports of subject goods from the subject country.

Causal Link

xi. **Non-Attribution Analysis**

210. The Rules require the Authority to examine factors other than the subject imports that are causing or may cause injury to the domestic industry to avoid erroneous attribution of injury caused by such other factors to subsidized imports.

211. The Authority notes that the present proceedings are a sunset review and the causal link between subsidization and injury has already been established in the original investigation. The Authority has examined whether other known factors, as provided in the Rules, have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

(i) **Volume and price of imports from third countries**

212. The imports from the countries other than Malaysia and countries already attracting anti-dumping / anti-subsidy duties accounted for less than 3% in total imports. Thus, it cannot be said that imports from other countries are currently causing injury.

(ii) **Export Performance**

213. It is noted that the injury information examined by the Authority is for domestic operations and therefore possible changes in exports volume have not caused injury to the Domestic Industry.

(iii) **Development of Technology**

214. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. It is further noted that technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

(iv) **Performance of other products of the company**

215. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the domestic industry.

(v) **Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers**

216. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

(vi) **Productivity of the Domestic Industry**

217. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has increased over the period.

(vii) **Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption**

218. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it can be concluded that the injury to the Domestic industry was not due to contraction in demand.

Examination of injury and causal link:

219. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry.:

a) Imports are undercutting the prices of the domestic industry;
b) Positive and significant price undercutting caused by the subsidized imports is preventing the domestic industry from increasing its prices to remunerative levels;
c) Due to the decline in the import prices, the domestic industry is forced to incur losses in the POI;
d) The growth of the domestic industry has been declining in terms of number of price related economic parameters like profit, return on capital employed and cash profits etc., as a result of subsidized imports of the subject goods from the subject country;
e) Market share of the subsidized imports in demand increased and consequently, market share of the domestic industry declined.
f) The inventory level of the PUC of the Domestic Industry was highest during the POI.
g) There were no constraints such as raw material shortages, power shortage, tax, capacity/investment constraints, etc., on the operations of the Domestic Industry concerning the PUC

xii. **Magnitude of Injury and Injury Margin**

220. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure-III to the Rules, as amended from time to time. The NIP of the domestic like product has been determined by adopting the verified information/data

relating to the cost to make and sell for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out in accordance with Annexure III to the Rules. For determining NIP, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilization and the same production has been considered for arriving per unit fixed costs. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being consistently followed by the Authority. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country to determine the injury margin.

Producer	**NIP**	**Landed value**	**Injury Margin**	**Injury Margin**	**Injury Margin**
	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
Kibing Group (M) Sdn. Bhd	***	***	***	***	80-90
Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.	***	***	***	***	40-50
Others	***	***	***	***	80-90

H. Likelihood Of Continuation Or Recurrence Of Subsidization And Injury

221. In accordance with Rule 24(3), the Authority is required to examine the likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury in the event of expiry of duties. The Authority has examined all material placed on record relating to the likelihood of continuation or recurrence of injury, along with such other factors relevant to and having a bearing on the question of likelihood of continuation or recurrence of injury.

i. Continued subsidisation

222. The Authority notes that subsidization of the subject goods has continued in the period of investigation in the subject countries. Therefore, the Authority considers that subsidization is likely to continue.

ii. New Investment in Malaysia

223. The Domestic Industry based on the market reports and public information, submitted that new producer i.e., Kibing Solar Glass has set up their new plants to manufacturer subject goods. The details of new investment of subject goods are as follows:

a. Nippon Sheet Glass[8] Co., Ltd.: Their capacities will be operational from fourth quarter of 2024 in Malaysia.
b. Xinyi Solar Malaysia, two[9] lines having capacity of 1200 MT.
c. China-based Kibing Group[10] is set to establish a large solar glass manufacturing plant in Kimanis, Sabah with installed capacity of 25 gigawatts (GW).

[3]. New Production Line of Solar Glass in Malaysia (nsg.com)
[4]. Page 11 of interim report 2022 i Xinyi Solar Holdings Limited
[5]. https://www.saurenergy.asia/kibing-group-to-build-usd-1-5-billion-solar-glass-plant-in-malaysia/

224. Based on the above data, Domestic Industry has submitted that with increased capacity and limited demand, in case duties are not extended, there is every likelihood that dumped imports from the subject countries will flood the Indian market to the detriment to the Indian producers.

iii. Attractiveness of the Indian market:

225. It is submitted by the Domestic Industry that the Indian market is very attractive to the producers / exporters from Malaysia or Chinese exporters either situated in China, Malaysia or Vietnam. It is further submitted that the demand for the subject goods increased during the injury investigation period. Furthermore, the industry's growth prospects remain strong. It is also submitted that India continues to be an attractive market for foreign producers and exporters, as evidenced by the sustained imports from despite the imposition of anti-dumping duties.

226. In addition to above, Domestic Industry has also submitted that based on the Trade map data India holds fourth position in the export destination for the producers// exporters from Malaysia.

iv. Increased imports from Malaysia post imposition of anti-dumping duties against China and Vietnam:

227. It is noted that post imposition of provisional duties against China and Vietnam in December 2024, imports have increased manifold from Malaysia. The month-wise imports during POI and post POI are provided below to show the aggressiveness of the exporters from Malaysia.

Qty-MT	Month	Total Imports
POI	Jan-24	0
POI	Feb-24	0
POI	Mar-24	0
POI	Apr-24	0
POI	May-24	0
POI	Jun-24	0
POI	Jul-24	0
POI	Aug-24	0
POI	Sep-24	474
POI	Oct-24	0
POI	Nov-24	2,870
POI / PF	Dec-24	14,832
Post PF	Jan-25	29,352
Post PF	Feb-25	67,908
Post PF	Mar-25	67,120
Grand Total		
Imports during POI		**18,916**
Imports (Jan-March 25) Post imposition of PF		**1,64,380**

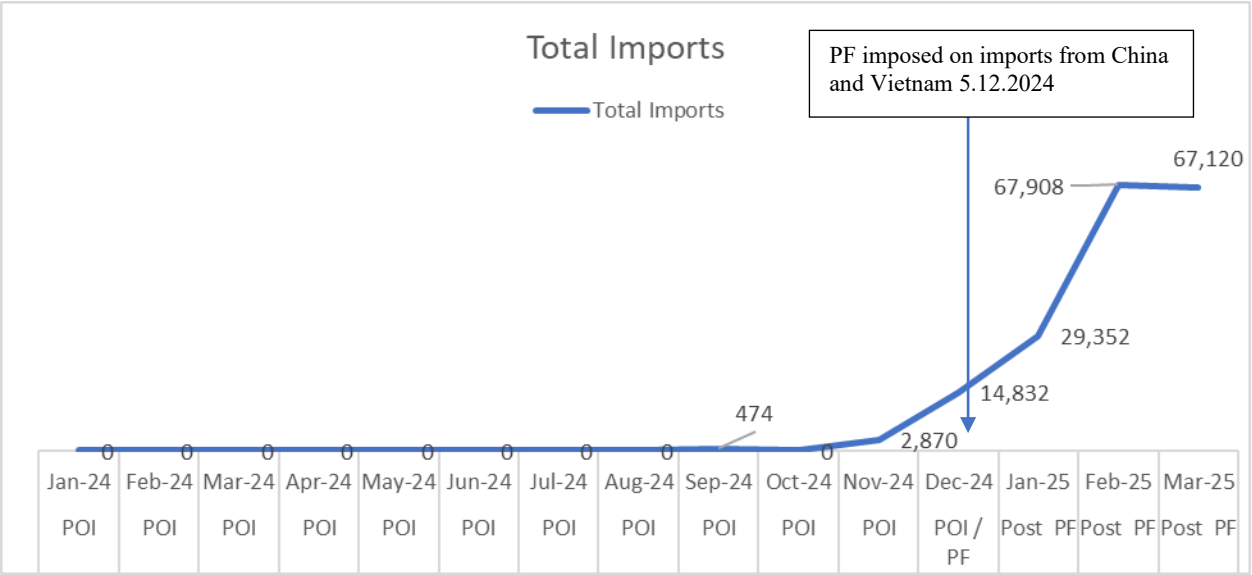

228. From the above graph, the Authority observes that the imports have increased substantially, post imposition of duties against China and Vietnam in December 2024, indicating clear likelihood of increased subsidized imports and injury to the Domestic Industry.

229. The Authority also notes the submissions of the Domestic Industry that, in view of the significant surplus capacities in Malaysia and the rising trend of imports post-POI there is a high probability that exports from Malaysia will once again flood the Indian market. This reinforces the critical need for extension and enhancement of anti-subsidy duties. The Domestic Industry has claimed that they will provide further substantiation of this likelihood during the course of the investigation, and its claims. The Authority during the course of the investigation will verify the projections through actual data submitted by Malaysian producers/exporters / government during the investigation process.

v. **Likely Quantities below the Non-injurious Price of the domestic industry**

230. It is noted from the responses of the cooperative exporters that Malaysian exporters have exported ***MT of the subject goods to countries other than India. Out of this quantity, ***MT is priced below the NIP computed by the Authority. The details are provided in the Table below:

Particulars	UOM	Xinyi	Kibing	Total
Quantity exported to third countries	MT	***	***	***
Quantity exported below NIP	MT	***	***	***
% of quantity below NIP (injurious quantity)	%	***	***	***
Range	%	70-80	70-80	70-80

vi. **Likely Quantities below the Domestic Sales price of the domestic industry**

231. It is also noted from the responses of the cooperative exporters that Malaysian exporters have exported ***MT of the subject goods to countries other than India. Out of this quantity, ***MT is priced below the domestic sales prices of the domestic industry. The details are provided in the Table below:

Particulars	UOM	Xinyi	Kibing	Total
Quantity exported to third countries	MT	***	***	***
Quantity exported below Domestic Sales Price	MT	***	***	***

% of quantity below Domestic Sales Price	%	***	***	***
Range	%	30-40	60-70	40-50

I. ISSUES OF THE INDIAN INDUSTRY

I.1 Submissions made by other interested parties

232. The other interested parties, including users and downstream solar module manufacturers, have inter alia submitted that:

i. Imposition or continuation of countervailing duties may increase procurement costs of textured tempered glass ("TTG"), which constitutes an important input for solar photovoltaic modules.

ii. Any increase in input cost may adversely impact competitiveness of downstream manufacturers operating in a globally competitive renewable energy market.

iii. The solar manufacturing sector is capital intensive and price sensitive; therefore, higher glass prices could affect module pricing, exports, and project viability.

iv. It has been argued that domestic availability of specialized variants of TTG, including advanced or application-specific glass used in newer module technologies, remains limited and downstream users may continue to depend on imports to ensure uninterrupted production.

v. Concerns were also raised that restrictions on imports may affect product quality, technological flexibility, and supply reliability for module manufacturers.

I.2 Submissions made by the Domestic Industry

233. The domestic industry has submitted that:

i. The objective of countervailing duty is to neutralize unfair subsidization and restore fair competition rather than restrict imports.

ii. The domestic industry has made substantial investments in TTG manufacturing and possesses the technical capability to supply the Indian market, while ongoing and planned capacity expansions are expected to improve supply availability.

iii. The presence of a viable domestic industry ensures supply security for a strategically important product used in solar energy generation.

iv. The impact of duties on downstream products is minimal because TTG constitutes only a small proportion of the total cost of solar modules.

v. Continuation of unfairly subsidized imports would undermine domestic manufacturing, discourage investments, and increase long-term import dependence, which would be contrary to national objectives of supply chain resilience and "Atmanirbhar Bharat".

vi. A healthy domestic industry historically contributed to price stability and market development and therefore supports, rather than harms, downstream industries.

A.1 I.3Examination by the Authority

234. The Authority notes that the purpose of countervailing duties under the Customs Tariff Act and Anti-Subsidy Rules is to offset the injurious effect of subsidized imports and to restore conditions of fair competition in the domestic market. Such measures are not intended to restrict availability of goods or create artificial price escalation but to neutralize distortions caused by actionable subsidies.

235. The Authority invited views from all stakeholders, including producers, importers, users, and downstream industries, and circulated Economic Interest Questionnaires seeking information regarding:

- interchangeability of supplies,
- availability of domestic production,
- impact of duties on downstream industries,
- adjustment capability of users, and
- effect on consumers and national industrial interest.

236. While downstream users expressed concerns regarding possible cost implications, the Authority notes that no verifiable financial analysis or quantified evidence was submitted demonstrating material adverse impact on profitability, exports, or employment of downstream manufacturers.

I.4 Demand, Supply and Strategic Considerations

237. The Authority observes that TTG is a critical input used in solar photovoltaic modules, a sector witnessing rapid expansion in India owing to renewable energy targets. Evidence on record indicates that demand growth is driven by technological transition towards glass-to-glass modules and higher efficiency solar panels, resulting in increased glass consumption.

238. The Authority further notes that while demand has expanded rapidly, continuation of subsidized imports at unfair prices would undermine domestic manufacturing viability and discourage further investments necessary to bridge the demand–supply gap in the medium term.

I.5 Availability of Product

239. The Authority notes that imposition or continuation of countervailing duty does not prohibit imports. Imports may continue to enter the Indian market, albeit at fair and unsubsidized prices. Therefore, availability of TTG to downstream users is unlikely to be adversely affected.

240. The Authority further observes that multiple sources of supply remain available, including domestic producers, imports from subject country at fair prices, and imports from other countries.

I.6 Impact on Downstream Industry

241. The Authority has examined the likely impact of duties on downstream solar products. Based on information placed on record, the share of TTG in the total cost of downstream products remains limited. The estimated impact is illustrated below.

I.7 Estimated Impact of Duty on Downstream Products

The Authority, however, notes that the possible impact of the anti-subsidy duties on the end consumers in the following table:

Particulars	Reference	UoM	Amount
Price of 540 Wp solar module based on M10 solar cells	A	Rs. / Module	9,000
Subject goods used in 540 Wp solar module based on M10 solar cells	B	Kgs./Module	20.05
Price of Subject goods – Coated	C	Rs./Kg.	42.01
Costs of subject goods build in 540 Wp solar module based on M10 solar cells	D=C*B	Rs/MT	842
% cost of subject goods in Module	E=D/A	%	9.36%
Additional cost on Module due to 10% anti subsidy duties on subject goods	F=D*10%	Rs/MT	84
Total cost of subject goods in module adding anti-dumping duties	G=D+F	Rs/MT	927
% cost of subject goods in Module	H=G/A	%	10.30%
Additional impact per Solar Module due to anti-dumping duties	I=F/A	%	0.94%

Source: Authority's analysis based on submissions on record.

242. The Authority notes that even assuming full pass-through of duties, the impact on final downstream products remains **well below 1%,** which is economically insignificant in comparison to overall module pricing fluctuations driven by global polysilicon, wafer, and logistics costs.

J. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

243. The post disclosure submissions have been received from the interested parties, and it is noted that most of the issues raised are reiterations and have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions have been analyzed as under:

J.1 Submission made by the Domestic Industry

244. The submissions made by the Domestic Industry are as under

i. That the responses filed by the so-called participating producers/exporters, Xinyi and Kibing, ought to be disregarded as they have withheld critical information and misled the Authority by submitting incomplete and inaccurate data. These deficiencies have a direct and significant impact on the determination of subsidy margins and undermine the integrity of the investigation.

ii. The exporters have, also failed to disclose the involvement of related companies in export sales, while Kibing has not reported regional subsidies despite publicly available evidence. It is further submitted by the Domestic Industry that there are indications that Xinyi may be benefitting from gas-related subsidies which require verification.

iii. That any leniency extended to such exporters would amount to rewarding non-compliance and misrepresentation. Domestic Industry has further also submitted that the Authority has previously taken a strict view in similar situations and the same approach is warranted here in order to ensure that only complete, accurate, and verifiable information is relied upon in the determination and reject the exporter questionnaire responses of Xinyi and Kibing and subject them to residual anti-subsidiary duty based on facts available on record.

iv. The Authority is also requested to confirm in the final findings that the subject goods are also known as heat-strengthened glass. It is further requested to confirm that the Government of Malaysia continues to provide subsidies, and that subsidized imports are causing material injury to the Domestic Industry.

J.2 <u>Submissions made by the other interested parties</u>

245. The submissions made by the other interested parties are as under:

i. The Domestic Industry violated confidentiality provisions by not adequately disclosing documents relied upon for subsidy allegations and by treating publicly available financial statements as confidential

ii. The Domestic Industry has already enjoyed prolonged protection through ADD and CVD measures and that further continuation would amount to undue and perpetual protection, contrary to the temporary and remedial nature of trade remedies.

iii. Kibing claims it cooperated fully and disclosed participation in programs such as natural gas, investment tax policies, sales tax exemptions, and import duty exemptions. It argues that benefits under the Investment Tax scheme were not received by the respondent itself and that exemptions on machinery imports arose from FTA concessions (Form-E), which allegedly cannot constitute a financial contribution or specific subsidy.

iv. The Domestic Industry has expanded capacity, production, investment, employment, and exports, showing positive performance trends. It argues that any decline in profitability is due to expansion costs, internal inefficiencies, and business decisions rather than Malaysian imports, and that injury claims are exaggerated or artificial. It is further submitted that imports from Malaysia have declined overall and that any surge in total imports is attributable to China and Vietnam. It is further submitted that imports from Malaysia were necessary to bridge demand–supply gaps and that cumulative assessment with other countries lacks evidentiary basis.

v. The Disclosure Statement does not establish likelihood of continuation or recurrence of injury, contending that the Domestic Industry has expanded capacity and sales, imports from Malaysia have declined, and no causal link has been demonstrated. It further argues that the Authority's likelihood conclusions are speculative and unsupported by evidence of surplus capacity, export orientation toward India, or any basis to assume a potential surge of imports.

vi. Kibing disputes the finding that its exports undercut or suppress domestic prices and claims its landed value reflects fair market pricing and requested termination of the investigation on the grounds that subsidy, injury, and causal link are not established.

vii. Continuation of duties would adversely affect downstream solar and renewable sectors by restricting access to competitively priced glass, increasing module costs, and burdening consumers. It further contends that the Domestic Industry has strengthened its position and that continuation of the measure would undermine fair competition and public interest.

viii. Xinyi Solar has requested the Authority to reexamine and recompute landed value by adding freight and insurance to FOB transactions. They have also requested the Authority to consider average

useful life of assets as 16.72 years instead of 10 years, as the same is inconsistent with the Company's audited financial statements prepared under GAAP.

ix. That Sales and Services Tax on raw materials used for export production is either exempt or refunded, so no residual tax burden remains. Therefore, SST cannot constitute a financial contribution or confer a benefit and should not be treated as a countervailable subsidy. Xinyi compares this mechanism to India's GST zero-rating of exports.

x. Xinyi argues that the findings of the original investigation are under challenge before CESTAT and therefore cannot be presumed final. Since the legality and quantification of alleged subsidies are under judicial examination, continuation of duty based on those findings would be premature and legally vulnerable.

J.3 Examination by the Authority

246. The Authority notes that most of the submissions made by interested parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above *ipso facto* deal with these arguments of interested parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.

247. As regards the contention of the Domestic Industry that the responses filed by the participating exporters are incomplete and misleading, the Authority notes that the information submitted by the exporters has been examined in accordance with the applicable Rules and, where necessary, verified to the extent feasible. The determination of subsidy margins has been based on verified information on record, supplemented where appropriate by facts available in instances of gaps or inconsistencies. Accordingly, the Authority does not find sufficient grounds to disregard the exporter responses in their entirety and has relied on the information considered appropriate for the purpose of the determination.

248. As regards submission made by the Domestic Industry related to involvement of related entities in the exports to India, non-reporting of alleged regional subsidies, and possible gas-related benefits by participating exporter, the Authority clarifies that the assessment of subsidization in the present investigation is based on information placed on record by the exporters, responses to verification queries, and other evidence examined during the course of the investigation. Wherever additional clarification was required, the Authority sought and evaluated relevant information and has reflected its conclusions in the subsidy determination accordingly. Allegations based solely on indicative or publicly available material, without supporting verifiable evidence demonstrating actual receipt of benefits, do not by themselves justify modification of the findings beyond what has already been established on record.

249. The Authority does not agree with the Domestic Industry's contention that reliance on exporter responses would amount to rewarding non-compliance. The Authority's determination is not based on any presumption of cooperation but on an objective examination of the information placed on record, verified data, and, where warranted, facts available in accordance with the Rules. The Authority has exercised due diligence in assessing the completeness and reliability of the information furnished and has drawn appropriate conclusions based on verified data. Accordingly, the allegation that the Authority has shown leniency or departed from its established practice is not correct.

250. The Authority has examined the Domestic Industry's submissions regarding the description of the product under consideration and the existence of subsidization and injury. The findings on these

aspects have been addressed in the relevant sections of the Final Findings on the basis of the evidence on record.

251. As regards the claim of confidentiality by Domestic Industry, the Authority observes that confidentiality claims are examined in accordance with the applicable Rules, and information is treated as confidential only where good cause is shown. The Authority further ensures that adequate non-confidential summaries are placed on record to enable interested parties to reasonably understand the substance of the information relied upon. Interested parties have not demonstrated that they are prevented from effectively defending its interests in the investigation and therefore, this contention is without merit.

252. In relation to submission that continuation of duties would amount to prolonged protection for the Domestic Industry, the Authority, notes that trade remedial measures are continued only where, upon an objective examination in a sunset review, cessation of the measure is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury. The continuation of a duty is thus not automatic nor protective in nature, but is strictly contingent upon the existence of unfair trade practices and their injurious effects. The exporter has not placed any evidence on record to demonstrate that subsidization has ceased or that the Domestic Industry would remain insulated from injury in the absence of the measure. Accordingly, the Authority finds that continuation of the duty, where warranted by the facts, does not constitute undue protection but remains a legitimate remedial response, and thus contention of the exporters is not correct.

253. As regards the contention that Kibing has fully cooperated and that certain program either did not confer benefits or arose merely from FTA concessions, the Authority, notes that during the course of verification, it identified the existence of certain subsidy elements which were not initially claimed or adequately substantiated by the exporter. The determination of subsidization in the present investigation is therefore based on verified information obtained during verification, supplemented where necessary by facts available in instances where complete or reliable information was not furnished. The Authority emphasizes that the use of verified data and, where warranted, best information available, is consistent with the Rules and ensures an objective assessment of subsidization. Even post disclosure comments also, exporter has not substantiated their claims and therefore, the contention that Kibing has suffered prejudice in the determination of subsidy margins is unfounded.

254. As regards contention that the Domestic Industry is not suffering any injury or injury is not on account of Malaysia, it is noted that that improvement in certain parameters does not preclude the existence of injury where the evidence on record demonstrates price suppression, adverse profitability trends, and vulnerability of the Domestic Industry in the event of cessation of duties. The exporter has not placed substantiated evidence to demonstrate that imports from Malaysia were at non-injurious prices or they are not getting any subsidy from the Government of Malaysia, or that they did not exert adverse price effects on the Domestic Industry. Further, the assertion that imports merely bridged demand–supply gaps or that cumulative assessment is unwarranted remains unsupported by verifiable data. The Authority therefore finds that submissions are based on selective interpretation of indicators and do not rebut the injury and likelihood analysis on record, and accordingly rejects the same

255. The Authority has re-examined the landed value calculation and used the corrected landed value for the purpose of present final findings. in relation to submission of average useful life, the Authority notes that the data on record shows that the Authority has correctly considered the average useful life of assets as 10 years based on verified information submitted by the exporter.

256. The contention of the exporter that Sales and Services Tax (SST) on inputs used for export production is either exempt or refunded and therefore cannot constitute a countervailable subsidy is misplaced. Under the subsidy framework, remission or exemption of indirect taxes on inputs can be treated as a financial contribution where such remission exceeds the amount actually levied on inputs consumed in the production of exported goods or where the scheme is not strictly limited to neutralization of prior-stage taxes. The exporter has not demonstrated, with verifiable evidence, that the SST exemption/refund mechanism operates as a permissible duty drawback system strictly limited to inputs consumed in the exported product. In the absence of a transparent and product-specific verification mechanism ensuring that remission does not exceed taxes actually incurred, such tax foregone constitutes revenue otherwise due to the government and therefore represents a financial contribution conferring a benefit. The comparison with India's GST zero-rating framework is inapposite, as the countervailability of a measure must be examined on the basis of its design, operation, and verification in the exporting country. Accordingly, the Authority considers that the SST treatment extended to the exporter is countervailable in nature.

257. As regards, the contention of the Xinyi that the findings of the original investigation are under challenge before the Hon'ble CESTAT and therefore, cannot be presumed final. In this regard, the Authority observes that the mere pendency of an appeal does not render the findings of the original investigation inoperative or devoid of legal effect. Unless and until the findings are set aside or modified by a competent appellate forum, they continue to remain valid and enforceable.

258. As regards submission that likelihood findings are unsupported by any positive evidence and amounts to mere assertion, it is noted that likelihood analysis in a sunset review is necessarily prospective and is based on objective evaluation of subsidization, market conditions, and exporters' ability and incentive to increase shipments in the absence of measures, and the Authority in the sunset review has examined if subsidization and injury would cease or not recur upon expiry of the duty.

259. With regard to the submission related to extension of duties would not be public interest, it is noted that the said claims are unsubstantiated and unsupported by any evidence on record. Countervailing duties are imposed to neutralize the injurious effects of subsidized imports and restore fair competition, and cannot be construed as a restriction on legitimate supply. In the absence of substantiated evidence demonstrating any disproportionate adverse impact on downstream industries or consumers, the Authority finds no merit in the contention and rejects the same.

K. CONCLUSION

260. The Authority, upon examination of the issues raised in the course of the proceedings, arguments advanced by all interested parties and the facts and evidence on record, concludes as follows:

a. The application for the present sunset review has been filed by M/s Borosil Renewables Limited (BRL) and Vishakha Glass Pvt. Ltd. (VGPL). The costing and injury data, as per the prescribed formats, is based on their data. The applicants satisfy the requirement of standing and constitute 'domestic industry' within the meaning of Rules 6(3) and 2(b) of the CVD Rules, 1995.

b. The scope of the product under consideration determined at the time of the original investigation does not warrant revision. Therefore, the product under consideration is 'Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds

1500 mm, whether coated or uncoated. However, for the same of clarity, the Authority has added Heat Strengthened Glass as one of the other names of the product under consideration.

c. The goods manufactured by the domestic industry are like article to the subject goods imported from Malaysia.

d. The Government of Malaysia has not filed response for the 'new subsidies' investigated in the sunset review. Therefore, determinations in respect of these schemes have been made based on facts available

e. The interested parties have not produced any evidence of termination of previously countervailed schemes. Further, the previously countervailed schemes have been countervailed in subsequent investigations. Therefore, the Authority considers that the schemes countervailed in the original investigation have continued in the present period of investigation.

f. Producers of the subject goods in Malaysia have continued to benefit from countervailable subsidies.

g. The position of the domestic industry is vulnerable during the present period of investigation. Further, based on the evidence on record, there is clear indication of likelihood of continuation or recurrence of subsidisation and injury from Malaysia in the event of cessation of duties.

h. Based on the information on record, it is seen that the producers from Malaysia are export oriented. The producers have set up capacities which far exceed the demand in the country.

i. The exports from Malaysia to other countries are at injurious prices and there is a likelihood of injury to the domestic industry in event of expiry of measures.

L. RECOMMENDATIONS

261. The Authority notes that the present proceedings were conducted in accordance with the applicable law. All interested parties were duly notified and were afforded adequate opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including subsidisation, injury, causal link, likelihood of continuation or recurrence of subsidisation and injury and impact of the measures on the Indian industry.

262. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of subsidisation and injury if the existing countervailing duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-subsidy/countervailing duties in force on the imports of the product under consideration from the subject country is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing anti-subsidy/countervailing duties on the imports of the subject goods from the subject country. Accordingly, the anti-subsidy/countervailing duties for producers from Malaysia are recommended as per duty table below.

263. Having determined that there is likelihood of continuation/recurrence of subsidy and injury to the domestic industry in the present matter if the existing countervailing duties is withdrawn, it is considered appropriate to continue the existing countervailing duties on import of subject goods from Malaysia without any modification in the current quantum of duties keeping in view the factual matrix of the present investigation.

264. However, the Authority also notes that an exporter namely Kibing Group (M) Sdn. Bhd (Kibing) has participated in the present sunset review investigation who did not participate at the time of original investigation. The exporter has cooperated during the present sunset review and the data submitted by the exporter was also verified by the Authority through desk verification. In the factual matrix of the present investigation, the Authority deems it appropriate to determine individual countervailing duty rate for Kibing. However, keeping in view the fact that there is a likelihood of continuation/recurrence of subsidy and injury in the event of expiry of existing countervailing duty in the present investigation, quantum of countervailing duty for the said producer/exporter cannot be determined solely based on the principle of countervailing duty equal to the margin of subsidy or less like in a fresh investigation as provided under Rule 4 (d). The current countervailing duty applicable on imports of subject goods from Malaysia covers countervailing duty that was determined by the Authority for the cooperating producer/exporter who participated in the original investigations and also the duties applicable for the non-cooperative producers/exporters. Since the existing countervailing duties is being recommended to be continued on the imports of subject goods from subject country in the present sunset review, the Authority deems it appropriate to recommend the existing countervailing duty rate applicable for the cooperating exporter for Kibing also.

265. Thus, in terms of the provision contained in Rule l9(1)(b) read with Rule 24 (3) of the Anti-Subsidy Rules, the Authority, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of existing countervailing duties equal to the figure indicated in Column 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from Malaysia. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, countervailing duty equal to the amount indicated in Column 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods, originating in or exported from Malaysia.

Duty Table

S. No.	Tariff Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as % of CIF
1	2	3	4	5	6	7
1	7003, 7005, 7007, 7016, 17020 and 8541*	Textured Toughened (Tempered) Coated and Uncoated Glass**	Malaysia	Malaysia	Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.	9.71%
2	-do-	-do-	Malaysia	Malaysia	SBH Kibing Solar New Materials (M) SDN. BHD	9.71%
3	-do-	-do-	Malaysia	All country including Malaysia	Any Producer other than producer mentioned in S. No. 1 & 2	10.14%
4	-do-	-do-	Any Country other than Malaysia	Malaysia	Any	10.14%

** The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows: 'I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in Malaysia. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.' If no such invoice is presented, the duty applicable to all other companies shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations."*

*** The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.*

****Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated. The product is also known by various other names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass and heat strengthened glass.*

266. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 88, 9 and 9A of the said Act

M. FURTHER PROCEDURE

267. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.09 12:09:18 +05'30'